Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १६६० का १७वां दिवस [संख्या ११

बुधवार, ७ सितम्बर, १६६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पंचायत, सिंचाई, स्वायत्त शासन, सामुदायिक विकास, कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं वन-विभाग]

आयुर्वेद सलाहकार मण्डल

३७७. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद के लिये परामर्श बोर्ड बनाया है ? यदि हां, तो कब से ?

(ख) क्या इस बोर्ड का सचिव डाइरेक्टर आयुर्वेद होता है ?

(ग) क्या इस बोर्ड में सहायक सचिव या अन्य कोई और पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जिसे वेतन या भत्ता दिया जाता हो ? यदि हां, तो किस पद पर और कब से ?

(घ) उक्त पदाधिकारी की नियुक्ति की क्या आवश्यकता थी ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां। दिनांक २१-७-५५ से।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, सरकार ने इस बोर्ड के लिये संयुक्त सचिव की नियुक्ति १० अगस्त १६५६ से की है जिन्हें २००) रु० पारिश्रमिक दिया जाता है।

(घ) संचालक आयुर्वेद को विभागीय अन्य कार्य के साथ योजना के लक्ष्य को यथा समय पूरा करने में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण जनतान्त्रिक परामर्श जो समय समय पर सम्बन्धित बोर्ड द्वारा दिया जाता है उसको यथा समय सरकार के सामने

(श्री भीखाभाई)

तथा अन्य स्थानों पर प्रस्तुत कर उचित निर्णय लेने हेतु पूरे समय पृथक सहसचिव की ही आवश्यकता रहती है अतः संयुक्त सचिव पद सरकार ने स्वीकृत किया ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या ये सज्जन पहले बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये गये थे ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

डॉ० बहादुरसिंह : जब ये सदस्य नियुक्त किये गये थे और सलाहकार बोर्ड में थे तो जोइन्ट डाइरेक्टर या असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को इस पद पर क्यों नहीं उपयुक्त समझा गया ?

श्री भीखाभाई : जो उपयोगी आदमी सिद्ध हुआ उसको रख लिया गया ।

डॉ० बहादुरसिंह : तो क्या बोर्ड के अन्दर दूसरे सारे मेम्बर्स अनुपयोगी थे ?

श्री भीखाभाई : दूसरे और किसी की दर्ख्वास्त नहीं आई थी ।

डॉ० बहादुरसिंह : मेम्बरों को दर्ख्वास्त देने का सवाल नहीं है । बोर्ड में ऑनरेरी मेम्बर्स बनाये । बोर्ड में ऐसा विशेष काम नहीं है । बोर्ड में जोइन्ट डाइरेक्टर, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, तीन चार डाइरेक्टर्स रहते हैं, इनको क्यों नहीं नियुक्त किया ?

श्री भीखाभाई : जो आदमी जिस काम के लिए उपयुक्त होता है उसको रखा जाता है । जोइन्ट डाइरेक्टर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पास और भी काम रहता है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह समझा जाये कि कुछ सरकार के महरबान हैं और उन पर महरबानी बरतने के लिए सरकार ने यह पद दिया ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ३७८

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम ।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा बजट में स्वीकृत रकम से अधिक की दवाइयों की खरीद

३७६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ दवाइयों की खरीद बजट में स्वीकृत रकम से अधिक रुपये की करने के अभ्यस्त हैं ?

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों करते हैं ? सन् १६५८ व १६५६ में उक्त अधिकारी ने दवा खरीदने के लिए कितने रुपये की अधिक स्वीकृति की मांग की ?

(ग) कितनी अधिक स्वीकृति प्रदान

Page No.3

(श्री किशनाराम)

की गई और कितने रुपये की बकाया है ?

(घ) कारण सहित उन महत्वपूर्ण दवाइयों की सूची प्रदान की जाये जिनकी आवश्यक खरीद के लिए पूर्व स्वीकृति नहीं ली जा सकी। खरीद के समय उक्त दवाइयों का स्टॉक बैलेन्स क्या था ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं। अभ्यस्त नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सन् १६५८-५६ में उक्त अधिकारी ने केवल १५,०००) रु० की अधिक मांग की थी।

(ग) ३,०००) रु० की स्वीकृति प्रदान की गई तथा १२,०००) रु० की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(घ) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले के लिए सभी प्रकार की दवाइयां खरीद सकता है और उसको इसके लिए पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

वन विभाग, जिला कार्यालय, जयपुर के भूतपूर्व अकाउन्टेन्ट का ग्रास फार्म बिल्डिंग खातीपुरा में निवास

३८०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) वन विभाग, जिला कार्यालय, जयपुर के भूतपूर्व अकाउन्टेन्ट ग्रास फार्म बिल्डिंग खातीपुरा में कब से किस आज्ञा से रहते हैं, उक्त आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे। यदि वे बिना आज्ञा रहते हैं, तो क्यों ?

(ख) इनके अतिरिक्त उक्त ग्रास फार्म के सरकारी भवन में कौन कौन कब कब से किस किस आज्ञा द्वारा रहते हैं और उनसे उक्त निवास का प्रतिमास कितना कितना किराया वसूल किया गया ? पानी के चार्जेज़ का पेमेन्ट किसने किया ?

(ग) क्या यह सच है कि उक्त भवन जिला वन अधिकारी के अधीन है और जिले से स्थानान्तर हो जाने के बावजूद भी वे उसमें अवैधानिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं ?

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त अकाउन्टेन्ट ने स्वयम् का कोई बंगला बना लिया है और उसमें हाउस बिल्डिंग एडवान्स का कर्जा भी सरकार से प्राप्त किया है तथा उस बंगले को किराये पर चलाता है ?

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जून १६५४ से जुलाई १६६० तक रहे हैं। भूतपूर्व चीफ कन्ज़रवेटर की मौखिक आज्ञा से।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी

Page No.4

श्री सम्पतराम)

गई है। कोई किराया नहीं लिया जाता क्योंकि वहां के सरकारी मकान, औजार व अन्य सामान की चौकीदारी के लिये रहते हैं। पानी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता क्योंकि नर्सरी के नल से पानी लेते हैं।

(ग) उक्त भवन डिविज़नल फोरेस्ट ऑफिसर जयपुर के आधीन है। श्री सावंतमल का स्थानान्तर जयपुर के बाहर नहीं हुआ है। अवैधानिक लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मकान बना लिया है और कर्जा भी प्राप्त किया है किन्तु किराये पर नहीं दिया। अब वे पूरा बनने पर स्वयं रहते हैं।

(ङ) किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ द्वारा छापर की फर्म जे० एन्ड ब्रदर्स को ड्रग्स एक्ट के तहत दिये गये लाइसेन्स

३८१. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ ने छापर की फर्म जे० एन्ड ब्रदर्स को ड्रग्स एक्ट के तहत दो लाइसेन्स दिये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फर्म को इन्कम टैक्स से बचाने के लिए ऐसा किया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो उक्त फर्म जे. एन्ड ब्रदर्स तथा मूंधड़ा ब्रदर्स (छापर) के लाइसेन्स के लिए प्रार्थी तथा प्रोप्राइटर्स की मय वल्दियत के तथा लाइसेन्स देने की तारीख की सूची प्रदान करें।

(घ) क्या इस सम्बन्ध में ड्रग्स इन्सपेक्टर की कोई रिपोर्ट है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट है ?

(ङ) यदि नहीं, तो ड्रग्स इन्सपेक्टर ने कितनी बार छापर का दौरा किया तथा उस दौरे में उक्त फर्म्स का निरीक्षण किया या नहीं ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। लेकिन कानूनन ये दोनों लाइसेन्स लेने थे।

(ग) फर्म जे. एन्ड ब्रदर्स तथा मूंधड़ा ब्रदर्स छापर के प्रार्थी के तथा प्रोप्राइटर्स मय वल्दियत के तथा लाइसेन्स देने की तारीख की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) जी हां, ड्रग्स इन्स्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसने उक्त फर्म का निरीक्षण किया जिसमें उक्त एक्ट के अनुसार कुछ कमियां पायी गईं जिनके बारे में उसे लिख दिया गया है कि उक्त कमियों को शीघ्र पूरा किया जावे।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या कमियां पाई गईं ? किस बात की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जाब्ते की बात थी और कोई खास बात नहीं थी।

श्री किशनाराम : प्रश्न (ख) में 'जी नहीं' बताया। इन्कम टैक्स की बात नहीं, शामलाती खानदान है और शामलाती व्यापार करता है। बेचने के लिए दो लाइसेन्स लिये हैं। इसकी जांच कराये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्ट के अनुसार दो लाइसेन्स लेने जरूरी हैं। एक इ. एन्ड इ. के बारे में और दूसरा शिड्यूल के बारे में। दो लाइसेन्स, एक्ट के अनुसार, लेने जरूरी हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : दो लाइसेन्स दिये गये तो क्या वे लाइसेन्स एक ही फर्म के हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, एक ही के हैं। दो लाइसेन्स लेने जरूरी हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सवाल यह है कि एक फर्म को दो लाइसेन्स अलग अलग दिये। एक मूंदड़ा ब्रदर्स को और दूसरा जे. एन्ड. ब्रदर्स को। दोनों को दिये तो अलग अलग हैं या एक ही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जे. एन्ड ब्रदर्स को दिया था। उस फर्म का नाम बदल गया इसलिए एक ही फर्म को दिया। फर्म तो एक ही है, केवल नाम चेन्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ग्राम पंचायत जोगीवाला, तहसील भादरा के भूतपूर्व सरपंच, श्री रामजीलाल द्वारा आबादी भूमि के अवैध विक्रय विलेख जारी किया जाना

३८२. **श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम पंचायत जोगी वाला, तहसील भादरा, जिला गंगानगर के भूतपूर्व सरपंच श्री रामजीलाल ने अपने कार्यकाल में कुल कितने विक्रय विलेख आबादी भूमि विक्रय के जारी किये हैं और इस मद में कितनी रकम जमा हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने कोई आज्ञा जारी कर आबादी क्षेत्र की भूमि विक्रय सम्बन्धी अधिकार ग्राम पंचायतों से वापिस ले लिये थे ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) उक्त सरकारी आज्ञा जारी होने के पश्चात् कितने पट्टे उक्त ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री रामजीलाल ने जारी किये हैं ?

(घ) उक्त सरपंच की इस अवैधानिक कार्यवाही के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) भूतपूर्व सरपंच श्री रामजीलाल ने पंचायत का चार्ज नव निर्वाचित सरपंच को नहीं दिया जिससे आबादी भूमि के विक्रय विलेख जारी किए और कितनी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

रकम जमा हुई, जानकारी नहीं दी जा सकती।

(ख) राज्य सरकार ने केवल भाखरा प्रोजेक्ट एरिया की पंचायतों के भूमि विक्रय के अधिकार पुनः लिए हैं। प्रतिलिपि आदेश सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) भूतपूर्व सरपंच द्वारा रेकॉर्ड चार्ज में नहीं मिलने से जानकारी नहीं हो सकी।

(घ) (१) मामला पुलिस में दिये जाने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जा रही है।

(२) चार्ज नहीं देने के सम्बन्ध में मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भादरा की अदालत में १७५ आई० पी० सी० के अन्तर्गत चल रहा है।

(३) कलेक्टर को जांच के लिए लिखा है कि वे रिपोर्ट भेजें ताकि राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा १७ (४) (बी) के अन्तर्गत फाइन्डिंग दी जा सके।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नये सरपंच का निर्वाचन कब हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ८–६–५६ को।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह समझा जाय कि ८.७.५६ से लेकर अब तक उस सरपंच ने जिसको चार्ज देना चाहिये था उसको चार्ज नहीं दिया और अनधिकृत रूप से कार्य करता रहा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चार्ज नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : चार्ज नहीं दिया, यह तो कहा गया और क्या यह समझा जाय कि वह अनधिकृत रूप से कार्य करता रहा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : काम नहीं किया। सरपंच दूसरा हो गया। पुराने सरपंच ने कागजात नहीं सम्हलाये।

श्री भैरोंसिंह : काम नहीं किया तो फिर उसने पट्टे किस प्रकार से लोगों को इश्यू कर दिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रेकॉर्ड नहीं है इसलिए जानकारी नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : सरकार को यह जानकारी कब मिली कि उस पंचायत का रेकॉर्ड अवेलेबल नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वर्तमान सरपंच श्री काशीराम ने ८–६–५६ को आवेदन प्रस्तुत किया कि उनको रामजीलाल ने चार्ज नहीं सम्हलाया।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार को कब जानकारी मिली कि भूतपूर्व सरपंच ने कागजात गायब कर दिये और कागजात नहीं मिल रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही बराबर चल रही है। ऑडिट द्वारा कार्यवाही हुई और कलेक्टर को जांच के लिए बार बार लिखा गया। तारीख आप चाहें तो पढ़ दूं।

Page No.7

श्री भैरोंसिंह : सरकार को कब जानकारी हुई, यह मेरा प्रश्न है। गवर्नमेंट ने कब कार्यवाही शुरू की ?

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी नहीं है मंत्री महोदय के पास।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह जानकारी दी जा सकती है कि यह जानकारी सरकार को मिल गई कि उक्त सरपंच ने चार्ज नहीं दिया और कागजात गायब कर लिये। सरकार ने उससे कागजात वापिस लेने की क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अप्रेल ६० में कलेक्टर को लिखा गया। भ्रष्टाचार विभाग को लिखा गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): लिखने के बाद अब तक कलेक्टर ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने पहले ही बताया था कि मामला पुलिस में दिया, एक कार्यवाही। दूसरी, दफा १७५ आई० पी० सी० में मजिस्ट्रेट भादरा की अदालत में कार्यवाही चल रही है। तीसरी, कलेक्टर को लिखा गया कि पंचायत अधिनियम की धारा १७ (४) (बी) के अन्तर्गत फाइन्डिंग दी जा सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस विभाग को मामला इसलिए दिया गया कि उक्त सरपंच ने चार्ज नहीं दिया इसलिए चार्ज दिलवाया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चार्ज नहीं दिया गया इसके लिए तो कार्यवाही कर रहे हैं। चार्ज दिलाने का प्रोवीजन तो अब नये एक्ट में आया है।

श्री भैरोंसिंह : चार्ज न देने के बारे में तो कलेक्टर को लिखा गया है फिर पुलिस विभाग को किस मामले के लिये लिखा गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इनके खिलाफ गबन की भी शिकायत थी। रामजी लाल सरपंच के खिलाफ भोमाराम ने स्पेशल आई० जी० को भ्रष्टाचार के बारे में १७-३-६० को एक प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन भ्रष्टाचार विभाग द्वारा जांच करने पर आरोप प्रमाणित नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : गबन के मामले को लेकर तो आपने पुलिस विभाग को शिकायत की, लेकिन जो कागजात उन्होंने गायब कर दिये उसके लिए आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चार्ज देने के बारे में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भादरा के यहां मामला चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : चार्ज न देने के बारे में आपने कलेक्टर को लिखा, लेकिन पंचायत के कागजात जो गायब कर दिये हैं उसके लिए किसको लिखा गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चार्ज देने का और कागज़ गायब कर देने के सवाल अलग अलग नहीं हैं, दोनों का सम्बन्ध चार्ज न देने से ही है।

Page No.8

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नये चुनाव हो जाने के बाद भी पुराने सरपंच महोदय बहुत सारे जमीन के पट्टे जारी कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कागजात बिना मैं यह कैसे बता सकता हूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, पुराने सरपंच महोदय अब भी पट्टे जारी कर रहे हैं और लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। ऐसी हालत में जिस किसी के पास जमीन का कब्जा देखते हैं वह पुराने सरपंच महोदय के हस्ताक्षरों से जारी किया हुआ है। पुरानी तारीखों में २॥ हजार बीघा जमीन भी उसी भाव और १०० बीघा जमीन भी उसी भाव सवा छः रुपया के हिसाब से, यानि उन्होंने हर माल मिलेगा ढाई आना का हिसाब कर रखा है; जब कि कलेक्टर को लिख दिया, एस०डी०एम० को लिख दिया उस पर भी कुछ नहीं हुआ। दा साहब यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें रहमदिली से काम नहीं चलने वाला है, इसमें तो सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): यह डिपार्टमेंट आपके बस का रोग नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है।

अजमेर जिले के रूपनगढ़ कस्बे व उसके आसपास के गांवों में जल-कष्ट का निवारण

३८३. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अरडा बांध बंधने से रूपनगढ़ कस्बे व उसके आसपास के ग्रामों में कुओं में पानी की इतनी कमी हो गई है कि जिससे वहां पीने को व काश्त को पानी मिलना दुश्वार हो रहा है ?

(२) अगर हां, तो सरकार इन गांवों में पानी के कष्ट को कम करने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

(३) क्या सरकार इन गांवों के कुओं को गहरे करवाने व नये खुदवाने के लिए सबसिडी देने की व दीगर रपट वगैरह बनाने की व्यवस्था कर इस कष्ट को मिटाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) यह प्रश्न इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(३) इस क्षेत्र में कुछ रपटों का निर्माण कार्य पंचायत समिति की ओर से हो रहा है।

सरपंच, ग्राम पंचायत अलीगढ़, तहसील उनियारा द्वारा अलीगढ़ मिडिल स्कूल के निर्माण हेतु पंचायत कोष से प्रदत्त धनराशि

३८४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(क) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ़ तहसील उनियारा ने अलीगढ़ मिडिल स्कूल बनाने के लिए कोई धनराशि पंचायत के कोष से दी है ! अगर हां, तो कितनी और किन आधारों पर ?

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत ने अपने अधिकार से ही यह धनराशि दी है ? क्या उसे पंचायत समिति अथवा परिषद् से ऐसी मोटी रकम देने पर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है ? अगर स्वीकृति लेना अनिवार्य है, तो क्या उक्त पंचायत ने पंचायत समिति आदि की स्वीकृति प्राप्त की है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के लिये समय चाहिये, इसमें पूछी हुई सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चौरासी के फेर में आ गये क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बारिश वगैरह की वजह से प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

सारडा (नोखा) गांव के सरपंच द्वारा गांव के कुएं में नल लगवाने हेतु एकत्रित किये गये द्रव्य का हिसाब-किताब

३८४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सारडा (नोखा) गांव के सरपंच ने गांव के कुएं में नल लगवाने के लिए कुल कितना रुपया गांव वालों से जमा किया ?

(ख) यह रकम कब जमा की गई ? जिस कार्य के लिए जमा की गई उस कार्य में खर्च की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) अब यह रकम कहां है ? इस रकम का कोई व्याज आता है या नहीं ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय):

(क) सरपंच सारडा ने गांव वालों से कोई रकम जमा नहीं की नल योजना के कार्य के लिए गांव वालों ने ११ व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई, इस कमेटी ने ६००० रु० एकत्रित किये जो पंचायत समिति नोखा में जमा कराये।

(ख) दिनांक १०-१२-५६ को ३८०० रुपये व दिनांक ३०-११-५६को २२०० रु० पंचायत समिति नोखा में कमेटी ने जमा कराये जो पंचायत समिति नोखा द्वारा एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ग्राम जलदाय योजना बीकानेर के कार्यालय में दिनांक ११-१२-५६ तथा २८-३-६० को जमा कराये।

एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर रूरल वाटर वर्क्स बीकानेर द्वारा उसी कार्य में खर्च की जा रही है। नल आदि डलवाये जा चुके हैं, इंजिन घर बनाया जा रहा है।

(ग) अवशेष रकम एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर रूरल वाटर वर्क्स बीकानेर के कार्यालय में भेज दी गई है और सरकारी कोष में जमा हो

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चुकी है अतः ब्याज का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह फरमाया कि नल आदि लगा दिये गये, कहां लगा दिये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर रूरल वाटर वर्क्स बीकानेर द्वारा उसी कार्य में खर्च की जा रही है। नल आदि डलवाये जा चुके हैं, एन्जिन घर बनाया जा रहा है और आगामी गर्मियों के पहले यह कार्यवाही पूरी हो जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : महीने भर पहले जाकर आया हूं वहां नल वगैरह कुछ नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : महिने भर में तो बहुत फर्क पड़ सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : नल आदि लग गये हैं, पाइप चला गया है। यह किस प्रकार से हो गया, मैं नहीं समझ पाया कि यह खबर गलत आपके पास कैसे आ जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरूडा में नल आदि डलवाये जा चुके हैं एन्जिन घर बनाया जा रहा है, यह सूचना मेरे पास है।

ओसियां तहसील के ग्राम मथानिया के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के डॉक्टर के विरुद्ध की गई शिकायतों पर कार्यवाही

३८६. **श्री सूरजमल** (फलौदी–मु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) ओसियां तहसील का गांव मथानिया के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के डॉक्टर ७ फरवरी, १९६० से ३० मार्च, १९६० तक हैडक्वार्टर छोड़ कर जोधपुर कितनी बार गये और किस कार्य हेतु ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त डॉक्टर नोन प्रेक्टिसिंग एलाउन्स प्रति माह उठाते हैं और फिर भी प्रेक्टिस कर लोगों से फीस वसूल करते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त डॉक्टर के विरुद्ध जनता द्वारा कई शिकायतें की गईं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में सफाई का कार्य करने के लिए एम्प्लॉयमेंट विभाग से नियुक्ति के लिए एक औरत और एक व्यक्ति जाति हरिजन को भेजा था ? यदि हां, तो उनका क्या नाम था और कहां के रहने वाले थे और उक्त दोनों की नियुक्ति नहीं करने का क्या कारण था ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) मथानिया के डॉक्टर श्री रतनचन्द्र दिनांक ७ फरवरी से ३० मार्च, १९६० तक केवल ६ बार हैड क्वार्टर छोड़ कर जोधपुर गये थे। उनमें से चार बार तो घरेलू कार्यवश, एक बार उच्च पदों के लिये प्रार्थनापत्र देने तथा एक बार होली त्योहार पर जोधपुर गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, कुछ शिकायतें आई थीं

Page No.11

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जिनमें से कुछ पर जांच की गई तथा कुछ पर जांच अभी की जा रही है ।

(घ) जी नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जिला जालोर के हाडेचा ग्राम में बोरिंग कार्य की शुरुआत

३८७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जालौर के हाडेचा ग्राम में बोरिंग करने के लिये कितनी धन-राशि सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है और पब्लिक डोनेशन के कितने रुपये किस किस तारीख को जमा हो चुके हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि हाडेचा में अभी तक बोरिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक सरकार कार्य शुरू कराने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम):

(क) बोरिंग करने के लिये सरकार की ओर से कुल २०,००० रु० की स्वीकृति हो चुकी है । जनता की ओर से ५,००० रु० इस कार्य के लिये ३०-१०-५६ को जमा कराये गये हैं ।

(ख) जी हां; बोरिंग की मशीनें दूसरे कार्यों पर लगी होने के कारण यह कार्य हाथ में नहीं लिया गया । अक्टूबर या नवम्बर माम में बोरिंग काम का शुरू होने की आशा है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : इतने समय तक रकम जमा होने पर भी कार्य नहीं करवाने का कारण क्या है ? क्या यह उचित है ?

श्री सम्पतराम : इसमें उचित-अनुचित का प्रश्न नहीं है टेकनिकल डिपार्टमेंट जो यह कार्य करता है उसको लिखा गया था लेकिन जो मशीन इस कार्य के लिए थी वह अन्य कार्य पर गई हुई थी, इसलिये इस कार्य को जल्दी टेक-अप नहीं कर सके ।

जयपुर विकास खंड के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्र

३८८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर विकास खंड के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्र कब से कहां पर चल रहा है ?

(२) क्या इस स्वास्थ्य केन्द्र से झोटवाड़ा तथा उसके आसपास के क्षेत्र की जनता पर्याप्त लाभ उठा रही है ?

(३) क्या अब कुछ लोगों की ओर से इस स्वास्थ्य केन्द्र को झोटवाड़ा से हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जाने की बात है ? यदि हां, तो किनके द्वारा, क्यों और कहां ले जाने की बात है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जयपुर विकास खंड के अन्तर्गत

Page No.12

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

संचालित स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम सिरसी में दिनांक १५-७-६० से कार्य कर रहा है।

(२) केन्द्र के आसपास की सब ही जनता पर्याप्त लाभ उठा रही है।

(३) जी नहीं ! झोटवाड़ा में पहले ही स्वास्थ्य केन्द्र था।

डॉ० चन्द्रकला : जो केन्द्र झोटवाड़ा में था उसको हटा कर सिरसी क्यों ले जाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति की राय के अनुसार किया गया।

डॉ० चन्द्रकला : जब वहां स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया था तो क्या उसमें पंचायत समिति की राय नहीं थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह केन्द्र २-१०-५६ को बना था जिसे पंचायत समिति की राय लेकर प्रोवीज़नली खोल दिया गया था।

डॉ० चन्द्रकला : जब पंचायत समिति नहीं थी तो उसकी राय नहीं ली गई, लेकिन आखिर जो केन्द्र खोला गया था वह किसी न किसी आधार पर खोला गया होगा। अब उसको हटाने की जरूरत क्यों मालूम हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति जो २-१०-५६ को कायम हुई उसने उस वक्त इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, लेकिन उसके बाद सिरसी में ले जाने का पंचायत समिति में प्रस्ताव हुआ था उसके अनुसार सिरसी में स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया।

डॉ० चन्द्रकला : जब झोटवाड़ा में पंचायत समिति थी तो उसने झोटवाड़ा में स्वास्थ्य केन्द्र रखने को कहा। जब उसका प्रधान बदल गया तो जहां का वह रहने वाला था वहां पर उसे ले जाने की सिफारिश की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति ने झोटवाड़ा के लिये कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। पहले पहल जो प्रस्ताव पास किया गया वह सिरसी में स्वास्थ्य केन्द्र रखने के बारे में किया था।

डॉ० चन्द्रकला : जहां पंचायत समिति के प्रधान बदल जाते हैं वहां क्या उनके बदलने के साथ साथ ये स्वास्थ्य केन्द्र भी जहां वे चाहें ले जा सकते हैं ? इस तरह से प्रधानों के बदल जाने के बाद स्वास्थ्य केन्द्र भी बदले जायं, क्या सरकार इस नीति को ठीक समझती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जैसा कि निवेदन किया पंचायत समिति ने पहली दफा अपने प्रस्ताव द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र सिरसी में रखने का पास किया। इस तरह से प्रधान के साथ यह भी बदलते हैं, यह कहना ठीक नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जिस समय वहां स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया था उस समय भी सरकार ने कुछ सोच-विचार कर ही खोला होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.13

पंचायत समिति के अधीनस्थ प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा की रात्रि पाठशालाएं चलाने का अलाउन्स

३८६. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के अधीनस्थ प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों से प्रौढ़ शिक्षा की रात्रि पाठशालाएं भी चलाई जाती हैं ? यदि हां, तो उनको क्या क्या अलाउन्स मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि समिति के अधीन होने से पूर्व इनको अलाउन्स मिलता था ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या सम्बन्धित अध्यापकों की ओर से अलाउन्स मिलने की प्रार्थनाएं भी सरकार में की गई है ? यदि हां, तो कब कब और उन पर क्या आदेश दिये गये ?

(४) क्या सरकार उनको अलाउन्स देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और वह कब तक दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां। पंचायत समितियों के अध्यापक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने को बाध्य नहीं हैं, स्वेच्छा से यदि चाहें तो चला सकते हैं। उनको ऐसे सामाजिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिये कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता, परन्तु इस काम में रुचि जाग्रत करने के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहन पंचायत समितियों की ओर से दिये जाने का सुझाव दिया गया है :

(क) सबसे अच्छा कार्य करनेवाले को निम्नलिखित पारितोषिक दिये जायें :—

पहला पारितोषिक	३०० रुपये
दूसरा पारितोषिक	२०० रुपये
तीसरा पारितोषिक	१०० रुपये

आठ पारितोषिक हर एक ५० रु० की दर से। इस प्रकार कुल धन-राशि जो पारितोषिक के लिये एक पंचायत समिति द्वारा दी जावे वह १,०००रु० तक हो सकती है।

(ख) दूसरे प्रकार का पारितोषिक यह होगा कि १० दूसरे सर्वोत्तम अध्यापकों को प्रमाण पत्र दिये जावें।

(ग) एक अग्रिम वेतन वृद्धि उन अध्यापकों को दी जावे जिनका काम अति सराहनीय रहा हो, पर यह अग्रिम वेतन वृद्धि दूसरों की वरिष्ठता में असर नहीं डालेगी।

(घ) उन्नत पद देते समय एक अध्यापक के इस संबन्ध में कार्य का खास ध्यान रखा जावे।

(ङ) सिर्फ वे ही मैट्रीकुलेट अध्यापक जिन्होंने पिछले साल (क), (ख) व (ग) के तहत कोई पारितोषिक पाया है आगे की परीक्षा में बैठने की इजाजत हासिल कर सकेंगे परन्तु यह शर्त नोन मैट्रिक अध्यापकों पर लागू नहीं होगी।

(च) जहां अध्यापक इस प्रकार सामाजिक शिक्षा जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल

Page No.14

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

है कार्य करते हों, वहां एक अध्यापक वाली पाठशाला में काम का समय ५॥ घंटे तक, जिसमें आधा घंटा खेल का भी शामिल है, रखा जा सकता है। जहां एक से अधिक अध्यापक हों वहां उस अध्यापक के लिये जो सामाजिक शिक्षा का काम करे उसका एक पीरियड कम किया जा सकता है।

क्योंकि अध्यापक को बाध्य नहीं किया जाता इसलिये ऊपर बताये प्रोत्साहनों के बाद एलाउन्स देना आवश्यक समझा गया।

(२) जी हां। १५ रुपये।

(३) जी हां, उन प्रार्थनाओं पर निर्णय प्रश्न संख्या (१) के उत्तर में दिये अनुसार लिया गया है।

(४) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने प्रोत्साहन देने की यह व्यवस्था की है और इसमें 'स्वेच्छा' शब्द का प्रयोग किया है? मैं कहता हूं यह व्यवस्था स्वयं उनकी स्वेच्छा के ही विरुद्ध है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कैसे विरुद्ध है?

श्री भैरोंसिंह : इस तरह कि इच्छा या अनिच्छा से चूंकि उनको जो मैट्रिकुलेट टीचर हैं और जिन्हें आगे पढ़ना है, आगे पढ़ने की इजाजत प्राप्त करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेना होगा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह उनकी स्वेच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है? किसी की इच्छा है किसी की नहीं, पर आपने सबके लिये बन्धन लगा दिया। अब जिनको आगे पढ़ना है, उनको तो मजबूरन इसमें भाग लेना होगा?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार तो यह प्रोत्साहन देती है।

श्री भैरोंसिंह : जब कि यह थियोरिटीकली कम्पल्शन है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा तो सरकार नहीं मानती। यह कोई कम्पल्शन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या सरकार ने अनिवार्य रूप से इसे रखा है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी नहीं। अनिवार्य नहीं है। ये सुविधाएं दी गई हैं, यह मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिये शर्त दी है? उस शर्त से अध्यापकों पर मानसिक असर नहीं होगा कि स्वेच्छा से नहीं, बल्कि सरकार के आदेश पालन हेतु प्रौढ़ शिक्षा में उनको अनिच्छा से हिस्सा लेना पड़ेगा?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रोत्साहन देने में मानसिक असर का सवाल नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): जो प्रौढ़ शिक्षा में हिस्सा नहीं लेते, क्या आप उनको इजाजत नहीं देंगे?

Page No.15

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नोन मैट्रिक के लिये तो नहीं, मैट्रिक के लिये है सिर्फ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ऐसा समझती है कि जो यह शर्त रखी है उससे अध्यापकों पर इस प्रकार का असर होगा कि जिसके कारण से ज्यादा से ज्यादा अध्यापक प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो फिर अच्छा ही है। इसमें बुराई की क्या बात है ? यह तो शुभ चिन्ह है कि इस कारण से उनको प्रोत्साहन मिला और सामाजिक सेवा का काम करने लगें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अगर उनको इस तरह का प्रोत्साहन न दें तो वे अध्यापक प्रौढ़ शिक्षा में भाग न लेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिना प्रेरणा के कौन काम करेगा, अपना समय देकर ?

श्री भैरोंसिंह : तो इससे साफ जाहिर है कि यह सही प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि बाध्य किया जा रहा है उनको इस डर से कि ऐसा नहीं करोगे तो आगे पढ़ने के लिये स्वीकृति नहीं दी जावेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका यह सोचना सही नहीं है। सरकार ने यह कम्पल्सरी नहीं रखा है, ऑप्शनल क्लॉज़ रखा है।

श्री भैरोंसिंह : पर क्या यह सरकार नहीं मानती कि यह स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति के लिये घातक है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो फायदा, जो प्रोत्साहन दिया जा सकता है उसका जिक्र मात्र है, कि जो यह करेगा तो यह सुविधा उसे मिलेगी और जो नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह : नहीं करेगा तो क्या जो उनका राइट है एजुकेशन विभाग से फर्दर एग्ज़ामिनेशन देने की स्वीकृति लेने का, तो क्या वह स्वीकृति उनको नहीं दी जावेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हक नहीं, उनको इजाजत लेकर बैठना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं उसी इजाजत की बात पूछ रहा हूं। क्या इस बिना पर कि चूंकि वह प्रौढ़ शिक्षा में नहीं जाना चाहता इसलिये उसे इजाजत नहीं दी जावेगी, क्या ऐसा नहीं होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके अलावा और भी प्रोसेस हो सकते हैं। एक प्रोसेस यह है।

श्री भैरोंसिंह : आप और कारण को बात छोड़िये। पर आपने एक कारण ऑब्लिगेटरी बना दिया है। अगर कोई बिना प्रौढ़ शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किये स्वीकृति मांगेगा तो विभाग आउट राइट रिजेक्ट कर देगा कि आपने प्रौढ़ शिक्षा में भाग नहीं लिया इसलिये आपको स्वीकृति नहीं दी जा सकती या यह कह कर आप इन्कार कर सकते हैं कि जितनों को स्वीकृति दी जा सकती थी उनको दे दी गई और वह सारी स्वीकृति प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेनेवालों को दे दी गई, आपको अब नहीं दी जा सकती? क्या यह उनकी स्वेच्छाचारिता की

Page No.16

(श्री भैरोंसिंह)

भावना के प्रतिकूल नहीं पड़ेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी नहीं। यह मैं कह चुका कि यह ऑब्लिगेटरी या कम्पल्सरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री मुरलीधर व्यास : जब आप फर्मा रहे हैं, साधारणतया अनिवार्य रूप से यह आवश्यक नहीं है, तो फिर अभी बीकानेर जिला परिषद् ने इसे अनिवार्य क्यों रखा है वहां के शिक्षकों के लिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह रखा है तो गलत किया है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो कॉन्स्टीट्यूशनल पोज़ीशन खड़ी हो गई। गलत नहीं किया। प्रौढ़ शिक्षा का सैक्टर और प्राथमिक शिक्षा का सैक्टर जिला समिति को दे दिया गया है। अब उन्होंने इसका मतलब समझ कर कि प्रौढ़ शिक्षा उनको देनी ही चाहिये तभी आगे पढ़ने की स्वीकृति दी जा सकती है, वह अब चूंकि उन पर निर्भर करता है, उन्होंने निर्णय लिया तो अब यह निर्णय उनका गलत कैसे हो सकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कानून ने जो उनको अधिकार दिया है वे अधिकार सुरक्षित हैं। अब इसका गलत अर्थ लगा कर कम्पल्सरी किया है तो उन्होंने कानून के विरुद्ध जाकर काम किया है, वह कैसे सही हो सकता है ?

हमने अनिवार्य थोड़े ही किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दा साहब ने वकालत पास कर रखी है।

राजस्थान निर्माण उपरान्त बने नये अस्पताल एवं उनमें लगी धन-राशि

३६०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान बनने के पूर्व बीकानेर व उदयपुर अस्पताल का बजट कितना था और अब कितना है ?

(२) राजस्थान बनने के बाद उदयपुर के अस्पताल के विकास में कितना धन खर्च हुआ तथा बीकानेर व जोधपुर के अस्पताल में कितनी धन राशि अब तक खर्च की गई ?

(३) राजस्थान बनने के बाद किस किस जिले में कहां कहां नये अस्पताल बने व उनमें कितनी धन राशि लगी।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राजस्थान बनने से पूर्व और अब बीकानेर व उदयपुर अस्पतालों का बजट निम्न प्रकार था :-

स्थान	राजस्थान बनने के पूर्व का बजट	अब का बजट
बीकानेर	७,४२,१५२) रु.	६,३७,१७०)रु.
उदयपुर	३,१६,०००) रु.	८,६१,६२६)रु.

(२) राजस्थान बनने के पश्चात् निम्न-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिखित धनराशि निम्न अस्पतालों पर खर्च करने की स्वीकृति दी गई :—

उदयपुर अस्पताल	६.६५ लाख
जोधपुर अस्पताल	३.३८ लाख
बीकानेर अस्पताल	२.०० लाख

(२) राजस्थान बनने के पश्चात् निम्न-लिखित नये अस्पताल बने तथा उन पर निम्न धन-राशि खर्च करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई :—

कोटा अस्पताल	१२.३३ लाख रुपये (महारावल जी का)
जनाना अस्पताल	
उदयपुर	६.५० लाख रुपये
पाली अस्पताल	१.६४ लाख रुपये ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो बीका-नेर में ७ लाख का ९ लाख हुआ और उदय-पुर में ३ से ९ लाख हुआ, तो क्या वहां मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ने से हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां अस्पताल नया बना, इस कारण हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिये तो अलग दिया हुआ है । सवाल तो दवाई और व्यवस्था के सम्बन्ध के खर्च से है ? इतना फर्क किस प्रकार से पड़ गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बैड्स बढ़ गये, इसलिये खर्चा भी ज्यादा हो गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसी प्रकार के बैड्स बढ़ाने की व्यवस्था बीकानेर के लिये नहीं की गई और क्या वहां की मांग नहीं आई ? आई तो, फिर भी क्यों नहीं बढ़ाये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मांग तो सब जगह की है और सबको कुछ न कुछ देते हैं हिसाब से । बीकानेर के भी बढ़े हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : कब बढ़े हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सात लाख थे, अभी नौ लाख हुए हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो दस पर्सेन्ट बढ़ा है, जब कि उदयपुर में ५० पर्सेन्ट बढ़ा दिया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीकानेर में ऑलरेडी बड़ा अस्पताल मौजूद है और इसीलिये तो वहां मैडिकल कालेज खोला गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैडिकल कॉलेज और बड़े-छोटे अस्पताल की बात नहीं करता, दवा के सम्बन्ध के खर्चे की बात कर रहा हूं । दवा तो सबके लिये समान रूप से चाहिये, पर वहां आपने मांग होते हुए भी दवाई की व्यवस्था नहीं की, बैड्स की व्यवस्था नहीं की, और उदयपुर में कर दी, यह क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां ऑलरेडी बैड्स बढ़े हुए हैं और ज्यादा कर दिये हैं हमने बीकानेर में । पहले ही काफी थे और उदयपुर में नहीं थे इसलिये वहां पर करना पड़ा ।

[redacted]

रूपबास तहसील के गांवों में सिंचाई हेतु बांध या नहर न होते हुए भी सिंचाई दरों की वसूली

३६१. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

What are the reasons for rea li- sation of Irrigation rates from the villages of Madapura, Soonoti, Khurasa, Ratana, Rasilpur, Jindpura-Jotrauli, Binana in the Rupbas tehsil of Bharatpur district, when there is no Irrigation Bund for Canal ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : Irrigation rates from the villages mentioned above have been charged as and when innundation facilities have been provided to these villages.

श्री श्रीभानसिंह : But how does the Government provide innundation, irrigation from these villages when there is no Bund and only the water is innundated from pull-over from the river ?

श्री भीखाभाई : Because costs are charged on construction of the storage Bunds.

श्री श्रीभानसिंह : But where does the cost of construction go as regards these villages, when there is no storage Bund of the sort ?

श्री भीखाभाई : As I have just said that this Khanua Bund is situated just above the full water supply of this village and when the water is stored in that Bund and when the abnormal floods of water come, those villages are innundated and for that Irrigation Deptt. has laid down the rates.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister aware that from Khanua Bund, there is no innundation and these villages are situated near the Bund ?

श्री भीखाभाई : I am quite aware of the fact that villages are situated below the full supply of the Khanua Bund and below the regulation.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विलेज एक रेगुलेटर के पास है, नाला बीच में से जाता है और जब पानी भर जाता है तो उससे इन्नडेशन होता है ।

I think the Hon'ble Minister is giving the answer without knowing the facts of these villages.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Is it correct that there was another storage area of the river in that season ?

श्री भीखाभाई : When there is no construction through which the water passes, Irrigation Department charges...

श्री श्रीभानसिंह : Irrigation rates have been charged from these villa-

Page No.19

(श्री श्रीमानसिंह)

ges because of some storage etc. Could you state as to why last year the Government remitted these rates ? Not due to construction or...

श्री भीखाभाई : I am not aware of the fact.

श्री श्रीमानसिंह : Is the Government aware that a telegram was sent to the Collector Bharatpur to go and enquire whether actually irrigation takes place through some river or it is natural and on his report the Irrigation Department exempted the villages from irrigation rates.

श्री भीखाभाई : I have not heard of the exemption.

श्री श्रीमानसिंह : If it is now brought to your notice that actually it was year before last, will the Government or the Minister correct his information and exempt these villages from the levy of the irrigation rates ?

श्री भीखाभाई : I cannot say off hand but I will enquire into the matter.

श्री श्रीमानसिंह : But when you can reply in the House off-hand and off-mind, you can say anything.

उदयपुर जिले के शैडो ब्लॉक्स में आयोजित कृषि प्रशिक्षण शिविरों पर हुआ खर्चा

३६२. श्री लक्ष्मण डीरात (गोगुन्दा) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

उदयपुर जिले के फलासिया, खैरवाड़ा, सराड़ा एवं सलूम्बर शैडो ब्लॉक्स में सन् १९५९-६० में कृषि प्रशिक्षण शिविर किन किन तारीखों में किये गये और उन शिविरों पर कितनी रकम खर्च हुई ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सन् १९५९-६० में छाया खण्डों में कृषि मुखिया प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मत्स्य-क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु कांच की वस्तुओं की खरीद में गबन

३६३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :-

1. Is it a fact that the F. D. O. sanctioned a sum of Rs. 2000/- for the purchase of Glasswares for Fisheries Research Laboratory, Udaipur ? If so, was he competent to sanction it ?

2. Is it a fact that the Audit

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

party reported misappropriation of the Government money in this particular purchase of Glasswares ? If so, who were involved in it and what action has been taken against such persons ?

3. Is it also a fact that Mr. N. L. Mathur, who was involved in the above case, was also charged by the audit party for charging double T. A. for single journey ? If so, what action has been taken against him ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं; खण्डीय उप संचालक ने डिटेक्ट किया, इसकी पूछताछ जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पूछताछ कौन कर रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिप्टी डाइरेक्टर शीप एण्ड वूल।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही के मर्दाने अस्पताल में चौदह चारपाई वाले जनरल वार्ड का निर्माण

३६४. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Health be pleased to answer :—

(1) Whether the Government had plans to construct a fourteen bedded general ward in the male hospital, Sirohi before the end of the current financial year ?

(2) If so, what has been the progress in this direction so far ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) Yes, there is a proposal for construction of a 14 bedded ward at Sirohi Hospital.

(2) The proposal is under consideration.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

रूपवास तथा बयाना तहसीलों में सिंचाई के बांधों की मरम्मत

३६५. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :-

1. How many Irrigation Bunds have been repaired or will be repaired during this year in the tehsils of Rupbas and Bayana and whether the following are included or not :-

Binana, Jatmali, Toranli, Norola in Rupbas tehsil and Jaisara in Bayana tehsil of Bharatpur district ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : मामूली मरम्मत हर साल की जाती है। इस वर्ष १२ बन्धों की भारी मरम्मत की गई, उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.21

(श्री दौलतराम सारण)

इस वर्ष तहसील रूपवास के नरूला बांध व तहसील बयाना के जैसोरा बांध की मरम्मत की गई। सन् १९५८ व १९५९ में जतवंस व बीनावा बांध की मरम्मत की गई। जातरोली बांध के मरम्मत का तकमीना की जांच-पड़ताल जारी है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व बाडमेर आदि शहरों में मई व जून के महीनों में होने वाले जल-कष्ट का निवारण

३९६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) ; क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में बड़े बड़े शहरों; जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर इत्यादि में मई और जून में नलों में पानी की अत्यधिक कमी के कारण जनता को अधिक कष्ट और संकट रहता है ?

(ख) अगर हां, तो गत जून में कौन कौन से शहरों में जल-संकट अधिक गंभीर रहा और उसके निवारणार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(ग) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में मई व जून में जल की कमी के कारण कई स्थानों पर लड़ाई झगड़े हुये जिसमें एक पुलिसमैन घायल हुआ और बुढ़िया की जल न मिलने के कारण मृत्यु हो गयी ?

(घ) अगर हां, तो सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : This has been transferred to the P. W. D. Minister for reply.

रावराजा श्री सरदारसिंह : Why this has been transferred to the P. W. D. Minister. ? यह तो जल का है, स्वास्थ्य का है।

श्री सम्पतराम : वे जवाब दे देंगे। अगर आप मुझसे ही जवाब चाहेंगे तो अगले टर्न पर मैं दे दूंगा

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा अस्पताल और टी० बी० अस्पताल में बगैर टेन्डर आमन्त्रित किये कपड़े की खरीद एवं धुलाई

३९७. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा अस्पताल में डॉक्टरों, कम्पाउन्डरों व वार्ड बोएज़ आदि को सरकार की तरफ से वर्दी दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार कपड़े

Page No.22

(श्री मोगजी भाई)

की खरीद व सिलाई आदि के लिए टेन्डर आमंत्रित करती है ?

(३) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा अस्पताल और टी० बी० अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के कपड़े आदि बिना टेन्डर आमन्त्रित किये ही धुलवाये जाते हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर और क्यों ?

(४) बांसवाड़ा अस्पताल और टी० बी. अस्पताल में मरीजों को सरकारी डाइट(भोजन) बनाने की व्यवस्था एक ही प्रकार की दी जाती है या अलग अलग ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । यदि खादी खरीदते हैं तो टेन्डर नहीं लिये जाते ।

(३) जी नहीं । जो धोबी बांसवाड़ा अस्पताल के कपड़े धोता है वही टी० बी० क्लीनिक के मरीजों के कपड़े धोता है ।

(४) मरीजों को एक ही प्रकार का भोजन दिया जाता है । केवल जो मांसाहारी होते हैं उनको रोजाना १ अंडा व २ छटांक मांस बजाय दाल व सब्जी के, व शाकाहारी को २ औंस मक्खन दिया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि जो धोबी अस्पताल और टी० बी० क्लीनिक के मरीजों के कपड़े धोता है वह सरकारी नौकर है या किसी और धोबी से प्राइवेटली धुलवाये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो गवर्नमेंट का धोबी रखते हैं अस्पतालों में ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : खादी के लिए टेन्डर क्यों नहीं मांगे जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खादी के लिए ऐसा है कि उसकी रेट्स फिक्स्ड हैं, इसलिए अच्छी स्टाल देखकर जहां अच्छा कपड़ा होता है वहां से ही ले लेते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): जिन कपड़ों की रेट्स फिक्स्ड होती हैं उन कपड़ों के खरीदने के लिए टेन्डर नहीं इन्वाइट किये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खादी के लिए स्पेश्यली ऐसा है ।

श्री मोगजी भाई : यह जो कपड़े खादी के खरीदे जाते हैं तो क्या चतुर्थ श्रेणी और वार्ड बोएज़ के लिए ही खरीदे जाते हैं या वे दूसरे कामों में आते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बैड शीट्स खरीदे जाते हैं, और भी बहुत से कामों के लिए खादी का कपड़ा खरीदा जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

ग्राम विकास निधि का निर्माण

३६८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : Will the Panchayat Minister be pleased to state:—

(श्री भीमसेन)

1. Is the Government aware that certain States of India, particularly Assam have set up a Rural Development fund to cater to the Development-needs of Panchayats ?

2. If yes, is the Government of Rajasthan also contemplating to create such a fund in the State ? If so, when and if not, why not ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): The State Government is aware that a rugal Development fund has been set up in Assam.

2. The State Government does not contempla te the creation of such a fund in the State since it is not considered appropriate at this stage.

श्री भीमसेन : पंचायतों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आप प्रावधान रखते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंचायत फण्ड कायम किया है जिसमें सब पैसा देते हैं। सेन्टर से आता है, स्टेट से देते हैं और कुछ कन्ट्रीब्यूशन से आता है । इस सबको मिलाकर एक फण्ड एकठ्ठा हो जाता है, उससे बहुत कुछ पूर्ति हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

जिला जालोर के कृषि अधिकारी के कार्यालय में मोटर किराये के पड़े हुए पेन्डिंग बिल्स का भुगतान

१६६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला जालोर के कृषि अधिकारी के कार्यालय में सन् १९५७ से आज तक कितने व्यक्तियों के मोटर किराया के बिल्स पेन्डिंग हैं और उनको पेमेन्ट न करने का क्या कारण है ?

उप मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): सिर्फ एक व्यक्ति चन्द्रसिंह ड्राइवर का २१६ रु० २ आने ६ पाई का बिल पेन्डिंग है। यह व्यक्ति रकम का भुगतान लेने नहीं आया, इसलिए अब तक इसका पेमेन्ट नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मीचन्द : श्री अब्दुल सत्तार का पेन्डिंग है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : केवल एक व्यक्ति का है जिसका नाम मैंने बता दिया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरे पूछने का मतलब यह है कि अब्दुल सत्तार का पेन्डिंग है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन कर दिया कि एक व्यक्ति जिसका नाम चन्द्रसिंह है उसका पेन्डिंग है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि अब्दुल सत्तार का पेमेन्ट नहीं हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या आप जानकारी करने की कोशिश करेंगे ? उसने माल ट्रक से ढोया और सन् ५८ से अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है ।

श्री दौलतराम सारण : किस सम्बन्ध का है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का खाद व बीज पहुँचाया गया था ।

श्री दौलतराम सारण : मैं जानकारी कर लूंगा ।

प्रश्न संख्या ४००

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

यज्ञनारायण अस्पताल किशनगढ के कर्मचारियों का फिक्सेशन

४०१. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा [किशनगढ़—डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]:—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में जितने कर्मचारी कम्पाउन्डर वगैरह हैं इन सबका फिक्सेशन हो गया है ?

(२) अगर नहीं, तो किस किस का फिक्सेशन नहीं हुआ और इसका क्या कारण है व अब कब तक इन लोगों का फिक्सेशन हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं ।

(२) जिन व्यक्तियों के फिक्सेशन नहीं हुए हैं उनके नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इनमें से २ कर्मचारियों के फिक्सेशन मेडिकल डाइरेक्टोरेट के विचाराधीन हैं तथा शेष कर्मचारियों के केस जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जयपुर दौसा के विचाराधीन हैं । इनके शीघ्र निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या ४०१ की सूची प्राप्त नहीं हुई है ?

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो सदन की मेज पर रखी हुई है ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने देखा है, नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने वेरीफाई कर लिया है, रखी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

पशुपालन विभाग द्वारा खरीदे गये औजार एवं सामग्री

४०२. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १९५९–६० में पशुपालन विभाग द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों में कितनी

Page No.25

(श्री भैरोंसिंह)

कितनी कीमत के instruments and applinaces खरीदे गए :—

1. E. Hospital & Dispensaries.
2. P. Key Village Schemes.
3. Camel Scheme.
4. Disease Investigation.
5. Fisheries.
6. Sheep & Wool Section.
7. Normalised Blocks.
8. Cerologist.

पशुपालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): पशुपालन विभाग में सन् १९५९–६० में इन्स्ट्रूमेन्ट्स और एप्लाइन्सेज़ खरीदे गये थे उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

१. २१,६३४.४७ न. पै.
२. ६,४८५.५६ न. पै.
३. ६,८७२.१८ न. पै.
४. ५४६.८३ न. पै.
५. २,६४१.४७ न. पै.
६. ४,३६८.३४ न. पै.
७. सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह काम पंचायत समितियों को दे दिया गया है।
८. ६५१.७० न. पै.

प्रश्न संख्या ४०३

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

बड़ोदिया भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर

४०४. डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जयपुर शहर में बड़ोदिया भवन निर्माण सहकारी समिति नाम की कोई संस्था है ? यदि हां, तो यह संस्था कब बनी और इसके कुल कितने सदस्य हैं ?

(ख) क्या इस समिति को भवन निर्माण हेतु भूमि मिल चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कहां पर और किस योजना के अन्तर्गत ?

(ग) क्या यह सच है कि बड़ोदिया की भूमि पर अनधिकार कब्जा जताने के लिए कुछ लोगों ने उक्त समिति बनाने का कुचक्र रचा है ?

(घ) क्या भवन निर्माण सहकारी समितियों के निर्माण के लिए उसके पास भूमि का होना जरूरी है ? यदि हां, तो फिर इस सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन किस आधार पर हुआ ?

(ङ) क्या सरकार इस समिति को गैर कानूनी घोषित कर इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। यह संस्था दिनांक २०-७-५९ को रजिस्टर्ड हुई। इसकी सदस्य संख्या ४०

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है जिनके नामों की सूचो परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । परन्तु इस समिति का रजिस्ट्रेशन भूमि मिलने से पूर्व इस कारण हुआ है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने लिखित में यह आश्वासन दिया है कि यदि रजिस्ट्रेशन पहले हो जावेगा तो इसको भूमि में प्राथमिकता दी जावेगी ।

(ङ) जी हां । यदि इसको भूमि नहीं मिली तो इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जावेगा । अभी अनुचित कार्यवाही का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि समिति में ऐसे सदस्य भी हैं जो बड़ोदिया के रहनेवाले नहीं हैं और केवल जमीन लेने के उद्देश्य से ही सदस्य बन गए हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से सूची में जो लिखा है बड़ोदिया के ही लिखे हुए हैं । कौन से नहीं हैं, वह आप बता दो ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह बात सही है कि कुछ लोगों ने दूसरी सहकारी समिति बनाने की योजना बनाई है और जो अन्डर रजिस्ट्रेशन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से एक पर्पज़ के लिए एक ही समिति बनती है दूसरी नहीं बन सकती ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : क्या वह दूसरी सोसाइटी नहीं बनेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या पहली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होकर दूसरी रजिस्टर्ड नहीं हो पायेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि उस समिति के सदस्यों की संख्या ४० है, यह सदस्य संख्या जब समिति बनी थी उस समय की है या अब की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस समय बनी थी उस समय भी इतनी थी और अब भी इतनी ही है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या समिति के सदस्यों की संख्या सौ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मेरे पास आज सवेरे की सूचना है कि बड़ोदिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी सदस्य संख्या सौ है और वहां दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की योजना बनाई जा रही है और दबाव डाला जा रहा है कि पहली सोसाइटी को कैंसिल करके दूसरी बना दी जाय । इस प्रकार का कुठाराघात चल रहा

(श्री लादूराम सुलाणिया)

है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो पुरानी स्कीम है उसे ही रखा जाय और दूसरी सोसाइटी नहीं बनाई जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई कुठाराघात नहीं हो रहा है। अभी भी सदस्य संख्या चालीस ही है और दूसरे कोई मेम्बर बनना चाहते हैं तो उनको भी एनरोल किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक पर्पज़ के लिए एक ही सहकारी समिति बनेगी, दूसरी कोई नहीं बनेगी। जो लोग रह गए हैं और खुशी से मेम्बर बनना चाहते हैं तो हम उनको एनरोल कर लेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : जो दूसरी सहकारी समिति बनने जा रही है उसको अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने लिखित में यह दे दिया है कि तुमको भी जमीन दे दी जायगी और वह लिखित में सहकारी विभाग के दफ्तर में भी पहुँच गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरों ने लिख कर दे दिया अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को कि हमको भी जमीन दे दो, तो जमीन तो सबको मिलनी चाहिये। लेकिन एक काम के लिए एक ही सोसाइटी बनेगी, दो बनने का सवाल नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यहां एक ही क्षेत्र में एक ही सोसाइटी का प्रश्न नहीं है, बल्कि दूसरी सोसायटी बन रही है और उसको इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने यह लिख कर दे दिया है कि जमीन दे दी जायेगी और वह सहकारी विभाग में पहुँच गया है। दूसरी सोसाइटी रजिस्टर्ड होने वाली है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने ऐसा क्यों किया और सहकारी विभाग के पास क्या वे कागजात पहुँच गए हैं, मैं यह जानना चाहती हूँ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सहकारी विभाग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। अगर सोसायटी में एडीशनल मेम्बर बढ़ा दिए गए तो जमीन दे दी जावेगी। लेकिन एक पर्पज़ के लिए एक ही सोसायटी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

गोशाला व्यवस्था, सिरोही द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

४०५. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Forest Minister be pleased to state:—

(i) Is it correct that the "Arbud Gaushala" Sirohi has a forest given to it by the Government for using it as grazing grounds and for collecting fodder ?

(ii) Is it correct that the management of the Gaushala has leased out the forest, without State Government sanction and also without proper publicity to a contrractor for felling trees ? Is it also correct that only 15 years back trees were felled and normally no trees should be removed from this forest till about 40 years from the previous date of cutting the trees ?

(श्री पी. के. चौधरी)

(iii) Is it correct that this forest area comprising 1,400 acres has been leased out at Rs. 10,000 whereas the valuation of the forest is the tune of Rs. 5,00,000 ?

(iv) Has the State Government taken any action against the manag-ement for their irregular action ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : 1. Yes.

2. Yes.

3. The total area of the Jor according to the records of the Forest Department, is 71,335 acres. No valuation has been made of the standing crop but judging from the nature and age of the crop and the average price obtained, for the firewood lots in Sirohi Division the valuation would not be more than Rs. 60,000 to 70, 000 /—

4. The contract given by the management has been cancelled by the State Government and the removal of the felled produce has been stopped The matter is further still under examination of Government.

प्रश्न संख्या ४०६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरीपूनिया ।

(अनुपस्थित)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में टेलीफोन्स की वृद्धि

४०७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कुल कितने टेलीफोन और उनके कितने एक्सटेन्शन हैं ?

(ख) अस्पताल में कितनी मंजिलें व विभाग हैं ? क्या यह सच है कि सबके लिये केवल एक टेलीफोन वहां की इन्क्वायरी में है ?

(ग) क्या एक ही टेलीफोन होने के कारण कभी कभी घंटों वहां का टेलीफोन नहीं मिलता जिससे अस्पताल के मरीजों, डॉक्टरों व बाहर की जनता को अत्यधिक परेशानी होती है ?

(घ) अस्पताल जैसी जगह में टेलीफोन की अनिवार्यता महसूस कर क्या सरकार वहां कुछ टेलीफोन और लगवाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) सवाई मानसिंह अस्पताल में केवल दो टेलीफोन हैं और उसके दो एक्सटेन्शन्स हैं ।

(ख) अस्पताल में ग्राउन्ड फ्लोर के अलावा दो मंजिलें हैं, आउट डोर के अलावा १८ वार्ड हैं । जी हां, यह सच है कि इन सब के लिए एक ही टेलीफोन है जो पूछताछ दफ्तर में है ।

(ग) यह सही नहीं कि घंटों टेलीफोन नहीं मिलता । मगर एक ही टेलीफोन होने के कारण कुछ समय अवश्य हो जाता है ।

(घ) जी हां ।

Page No.29

डॉ० चन्द्रकला : हां, तो क्या दूसरा टेलीफोन वहां पर जल्दी ही लगने वाला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक टेलीफोन और लगाने के ऑर्डर्स भी हो गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह दूसरा टेलीफोन कब लगा, आपने बताया कि एक ऑफिस में है और एक कब लगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां पहले से ही दो टेलीफोन हैं। एक ऑफिस में है और एक जनरल फोन इन्क्वायरी में है। एक फोन जो ऑफिस में है वह डॉ० सरीन के पास है जिनका टेलीफोन नं० ३६४७ है और जो इन्क्वायरी पर फोन है उसका नम्बर २२२२ है। दो एक्सटेंशन्स हैं। एक और जनरल टेलीफोन लगाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : क्या यह सही है कि अस्पताल में इन्क्वायरी से एमर्जेन्सी में कोई फोन करते हैं तो २० नये पैसे चार्ज कर लेते हैं डॉक्टरों से भी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड

४०८. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की स्थापना कब हुई, इसके अब कौन कौन सदस्य हैं और उनकी नियुक्ति के क्या आधार हैं ?

(ख) बोर्ड के तहत कुल कितने कर्मचारी हैं ?

(ग) इस बोर्ड के निर्माण से लेकर आज तक कुल कितनी धन राशि बोर्ड द्वारा खर्च की गई, इसमें केन्द्रीय सहायता कितनी और किस रूप में मिली ?

(घ) बोर्ड के पास कितने बोरिंग यूनिट हैं जिनमें डाइमन्ड बोरिंग मशीन कितनी हैं ? ये यूनिट कहां कहां पर काम कर रहे हैं ? काम न आने वाली मशीनें कितनी हैं और किस कारण से पड़ी हैं ?

(ङ) बोर्ड ने कितनी जगह बोरिंग किया और कितनी सफलता और असफलता मिली ?

(च) भविष्य में और कितनी मशीनें मंगवाने की मांग है ?

(छ) क्या यह सही है कि बोर्ड के पास कई काश्तकारों ने बोरिंग करवाने के लिए पेशगी रकम जमा करा रखी है और ऐसी पेशगी की कुल कितनी रकम है ? यह रकम वापस क्यों नहीं कर दी गई, जहां पर मशीनें अब नहीं भेजी जा सकतीं ? क्या रकम की वापसी का निवेदन किसी ने किया ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (क) राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की स्थापना दिसम्बर, १९४९ में भारत सरकार द्वारा की गई और अप्रेल सन् १९५५ में यह

(श्री दौलतराम सारण)

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में ले लिया गया । इसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

१. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, चेयरमैन ।

२. चीफ इन्जीनियर, लोक निर्माण विभाग (भवन व पथ),

३. चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग,

४. चीफ इन्जीनियर, राजस्थान विद्युत विभाग,

५. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान,

६. सचिव, कृषि विभाग

७. उप सचिव, वित्त विभाग,

८. अतिरिक्त उप सचिव, विकास विभाग

६. संचालक, कृषि विभाग राजस्थान, सदस्य सचिव ।

(ख) राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के कुल २०५ कर्मचारी हैं,

(ग) राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में कुल धन राशि ५०,५३,८७३.६८ खर्च की गई उसमें से १७,८६,५५५.७७ कैपिटल एक्सपेन्डीचर फाइनेन्सड बाई सेन्ट्रल असिस्टेंस ऋण के रूप में है ।

(घ) राजस्थान अन्डर ग्रन्उड वाटर बोर्ड के पास कुल सात बोरिंग यूनिट हैं उनमें दो डाइमन्ड बोरिंग मशीनें हैं । अभी ये मशीनें राजाखेड़ा, भरतपुर, अलवर, अजमेर, मेड़ता, भीनमाल और रानी में काम कर रही हैं । अभी सब मशीनें काम में आ रही हैं ।

(ङ) राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने कुल १२१ कुओं पर बोरिंग का काम किया है । बाड़मेर में एक जगह बोरिंग असफल रहा ।

(च) अभी चार मशीनों की और मांग है ।

(छ) बोर्ड के पास बोरिंग कराने के लिए अभी कोई काश्तकार ने पेशगी रकम जमा नहीं करा रखी है इसलिए रकम वापसी करने का प्रश्न नहीं उठता । पेशगी रकम तब ही ली जाती है जब बोरिंग मशीन उक्त जगह काम करने के लिए उपलब्ध हो सके ।

(१२ मध्यान्ह)

श्री अनूपसिंह : यह बोर्ड की जो आपने स्थापना की है उसके क्या नियम हैं ? उसकी मीटिंग्स किस तरह हुआ करती हैं, कहां पर हुआ करती हैं उसके नियम क्या हैं ; वह थोड़ा फरमाने की कोशिश करें ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बोर्ड की मीटिंग्स राजस्थान की कैपिटल, जयपुर में होती हैं । महीने में एकाध दफा बोर्ड मीट करता है और उसके नियम कामकाज करने के वही हैं जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के हैं–वे ही अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के हैं ।

श्री अनूपसिंह : आपने यह फरमाया है कि कोई रकम पेशगी नहीं दी गई है । मैं यह अर्ज कर दूँ कि मुकन्दसर में एक कुआं

Page No.31

(श्री अनूपसिंह)

खोदने का वहां पर रखा गया था कि कुआं यहां पर खोदा जायगा । उन्होंने कहा कि यूनिट भेजेंगे और पेशगी पैसा वहां पर जमा करा दिया गया, लेकिन जमा पैसा आज तक वापिस नहीं लौटाया गया और न वह काम हुआ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं कहता कि जमा नहीं कराया गया । कुओं की रकम का रुपया जमा करवा रखा है । उस समय जब कि वह रकम जमा करवाते हैं हम क्ली-अर कह देते हैं कि जब आपकी बारी आयेगी और जब मशीन खाली होगी तभी काम को कर देंगे । उस समय बहुत से लोग एग्री होकर चले जाते हैं कि जब मशीन खाली हो तो काम पर भेज दें । मानलो कि काम बराबर नहीं किया गया और वापिस मांगते हैं तो वापिस लौटा देते हैं । हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री अनूपसिंह : अभी माननीय उप मंत्रीजी ने जवाब दिया कि कोई काश्तकार की कोई रकम जमा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुकन्दसर के काश्तकारों की रकम जमा है और आज तक कोई युनिट वहां नहीं पहुंचा है, उसका क्या जवाब है ?

श्री दौलतराम सारण : बोरिंग का आपने पूछा था कि बोरिंग का किसका पैसा जमा है तो मैंने निवेदन किया कि बोरिंग के लिए कोई पैसा जमा नहीं है ।

श्री अनूपसिंह : किसलिये जमा किया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा उसके लिए मैंने उत्तर दे दिया ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि पैसा जमा है तो उन्होंने किसके लिए कहा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें दो हैड्स हैं, एक तो बोरिंग के लिए और एक ब्लास्टिंग के लिए । कम्प्रेशर्स वह ब्लास्टिंग का काम करते हैं जो कि चट्टानें तोड़ने का काम करता है । उसके लिए भी बहुत से लोगों को रकम जमा है और बोरिंग के लिए भी हो सकती हैं । इसलिए मुकन्दसर वालों की कोई रकम जमा हो और वह चाहते हैं कि उन्हें वेट नहीं करना है और वापिस रकम मिल जाय तो वापिस मिल जायगी ।

श्री अनूपसिंह : वह रुपया वापिस नहीं चाहते हैं । वे तो मशीन चाहते हैं, लेकिन वह नहीं जा रही है, इसलिए निराश होकर कह रहे हैं कि रुपया वापिस दो ।

श्री नाथूराम मिर्धा : निराश होने की नौबत नहीं आने की है । हम भी चाहते हैं कि काफी मशीनें हों क्योंकि कामकाज बढ़ा है । इसके उपरान्त भी निराश हो रहे हैं और अगर कोई रकम जमा हो तो वापिस ले सकते हैं ।

सी. ए. एस. प्रथम श्रेणी के डॉक्टरों का चयन एवं अस्पतालों का श्रेणी विभाजन

४०६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : Will the Health Minister be pleased to state :-

(श्री मूलचन्द डागा)

(1) What is the method for selecting Doctors as C. A. S. Class I ? Is it done only by P. S. C. ?

(2) When were Hospitals categorised ?

(3) When was selection of Doctors in C. A. S. class I finalised ?

(4) Was the selection of C. A.-S. Class I done first or the Hospitals were categorised first ? Which of the two should have been done first ?

(5) If the Hospitals were first categorised, were proper postings of the Doctors done according to their seniority against the vacancies of C. A. S. Class I ?

(6) Were the Doctors who were given C. A. S. Class I pay and grade from the date earlier than 27-4-54 sanior most of all other Doctors in qualification and service ? Were there any junior Doctor or doctors who were given C. A. S. Class I pay and grade from a date earlier than 27-4-54? When a senior person did not get it, and if so, on what basis ?

(7) When was the Jalore Hospital categorised from C. A. S. Class I Hospital to C. A. S. Class II Hospital and why ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(1) Yes, the selection is done by the Public Service Commission. Recently some promotions were made by the Departmental Promotion Committee. The Chairman of the Committee was one of the Members of the Public Service Commission.

(2) In 1953.

(3) In April and June, 1954.

(4) Hospitals were categorised first and this ought to have been done first.

(5) No changes in the postings were made due to the integration, after the categorisation of Hospitals.

(6) Yes. Doctors who were already working on the posts of C. A. S. I in Class I Hospitals were allowed grade before 27-4-1954 irrespective of their seniority.

(7) In the integration this (Jalore) Hospital was categorised as III grade Hospital and is still III grade Hospital. It was never converted from Class I to Class II Hospital.

प्रश्न संख्या ३७८

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४००

(अनुपस्थित)

Page No.33

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४०३

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०६

श्रीमती गौरी पूनिया ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

अल्पकाल-सूचना प्रश्न सम्बन्धी

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैंने २६ तारीख को एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन दिया था। वह बड़ा महत्वपूर्ण है उसका जबाब दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : उसकी आपको जानकारी दे दी जायगी कि किसी तारीख को लिया जायगा या नहीं लिया जायगा।

(१२.५ म० प०)

स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन-प्रस्ताव हैं; एक तो माननीय श्री भैरोंसिंह, विभाजन संख्या १४ का—राजस्थान केनाल व उसके सम्बन्ध में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में जो संधि हो रही है उन मामलों को लेकर प्रस्तुत किया गया है। उनका विशेष रूप से यह कहना है कि चूंकि राजस्थान सरकार की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत उस केनाल का खर्चा पूर्णतया राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा, इसलिए इस मामले पर यहां पर बहस की जाय। मैं उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि जो सदन में कार्यवाही निर्धारित की गई है उसको रोक कर इस मामले पर वाद-विवाद करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा अब भी जो राजस्थान की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस चल रही है उस सिलसिले में इस मामले पर बहस की जा सकती है।

दूसरा स्थगन-प्रस्ताव है माननीय श्री छोतीलाल का। उन्होंने जैसलमेर में दिनांक २३ अगस्त, १९६० को कुछ डाकुओं द्वारा आत्म समर्पण किये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। राज्य सरकार से इसके विषय में कोई पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर बहस की जाय। माननीय गृह मंत्री अगर चाहें तो आज या किसी और अगली तारीख को अपना बयान दे सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : यह मामला अदालत में जाने वाला है इसलिए....

श्री अध्यक्ष : सिर्फ फेक्चुअल बातें चाहिए कि कितने आदमी हैं, क्या बेकग्राउन्ड है, किस तरह की बात हुई? उसमें इन्डिविजुअल केसेज़ की कोई बात है नहीं।

श्री छोतीलाल (भरतपुर) : फिर किस दिन स्टेटमेंट देंगे ?

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सभापति, कार्य सलाहकार समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति (बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी) का सत्तरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय, भरतपुर में बाढ़ से हानि पर ध्यान दिलाने, सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir, Under Rule 131 I beg to call the attention of the Revenue Minister to the following matter of urgent public importance and I request him to make a statement thereon :—

"Damage caused by floods in Bharatpur District to the human lives, livestock, crops etc. and the relief measures taken by the Departments concerned in respect thereof."

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में बाढ़ की स्थिति पर विचार करने के लिये कुछ तथ्यों को जान लेना आवश्यक होगा । इस जिले में सिंचाई के खास साधन बड़ी तादाद में इनन्डेशन बन्ध हैं, जिनके द्वारा बरसात का पानी इकट्ठा कर बरसात के बाद निकाल दिया जाता है ताकि पेटे में रबी की काश्त कर सके। इस जिले में मुख्य नदियां गम्भीरी बाणगंगा, रूपारेल हैं जिन सभी पर बान्ध बनाये हुए हैं। यह बन्ध इस प्रकार से बनाये गये हैं कि एक बन्ध से दूसरे बन्ध में पानी भरता रहे। सन् १९५८ में जिस समय बाढ़ आई तो यह निश्चय किया गया कि कुछ ऐसा इन्तजाम किया जाय जिससे बाढ़ पर नियन्त्रण किया जा सके और बन्धों में पानी भरने पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि गम्भीर स्थिति पैदा नहीं हो सके।

मैं इस जगह माननीय सदस्य का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भरतपुर में बाढ़ को रोकने के स्थाई प्रबन्ध करने के लिए २४ स्पान का रेग्युलेटर उन्चेन केनाल (उन्चेन रोड) पर बनाया गया है, जिससे अब यह संभव हो गया है कि फालतू पानी अजान बन्ध में लिया जा सके, जब कि इससे पहले यह संभव नहीं था। पहले पानी केवल मोती झील में ही जा सकता था जिसकी केपेसिटी कम थी। अजान बन्ध भरतपुर का सबसे बड़ा बन्ध है और बहुत बड़ी मात्रा में पानी ले सकता है।

इस वर्ष की स्थिति यह रही कि माह जुलाई में थोड़ी ही वर्षा हुई लेकिन माह अगस्त में कई तहसीलों में औसत से अधिक बरसात हुई जिसके कारण सभी नदियों में बाढ़ आ गई, लेकिन बाढ़ की स्थिति से बचने के लिये पहले ही योजना बनाई जा चुकी थी। अगस्त में पहले सप्ताह शुरू होने से पहले मामूली बाढ़ आई तो तमाम बांध खाली थे और फ्लड कमेटी के बनाये हुए प्रोग्राम के अनुसार उनमें पानी लिया गया। इसके पश्चात् दिनांक १५ अगस्त से २३ अगस्त तक निरन्तर वर्षा होती रही जिसके कारण बाण गंगा, और गम्भीरी नदियों में दिनांक १८ की रात में बाढ़ आई और रूपारेल में सबसे अधिक बाढ़ दिनांक २१

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अगस्त को आई। पूर्व योजना के अनुसार निश्चित किया जा चुका था कि समस्त बन्धों में पानी फुल टैन्क लेवल से २ फीट नीचे रखा जाय ताकि कहीं भी बाढ़ से आये हुए अधिक पानी को समाया जा सके। योजना यह थी कि गम्भीरी नदी के अधिकतम बाढ़ को गम्भीरी नदी में ही निकाल दिया जाय और बाणगंगा, रूपारेल की बाढ़ को बन्ध में लिया जाय। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाया गया जिसके फलस्वरूप जन व धन की हानि नहीं हुई। यही प्रबन्ध दिनांक २७ की बाढ़ के लिए भी किया गया। विविध बन्धों में मेग्जिमम पर्मीसिबल वाटर लेवल से अधिक पानी भरने नहीं दिया गया। क्योंकि सभी बन्ध कुछ खाली रखे गये थे। अब नदियों का पानी उनमें लिया जा रहा है ताकि वे अपने पूरे लेवल तक भरे जा सकें। यह बन्ध रबी की फसल को बोने के लिये सितम्बर माह के तीसरे सप्ताह में खाली कर दिये जावेंगे। अगर इसी दर्म्यान फिर से बाढ़ आवे तो फालतू पानी को उसी तरीके से निकाल दिया जावेगा जैसा कि इस वर्ष की पहली बाढ़ों में किया गया है। बाढ़ के विषय में जो सूचना तहसीलों से प्राप्त हुई है उसके अनुसार कुल तीन बन्धों की पालें टूटी हैं। वगोरा, बारेठा सेक्शन में, आर० टी० बन्ध धौलपुर सेक्शन में, और दोहरड़ा बन्ध रूपबास सेक्शन में। इन बन्धों की पालें अधिक वर्षा के कारण टूटी थीं जो कि दिनांक २७ को हुई। लेकिन इन बन्धों के टूटने से कोई जन व धन की हानि नहीं हुई सिवाय इसके कि केवल नीचे के इलाकों में पानी भर गया। इस जिले में मुख्य तौर पर भरतपुर व बयाना सब डिवीज़नों में काफी क्षेत्र में पानी भरा जाता है ताकि रबी की फसलें अच्छी पैदा हो सकें। बाकी इलाके में जहां खरीफ की फसल बोई जाती है वह अच्छी बताई जाती है और आशा यह है कि जहां कहीं खरीफ की फसल में पानी भरा है वह सूख जावेगा और करीब ६० प्रतिशत फसल फिर से पनप जावेगी। नुक्सान की रिपोर्ट सिर्फ परवाई खेड़ा, तहसील बयाना से आई है। जिससे १०,१२ मकानों की दीवारें गिर गईं और उनको नियमानुसार सहायता दिये जाने की कार्यवाही जारी है। नुक्सान अन्दाजन ५,०००रुपये का हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कहीं पर संपत्ति के हानि होने की सूचना नहीं है। रूपबास तहसील का अधिकतम भू-भाग नीचा है और खरीफ की फसल के समय वहां पानी जमा रहता है जिसके फलस्वरूप सड़क से आने जाने का रास्ता भी बन्द हो जाता है। जिलाधीश ने स्वयं कई तहसीलों में घूम कर यह पाया है कि तहसीलों की हालत अच्छी है और किसान इस साल की वर्षा से सन्तुष्ट हैं। इन सब हालात को देखते हुए केवल उन क्षेत्र में पानी भर जाना जहां कि अक्सर भर जाता है, यह कहा जाना ठीक नहीं होगा कि यह बाढ़ की स्थिति है। जब भी बाढ़ें आई उनका पूरा प्रबन्ध किया गया और उन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ काबू किया गया। सही बात तो यह है कि इस वर्ष इस समय तक भरतपुर जिले में कोई बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं हुई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय अध्यक्ष, यह जो वक्तव्य दिया गया है मैं समझता हूँ कि उसमें पूरे फैक्ट्स नहीं आये हैं। नगर तहसील में सीकरी के आसपास रूपारेल में २७-२८ को पानी आया है

Page No.36

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जिससे लाखों बीघा जमीन उजड़ गई है और उसने खरीफ की फसल को नष्ट किया है और उस पानी ने चारों तरफ फैल कर फसल को समाप्त कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो वक्तव्य दिया गया है वह दो-तीन तहसीलों के ही सम्बन्ध में है, पूरे जिले के सम्बन्ध में नहीं है....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहां का चाहते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नगर के पास सीकरी और पहाड़ी के सम्बन्ध में....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको रूपारेल के सम्बन्ध में बताया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नुकसान ज्यादा होना नहीं बताया।

श्री दामोदरलाल व्यास : नुकसान कुछ नहीं हुआ। बयाना तहसील में कुछ जगह जहां बरसात में पानी भर जाता है उस जगह को सेटलमेंट रेकॉर्ड में एक फसली काश्त की भूमि दिखाई गई है। आप रूपारेल के बारे में फरमाते हैं उसकी पोज़ीशन इस तरह की है। मैं आपको रूपारेल के बारे में फैक्च्युअल नोट जो एक्ज़ीक्युटिव इंजीनियर और कलेक्टर ने मिल कर बनाया है पढ़ कर सुना देता हूं ताकि सारी बात क्लीयर हो जाय :

"This river originates in Thana Ghazi District of Alwar..."

श्री अध्यक्ष : तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं उसका जबाब हो तो दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, इससे ज्यादा आप बताते हैं तो मैं आपको फैक्च्युअल नोट दे सकता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : स्थिति के सम्बन्ध में मैंने खुद सरपंच और तहसील का जो रिज़ोल्युशन आया वह साथ में दिया था। तो क्या यह समझा जाय कि पंचायत ने गलत रिज़ोल्युशन पास किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं गलत या सही की बात नहीं कहता।

श्री श्रीभानसिंह : पंचायत ने जो रिज़ोल्युशन भेजा मैंने वह लैटर भेज दिया, इसलिये क्या अब यह माना जाय कि पंचायत ने गलत रिज़ोल्युशन भेजा है ? रूपवास की बाढ़ के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि आई ही नहीं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा था कि बाढ़ वहां पर आई। कुछ जमीन नीचे लेवल पर है और हर साल सड़क के दोनों ओर पानी भर जाता है और आसपास के गांवों तक पानी फैलता है और सेटलमेंट रेकॉर्ड्स में एक फसल की जमीन दर्ज की गई है। वहां का असेसमेंट रबी का है और इनन्डेशन शुरू किया है। It is peculiar to Bhaatpur Distric। मैंने यह नहीं कहा कि बिल्कुल नुकसान हुआ ही नहीं। १०,१२ मकानों की दीवालें टूट गई हैं। कुल ५,००० का नुक्सन हुआ है। जो वस्तु-स्थिति कले-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कटर और एग्ज़ीक्युटिव इंजीनियर इर्रिगेशन ने बताई वह नोट पेश किया : १०–१२ मकानों की दीवारें टूटने के अलावा और कोई नुकसान हुआ हो तो आप बतावें I will depute Senior Officers to go to the spot also.

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

कार्य-सलाहकार समिति के सत्तरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सभापति, कार्य-सलाहकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के सत्तरहवें प्रतिवेदन से सदन सहमति प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकारी समिति के सत्तरहवें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करे।

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के रूप-रेखा पर विचार-विमर्श

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों से तृतीय पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। मैं इस पर अपने विचार प्रस्तुत करूं उससे पहले यह बात स्वत: पैदा होती है कि प्रारूप पर विचार करना है किन्तु किस आधार पर करना है और किस किस विषय पर हम अपने विचार रख सकते हैं। एक तो प्रारूप की साइज़ है। जो धन-राशि रखी है वह पर्याप्त है या नहीं और उस धन-राशि का जो बंटवारा किया गया है, वह ठीक तरह से किया गया है या नहीं; मैं इन दो मुद्दों पर अपने विचार जाहिर करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, आज प्लान डिस्कस हो रहा है लेकिन यहां पर न तो प्लानिंग मिनिस्टर मौजूद हैं और न फाइनेन्स मिनिस्टर हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या तो प्लानिंग की बात करें और क्या रिसोर्सेज़ की बात करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): We are here already. You will not find us wanting in any information.

श्री श्रीभानसिंह : यह ठीक है कि दो-तीन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और एक डिप्टी मिनिस्टर भी बैठे हैं। और एक नोन प्लान मिनिस्टर साहब जिनका प्लॉन से ताल्लुक नहीं है वे भी बैठे हुए हैं, लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर यहां मौजूद होते तो वे हेल्प कर सकते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : You will find that we will interfere whenever necessary.

श्री अध्यक्ष : Without listening to what they say?

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्लॉन की साइज़ है उस सम्बन्ध में जो थर्ड फाइव ईयर प्लॉन है उसकी साइज़ क्या है, प्लॉन कैसा है, किस

(श्री पी. के. चौधरी)

एम (aim) से थर्ड फाइव ईयर प्लॉन आया है, तृतीय पंच वर्षीय योजना का एम क्या होना चाहिये ? इसका एम और ऑब्जेक्टिव है वह जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में आया है वह एम पूरा होता है या नहीं, संविधान के आर्टिकल ३८, ३९ और ४१ के अनुसार स्टेट की क्या पॉलिसी प्लानिंग के बारे में होनी चाहिये, सोशियल ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिये, इकोनोमिक ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिये इस आकार पर प्लान के अन्दर ले-डाउन किया है या नहीं, यह देखने की बात है। थर्ड फाइव ईयर प्लॉन में इन ऑब्जेक्टिव्ज़ को पेज़ ११ पर दिया है जो इस प्रकार हैं:–

"(1) to secure during the Third Plan a rise in National income of over 5 per cent per annum, the pattern of investment being designed also to sustain this rate of growth during subsequent plan periods';

(2) to achieve self-sufficiency in foodgrains, and increase agricultural production to meet the requirements of industry and exports;

(4) to utilise to the fullest extent possible the manpower resources of the country and to ensure a substantial expansion in employment opportunities; and

(5) to bring about reduction in inequalities."

ये हमारे एम्स हैं। अब इन एम्स के बेसिस पर जो फर्स्ट प्लान हमने चॉक आउट किया था उस समय हमने ३० ईयर्स का प्रोस्पेक्टिव अपने सामने रखा था। ३० साल में जाकर, जो हिन्दुस्तान की नेशनल इन्कम है, या हिन्दुस्तान का स्टेन्डर्ड है उसको हम कहां पहुँचाना चाहते हैं ? अब फर्स्ट में यह हमने किया था कि १९७०–७१ तक जाकर, जो १९५१–५२ की नेशनल इन्कम थी उसको १९७०–७१ तब डबल करेंगे और जो पर–कैपिटा इन्कम थी उसे १९७७–७८ में जाकर हम डबल करेंगे। तो सेकिंड प्लान में हमने रखा था कि जो पर–कैपिटा नेशनल इन्कम है, उसको १९७०–७१ में जाकर डबल कर देंगे। अब पिछले दो प्लान के दरम्यान में, फर्स्ट प्लान और सेकिंड प्लान में, हमने नेशनल इन्कम को लगभग ४२ पर्सेन्ट बढ़ा दिया है और इस प्लान में हम पांच वर्ष में २५ प्रतिशत की और बढ़ोतरी करना चाहते हैं। इस तरह जाकर १९७०–७१ में नेशनल इन्कम डबल हो जायगी। यह हमारा ऑब्जेक्टिव है, यह एम है। इस एम को सामने रखते हुए, हमारे प्लान की साइज़ क्या होनी चाहिये, यह सबसे पहले हमको तय करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, साइज़ तय करने के लिए और प्लान में कितनी धन राशि रखनी चाहिये, इसको तय करने के लिये सबसे बड़ा सवाल आता है, वह रिसोंसेज़ का है। आया हमारे साधन कितने हैं: जिसके जरिये हम अपने प्लान की साइज़ तय करेंगे ? जैसे, अध्यक्ष महोदय, एक शेरवानी बनानी है। उसमें सवाल आता है कि शेरवानी कितनी लम्बी होनी चाहिये और वह कपड़े पर निर्भर रहती है कि कितनी खादी अवेलेबल है, कितना कपड़ा अवेलेबल है, और कपड़े की अवेलेबिलिटी के अनुसार हम शेरवानी

(श्री पी. के. चौधरी)

की साइज़ तय कर सकते हैं ।

जैसा कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमको टैक्स लगाने ही नहीं चाहिये और फिर भी जैसा प्लान चाहिये, वैसा प्लान बनना चाहिये। लेकिन रिसोंसेज़ या तो टैक्स से मिलते हैं या सेन्टर से मिलते हैं और जो सेन्टर से मिलते हैं, वह भी टैक्स के जरिये ही रुपया आता है । तो जितनी बड़ी साइज़ हम प्लान की चाहेंगे, उसी प्रमाण में हमें टैक्स के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रिसोंसेज़ का सवाल आता है। जैसा कि कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बताया और जैसा प्लान में दिया हुआ है, स्टेट सेक्टर में जो प्लॉन है, उसमें स्टेट्स में ३,६५० करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उस हिसाब से और राजस्थान की पोपुलेशन के हिसाब से हमारे प्लॉन की साइज़ छोटी पड़ती है । तो ३६५० करोड़ रुपये स्टेट प्लान में इन्वेस्ट किये जायेंगे, इन ३,६५० करोड़ रुपयों में से सेन्ट्रल असिस्टेन्स, जो कि पेज ७५ पर दी हुई है, ३,६५० करोड़ रुपये में से २,५०० करोड़ रुपये की सेन्ट्रल असिस्टेन्स रहेगी। इसका मतलब यह है कि स्टेट्स को १,१५० करोड़ रुपये इकट्ठे करने चाहिये । १,१५० करोड़ रुपये जो इकट्ठे करने हैं उसमें से राजस्थान का हिस्सा आता है ५३.७५ करोड़ रुपया। अब प्लान में जो रिसोंसेज़ रखे हैं, उसमें है कि जो ३,६५० करोड़ रुपये का स्टेट प्लान है, और उसको आज पोपुलेशन बेसिस पर अलॉट किया जाता है, उस हिसाब से अगर प्लान छोटा होता है तो जाकर रिसोर्सेज़ के लिए एफर्ट्स किये जायेंगे यानी ८४ करोड़ रुपये हमारे प्लान में स्टेट सेक्टर से देंगे। लेकिन जो प्लान पेश हुआ है उसमें ३,६५० करोड़ रुपये में से २,५०० करोड़ रुपया तो सेन्ट्रल असिस्टेन्स से मिलेगा यानि स्टेट्स को अपने एफर्ट्स से १,१५० करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं, उससे प्लान की लिमिट बनेगी । तो राजस्थान को ५० करोड़ इकट्ठे करने है, उससे ज्यादा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी प्लान की लिमिट है वह २०० करोड़ रुपये की रखी जाय। अब एडीशनल टैक्सेशन से २० करोड़ रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, उसके अलावा १० करोड़ नॉन टैक्सेशन मेजर्स से इकट्ठे कर रहे है, इस प्रकार ३० करोड़ रुपये एडीशनल फाइनेन्स के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं, वह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आज का प्रपोर्शन है, उससे प्लान की लिमिट २०० करोड़ रुपये की रहती है । अभी जो ५३.७५ करोड़ रुपये एग्ज़िस्टिंग लेवल ऑफ टैक्सेशन है, तो यह एग्ज़िस्टिंग लेवल ऑफ टैक्सेज़, एग्ज़िस्टिंग लेवल ऑफ इन्कम है, यह जाकर ५४ करोड़ रुपये हो जाती है। उससे २०० करोड़ रुपये का प्लान हम फाइनेन्स कर सकते हैं, subject to the conditions जो पेज ७५ ऑफ दी रिपोर्ट में कहा है, यानि ३,६५०करोड़ रुपये में से २,५०० करोड़ रुपये सेन्ट्रल असिस्टेन्स से मिलेगा । अब एडीशनल टैक्सेज़ के लिए एफर्ट्स करते हैं। तो एडीशनल टैक्सेज़ २० करोड़ रुपये ज्यादा लेते हैं एण्ड अदर नॉन टैक्सेशन के मेजर्स से १० करोड़ रुपये और लेते हैं। इस प्रकार ३० करोड़ रुपये फाइनेन्स करते हैं, इस प्रपोर्शन से हमारे प्लान की लिमिट है, यह इससे ज्यादा बढ़नी चाहिये ।

(श्री पी. के. चौधरी)

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि दूसरे स्टेट्स के प्लान देखेंगे; जैसे यू० पी० के प्लान को देखें, तो ६६३ करोड़ रुपये स्टेट सेक्टर से प्लान में मिलते हैं। यू० पी० के मुख्य मन्त्री को प्लानिंग कमीशन ने इन्डिकेशन दिया, जैसा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री को इन्डिकेशन दिया था कि इससे ज्यादा का प्लान नहीं बनना चाहिये। यू० पी० के मुख्य मन्त्री को इन्डिकेशन मिला कि यू० पी० का ६६३ करोड़ रुपये का स्टेट प्लान हो और क्योंकि यू. पी. के लिए, अध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा प्लान है, उसके कारण पब्लिक एन्टरप्राइजेज़ सेन्ट्रल सेक्टर से कुछ मिलेगा; इस प्रकार it will be to the tune of about Rs. 900 crores. यू.पी. ने फर्स्ट और सेकिंड प्लॉन में अलॉट किया, उसकी तरफ भी हम देख सकते हैं। फर्स्ट प्लान में १८२ करोड़ और सेकिंड प्लान में २५३ करोड़ रुपये हुआ, अब जाकर by a leap they come to Rs. 693 crores, that means about ७०० करोड़ रुपये हो जाता है प्रपोर्शनेट रेज़ हुआ है थर्ड प्लान में यू. पी. के अन्दर। राजस्थान का फर्स्ट प्लान ६२ करोड़ का था, सेकिंड १५० करोड़ का हुआ और थर्ड प्लान डबल हुआ यानि २१२ करोड़ रुपये का, जब कि यू. पी. का थ्री टाइम्स बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश का आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल और विन्ध्य प्रदेश, इन तीनों का मिल कर हुआ है, तो तीनों का मिल कर फर्स्ट प्लान ५४ करोड़ रुपये का था, सेकिंड प्लान १६० करोड़ का हुआ है और अब जाकर मध्य प्रदेश में आज अखबारों में देखें तो वहां स्टेट का प्लान ४६२ करोड़ रुपये का है। बाकी स्टेट्स की जो सीलिंग स्टेट की तरफ से चेंज करने का इशारा किया है, मैं देख रहा हूं कि वह राजस्थान से काफी ज्यादा है। यू. पी. के लिए ऐसा महसूस हो रहा है, यू. पी. के एम. पीज़. ने लॉबीज़ में एक बात क्रियेट कर दी! मैं समझता हूँ कि यू. पी. का सेकिंड प्लान २५३ करोड़ रुपये का था, अब जिस रेट से राजस्थान को सीलिंग दिया जा रहा है, उस रेट से यू. पी. को दिया जाय, तो यू. पी. का मेग्ज़िमम ५०० करोड़ रुपये से ज्यादा किसी कन्डीशन पर नहीं हो सकता। अगर राजस्थान को २१२ करोड़ रुपये का अलॉटमेंट होता है तो यू. पी. को ५०० करोड़ रुपये से ज्यादा का अलॉटमेंट नहीं हो सकता। उस स्थिति में यू. पी. का किसी हालत में ७०० करोड़ रुपये हो नहीं सकता। Over and above this, they are getting Rs. 200 crores investment under central sector. तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो साइज़ है इसमें हम देखते हैं कि इस साइज़ को तय करने में जहां तक राजस्थान का अपने रिसोर्सेज़ रेज़ करने का सवाल है, जो एग्ज़िस्टिंग प्लान सीलिंग रखा है २०० करोड़ रुपये का, उसको विदाउट एडीशनल टैक्सेशन, जो ६३ करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यु से होता है उसको मिला कर मीट कर सकते हैं। लेकिन जो एफर्ट्स का सवाल है, हम एफर्ट्स में ३० करोड़ रुपये एडीशनल रेवेन्यु, २० करोड़ एडीशनल टैक्सेशन से, १० करोड़ नॉन टैक्सेशन मेजर्स से इकट्ठे करते हैं। उस अवस्था में in proportion to what will be the response from the Centre है।

सेन्ट्रल असिस्टेन्स जो है, मैं मानता हूं

Page No.41

(श्री पी. के. चौधरी)

उसमें रीजनल डेवलपमेंट का सवाल आता है, वह रफ प्लान में दिया हुआ है। यह थर्ड फाइव ईअर प्लान बनेगा, उसमें रीजनल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जायगा। हर एक रीजन का बैलेन्स्ड डेवलपमेंट होगा। उसमें राजस्थान का भी एक स्थान होता है। ड्राफ्ट प्लान में कहा गया है कि उनको जो एलोकेशन होगा, जो इन्वेस्टमेंट हो, उस इनवेस्टमेंट में कोई बाधा इस प्रकार की नहीं हो कि जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें रिटर्न नहीं होगा या अनप्रोफिटेबल होगा। तो राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट होगा वह प्रोफिटेबल जरूर होगा। इस ग्राउन्ड पर राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न नहीं मिल सके, यह कारण नहीं है। Rajasthan is rich in mineral wealth and in so many other aspects. तो इसलिए कम फंड अलॉट करने का कोई कारण महसूस नहीं होता है। दूसरी बात, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि प्रोपर कोर्स यह रहता कि राजस्थान का ५०० करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट होता, जैसा कि नेशनल सर्वे कमेटी की रिपोर्ट में है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि वह होना ही चाहिए; वह तो होना चाहिये। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से एलॉटमेंट हो। जैसे ३० करोड़ के एडीशनल टैक्सेज़ हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम कह सकते है कि इससे आगे चल कर हम पैसा इकट्ठा कर लें। Why the Centre should be so parsimonious in alloting funds to us? यानि उनकी पॉलिसी राजस्थान के लिये भी इतनी ही लिबरल होनी चाहिये जो यू. पी. और दूसरे प्रान्तों के लिये होनी चाहिये। दूसरे प्रान्तों के पब्लिक सेक्टर का टोटल पब्लिक एन्टरप्राइज़ का जो इन्वेस्टमेंट था आज ८८० करोड़ रुपयों का पब्लिक एडवान्सेड के over and above this, सेन्टर ने ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेशन्स पर जो इन्वेस्ट किया वह १,२६० करोड़ इन्वेस्ट किया। जहां सेन्टर ने १,२६० करोड़ इन्वेस्ट किया उसमें से राजस्थान को कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। आप देखेंगे कि सेन्टर में सेकिन्ड प्लान में भी राजस्थान को १५ या २० मील की रेल्वे लाइन मिली और अभी भी २० मील की मिलेगी। जब कि १,२६० करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें दूसरों को काफी मिला है और राजस्थान को एक फूटी कोडी भी नहीं मिली है। सेन्टर की तरफ से ८८० करोड़ का दूसरा इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें भी राजस्थान को एक पाई का भी फायदा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं, दूसरे सेक्टरों में जो धन राशि दी गई है उनके फिगर्स की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसलिये कि जहां तक पब्लिक सेक्टर का प्रश्न है उसमें भी राजस्थान के साथ किस प्रकार से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया है। जैसा ८८० करोड़ की बात मैंने आपको कही कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में यह हुआ, इन सब के फिगर्स मेरे पास हैं:—

महाराष्ट्र में लगभग ३ करोड़ का इन्वेस्टमेंट

गुजरात में लगभग ५ करोड़ का इन्वेस्टमेंट

वेस्ट बंगाल में १६२ करोड़ का इन्वेस्टमेंट।

इसमें दुर्गापुरा के लेटेस्ट फिगर्स १३८ करोड़ के थे।

(श्री पी. के. चौधरी)

वेस्ट बंगाल	६० करोड़
बिहार	६४ करोड़
मैसूर	२० करोड़
मद्रास	२४ करोड़
दिल्ली	२.५ करोड़
केरल	६४ लाख का हुआ

जब कि राजस्थान में ० पर्सेन्ट ।

केरल जैसे प्रान्त के लिये ६४ लाख और आन्ध्र में ४ करोड़ ।

उड़ीसा में अध्यक्ष महोदय, रूरल में actual investment to the tune of १७० करोड़ का हुआ । इसके अलावा १० लाख माइन्स के लिये ।

मध्यप्रदेश में १३५ करोड़, इसमें से १०० करोड़ भिलाई के लिये but the actual expenditure was 121 crores.

इसके अलावा आसाम में ५० लाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी काफी इन्वेस्टमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है । जैसा इस प्लान में कहा गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट है । हम क्या चाहते हैं ? वे कहेंगे कि समान रकम वे देंगे और इससे जब कार्य चालू होंगे तो स्टेट में एम्पलॉयमेंट बढ़ेगा । जब कहीं पर एक एन्टरप्राइज़ लोकेट होता है तो उसके साथ साथ कई एम्पलॉयमेंट ऑपोचुनिटीज़ बढ़ती हैं और कई डेवलपमेंट रहते हैं, उसके आस पास में industrial township हो जाती है । तो इसमें पब्लिक को १०० करोड़ करने का है तो आधा स्टेट सेक्टर और आधा प्राइवेट सेक्टर में होता है । इसमें इन्डस्ट्रीज़ डेवलप हो जाती हैं; anciliary industries develop हो जाती हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि इन सभी बातों को देखते हुए राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं किया गया । इसका क्या कारण है ? इसका ग्राउन्ड समझ में नहीं आता । There is no ground.

मैं आपका ध्यान पेज २२९ ऑफ दी ड्राफ्ट प्लान की तरफ आकर्षित करूंगा । वहां पर एक एनेक्श्योर है ? There are about 90 enterprises; लगभग ९० एन्टरप्राइजेज़ हैं जो ९० एन्टरप्राइजेज़ पब्लिक सेक्टर में हैं वे इन्डस्ट्रीज़ और माइनिंग सेक्टर में । हैं इसमें शिपिंग और डोक यार्ड भी आता है । Unfortunately, not a single project has been allotted to Rajasthan. वे आपका खेतरी क्या है ? इसलिये जो रखा है वह भी इसमें रखा गया है । इसलिये भी मुझे अब शंका है क्योंकि इसके लिये यह कहा जा सकता है कि अभी तक इसका फोरिन एक्सचेन्ज तय नहीं हुआ है ।

Under the new projects included in the Plan for which foreign credits have not yet been arranged. Under this heading comes your Khetri. आपके खेतड़ी को भी ऐसे रखा है । फोरिन एक्सचेन्ज का इन्तजाम नहीं होगा । खेतडी देने से क्या होगा ? पिछले सेकिन्ड प्लान में जिस तरह से राजस्थान को निग्लेक्ट किया तो जैसा हम कहते हैं to make up the back log, तो यह राजस्थान को निग्लेक्ट करने का back log है । राजस्थान को निग्लेक्ट किया

(श्री पी. के. चौधरी)

है, उसको मीट आउट करने के लिये atleast a few more industries, अध्यक्ष महोदय, यहां रहनी चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में १,५०० करोड़ का पब्लिक सेक्टर का प्लान है उसमें से ५० करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर में लोन का दे रहे हैं। वह लोन भी दूसरी रियासतों में जा रहा है । बाकी १,४५० करोड़ है उसमें लगभग ५७५ करोड़ आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज़ पर लगाने का फैसला कर दिया गया है । अभी आइरन एन्ड स्टील की पोसिबिलिटी नहीं है कि कहां पर खर्च किया जावेगा ? राजस्थान में काफी आइरन ओर डिपोजिट्स हैं । इसकी बहुत गुंजाइश है, जो आज मद्रास में जाकर नेवली में रहे हैं। इसकी राजस्थान में बहुत गुंजायश है। राजस्थान में पलाना कोल, lignite coke available हो सकता है । इसलिये मैं यह चाहूँगा और इस बात के लिये मैं चीफ मिनिस्टर को भी जोर देना चाहूंगा कि जब आप प्लान सीलिंग के बारे में बात करने जावें तो जैसा उन्होंने खुद कहा और जैसा सदन का ख्याल है कि हमारा साइज़ ऑफ प्लान बढ़ना चाहिये और ५०० करोड़ होना चाहिये; यह तो स्टेट में प्राइवेट सेक्टर है ।। जैसे आप यू० पी० में १०० करोड़, भाखरा प्लान में २०८ करोड़ का सेन्टर का इन्वेस्टमेंट है । यू० पी० में १०० करोड़ है तो राजस्थान में भी कुछ न कुछ मिलना चाहिये । ५७५ करोड़ आइरन एन्ड स्टील के लिये है उसमें से कुछ एक्स-टेन्शन के लिये राजस्थान में होना चाहिये । बाकी कुछ इन्डस्ट्रीज़ के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम हमारे पास Blast furnace, iron ore पर experiment करने के लिये होना चाहिये । भोपाल में २० करोड़ का अलग प्लान है । Heavy electrical machine manufacturing plan आप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं । अब उस एक प्लान्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ग्राउन्ड यह नहीं होता है कि रॉ मेटीरियल ऐसा हो । भोपाल में है । एडीशनल इलेक्ट्रिकल मशीनरी प्लान्ट वे इरेक्ट करने जा रहे हैं । आपको राजस्थान में इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिये । एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स की एक फेक्टरी भी यहां होनी चाहिये ! Rajasthan will be the future granary of India. राजस्थान फ्यूचर ग्रेनरी ऑफ इन्डिया होने जा रहा है, तो उसके लिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स राजस्थान में ही बनने बहुत जरूरी हैं और इसलिए यहां पर यह एक फेक्टरी होनी चाहिये । इसी तरह से प्लान में पांच डाइस्टफ्स केमिकल्स और ड्रग्स की फेक्टरी दी है । उनमें से भी यहां पर एक–दो फेक्टरी हो जानी चाहिये । केमिकल्स के लिए राजस्थान काफी उपयुक्त है । मैं आशा करता हूँ कि राज्य सरकार यदि केमिकल्स या ड्रग्स की कोई फेक्टरी खुले तो उसके लिए पूरा जोर देगी । ऑर्डिनेन्स फेक्टरी के लिए भी कहना चाहिये ।

गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के ड्राफ्ट प्लान में भी मैंने देखा है कि ऑइल एक्स्प्लोरेशन के लिए स्टेट का पार्टिसिपेशन भी हो । एक हफ्ता पहले मैंने देखा कि Stanvac Company has offered to explore for oils in Jaisalmer area in

(श्री पी. के. चौधरी)

Rajasthan. राजस्थान में एक्सप्लोरेशन करने के लिए it appeared in the papers only a couple of days ago; उसका फायदा राजस्थान को मिलना चाहिये और ऑइल एक्सप्लोरेशन के लिए राजस्थान के लिए यह करना चाहिये।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, एक हमारे यहां पर डीज़ल सेट के लिए पिछले समय मुख्य मंत्री महोदय ने और शायद गवर्नर के एड्रेस में भी यह कहा था कि राजस्थान में सवाई माधोपुर में यह होगी। इसको थर्ड फाइव ईयर प्लान में नहीं लिया है। क्यों हुआ? विद्ड्रॉ किया है तो फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए कहा जाना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि वह पैराम्बूर में हो रही है। लाइसेन्स इश्यू हो गया है। उसको पेराम्बूर में ले जाया जाता है। उसको प्राइवेट सेक्टर में न चलाना हो तो भारत सरकार को सवाई माधोपुर में पब्लिक सेक्टर में चलाने के लिए कहना चाहिये और जोर देना चाहिये।

सोडा एश प्लान्ट सांभर लेक में है और काफी अर्से से चल रहा है। इस प्लान में नहीं होगा। थर्ड प्लान के अन्त में इम्प्लीमेंट किया जावेगा।

राजस्थान केनाल के लिए एडीशनल रखा है। यह कहा जाता है कि यह स्टेट सेक्टर में होगा और प्लानिंग बोर्ड ने भी प्रस्ताव किया है कि स्टेट सेक्टर में हो जाय। हमारी २१२ करोड़ की नोर्मल सीलिंग है। यदि २५० करोड़ भी मान लें, तो राजस्थान केनाल ओवर एन्ड एबव होना चाहिये, ऐसा प्लानिंग बोर्ड का रिज़ोल्यूशन है। मैं एक स्टैप आगे जाना चाहता हूं। दामोदर वेली कॉर्पोरेशन और राजस्थान केनाल में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। उसका एड्वान्टेज़ बिहार और बंगाल के एरिया को मिलेगा। इसी तरह राजस्थान केनाल के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने डिस्कशन इनिशियेट करते हुए बताया था कि according to the calculations of their engineers, इन्जीनियर्स की राय के हिसाब से पेरेनियल इर्रिगेशन का फायदा फोर्थ प्लान में मिलेगा। इससे फोर्थ प्लान से पहले रिटर्न मिलना भी मालूम नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन ने स्टेट को यह अधिकार दिया है कि स्टेट्स अपने प्लान अपने ढंग से बनायें और चीफ मिनिस्टर्स को हिदायत दी है कि डिस्ट्रिक्ट के माफिक स्टेट प्लान बनायें, अपनी जरुरियात के माफिक बनायें। जब बनायेंगे तो मैं कहूंगा कि दस साल के बाद राजस्थान केनाल आती है, it may sound as sacrilege. लेकिन मैं कहना चाहता हूं that we can wait for it. मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। अगले पन्द्र-हबीस वर्ष की राजस्थान की जो जरूरियात है उसको एग्ज़िस्टिंग इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनसे पूरी कर सकते हैं या नहीं। थर्ड फाइव ईयर प्लान में और प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग में कहा गया है by the beginning of the 5th. Five Year Plan, agriculture pressure पोपुलेशन का ७० पर्सेन्ट है, वह ६० पर्सेन्ट हो जायेगा, ४० पर्सेन्ट इन्डस्ट्रीज़ पर या अदर ऑक्युपेशन पर डिपेन्ड करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग प्लानिंग हो तो फोर्थ प्लानिंग में जाकर 60 percent of our population will depend on agriculture. अब से जो हमारा प्लानिंग

(श्री पी. के. चौधरी)

है उसका ट्रेन्ड लेंगे, 40 percent of the persons will depend on non-agricultural operations इन्डस्ट्री की तरफ जाकर रहेगा न कि एग्रीकल्चर की तरफ। हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं या राजस्थान केनाल है उसको क्यों लेना चाहते हैं? राजस्थान केनाल बनायेंगे तो राजस्थान की बहबूदी बढ़ेगी, यह कहा जाता है। आज मैं सोचता हूं राजस्थान केनाल, from the point of view of requirements, from the point of view of exigencies, it is a 'must' for the Centre and not for Rajasthan.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो हमारी फूड रिक्वायरमेन्ट्स हैं उसमें से बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है ५१ में २० लाख टन। ५६ में ४१.३७ लाख टन्स व ६१ में होगा ५० लाख टन्स और ६६ में ६६.६८ लाख टन्स। यह हमारा फूड प्रोडक्शन होगा। फूड रिक्वायरमेन्ट्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है। एक आदमी को १८ औंसेज़ फूड ग्रेन्स चाहिये। ज्यादा से ज्यादा २० औंसेज़ लगा लीजिये। उसमें मैंने एडल्ट्स और बच्चे शामिल कर लिये हैं अदरवाइज़ केल्कुलेशन का जो तरीका है वह १० साल के बच्चे का हाफ़ एडल्ट युनिट मानना चाहिये। १८ युनिट के हिसाब से सन् ६१ में ३६.७६ लाख टन्स की आवश्यकता होगी, पहले से १४ लाख ज्यादा। ६६ में जाकर on the basis of 18 ozs. even for a child of six months; उसके हिसाब से फूड रिक्वायरमेन्ट्स, अध्यक्ष महोदय ४०.६७ लाख टन्स हैं। यह १८ औंसेज़ के हिसाब से है। २० औंसेज़ का हिसाब लगायें तो ६१ में ४० लाख टन्स और ६६ में जाकर ४५।। लाख टन्स की फूड रिक्वायरमेन्ट्स होती हैं। आज का फूड प्रोडक्शन है it is enough to meet our requirements even after 1966. आज राजस्थान केनाल is not a 'must' for us. उसका फूड ग्रेन्स हम पैदा करेंगे, that will be to make India self-sufficient.

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के जो फूड टार्गेट्स हैं, १०० मीलियन टन्स का हिसाब रखा है। सारे हिन्दुस्तान की पोपुलेशन है, १८ औंसेज़ के हिसाब से और १० साल के बच्चे का हाफ युनिट का हिसाब लगाते हैं तो ८५ मीलियन टन्स आता है और २० औंसेज़ का हिसाब लगाते हैं तो ९० मीलियन टन्स आता है। ओवर ऑल जो पिक्चर है, it is on the border, on the brink; लेकिन उस ब्रीफ में भी पी० एल० 480 का 17 million tons का offer है। हमारी जो फूड प्रोब्लम है it is a headache for the Centre. लेकिन राजस्थान में जाकर, with our existing Plan, with our existing projects, जो चम्बल की स्कीम है या जो माइनर या मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया है और ६१ में जाकर एक्चुअल प्रोडक्शन है, जब पोपुलेशन २ करोड़ २० लाख हो जायगी वे फूड रिक्वायरमेन्ट्स को मीट कर सकती हैं।

इस हालत में जो लिबर्टी दी जाती है वह अपने रिक्वायरमेन्ट्स के माफिक within certain limit they had to prepare their plans. मैं कहूंगा राजस्थान केनाल का फायदा या अर्जेन्सी हमारे लिये उतनी नहीं जितनी कि सेन्टर के लिये है। एक बात जरूर हमारे

(श्री पी. के. चौधरी)

यहां पिछले दिनों में हुई वह यह कि जिस प्रकार भाखरा नांगल बान्ध का इमोशन वहां की जनता में क्रिएट किया गया उसी प्रकार का इमोशन राजस्थान केनाल के लिये किया गया और कहा गया कि इससे बड़ी बहबूदी होगी। इस प्रकार के इमोशनल का बेक ग्राउन्ड हमने क्रिएट किया, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने किया और हम सब ने किया। लेकिन जब इसको अनेलाइज करते हैं तो राजस्थान केनाल का फायदा जो दस साल के बाद हमें मिलेगा दूसरी हमारी नीड्स हैं, आवश्यकतायें हैं हमारी इकोनोमी ऑल इन्डिया के साथ रहते हुए हमें इन्डस्ट्रियल बायस यहां लाना है और वह इन्वेस्टमेन्ट अगर हम राजस्थान केनाल के लिये कर देते हैं जो कि करीब ४५ करोड़ रुपया इस योजना में है that is an important question to be decided. इसलिये मेरी ओपीनियन यह है कि यू० पी० के चीफ मिनिस्टर की तरह हमारे मुख्य मंत्री के साथ हम सपोर्ट करें कि every single citizen of this State will be behind him when we fight for the cause with the Centre. आज यदि राजस्थान केनाल के बगैर हम चलते हैं तो even then we can develop our industries in a better way than after taking the Rajasthan Canal in our State. जब कि दामोदर वेली सेन्ट्रल सब्जेक्ट में जा सकती है तो फिर राजस्थान केनाल सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं आ सकती? आज हम राजस्थान केनाल को हमारी इस प्लान में लेते हैं तो उस हालत में हम उसको स्ट्रेगर कर सकते हैं। जहां ४५ करोड़ रुपया खर्च करने का है वहां हम केवल १० करोड़ रुपया खर्च कर दें। इस तरह से हम इस कार्य को धीमा कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन हमें मजबूर करे या पं० नेहरू हमें इसके लिये कहें तो भी हमें स्ट्रेगर करने का अधिकार है। आखिर वे बड़े भाई हैं, उनका कहना तो हमें मानना होगा लेकिन हर राज्य को इन्डिपेन्डेन्स तो दी हुई है। मुख्य मंत्री महोदय को अधिकार है वे इस बारे में कह सकते हैं कि हमारे पास इतना रुपया नहीं, हम इसको धीमी गति से कर सकते हैं। पहले तो बात यह है कि इसको हमारी प्लान के अन्दर लेना ही नहीं चाहिये और अगर किसी के दबाव से या कहने से ले भी लेते हैं तो इस पर दस करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं लगावें। आज तक हमने भावावेश में आकर यह कहा कि राजस्थान केनाल के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इस तरह से हम एग्रीकल्चरल इकोनोमी को ज्यादा तरजीह देते जा रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि एग्रीकल्चर इकोनोमी के बजाय इन्डस्ट्रियल इकोनोमी की ओर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि agriculture economy is a sign of backward economy. इस तरह से इन्डस्ट्रियल इकोनोमी एडवान्स्ड इकोनोमी है। अगर हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज़ करना है then मेजुअली the pressure of population on agriculture will have to be reduced; जब कि हम धीरे धीरे ५० से ४० पर्सेन्ट तक लायेंगे। Today the whole trend is to shift the people from agriculture to industry यह लौंग टर्म प्लान है, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है। हिन्दुस्तान का प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग इन्डस्ट्रीज़ से चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम राजस्थान के प्लान को लेते हैं तो यहां एग्रीकल्चरल इकोनोमी को ज्यादा महत्व दिया

Page No.47

(श्री पी. के. चौधरी)

गया है । इसलिये मेरा मुख्य मंत्री की मार्फत प्लानिंग कमीशन से यह निवेदन है कि राजस्थान का भी लोंग टर्म प्रोस्पेक्टिव होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपने को संक्षिप्त करें क्योंकि और भी माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे । Kindly make your points brief and to the point.

श्री पी० के० चौधरी : Now I will come to priorities. हमारी प्लान में प्रायोरिटीज़ हैं । अध्यक्ष महोदय, वे इस प्रकार हैं:—

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय टाइम लिमिट कर दी जाय । जहां तक प्लानिंग कमीशन से लड़ने का सवाल है हम मुख्य मंत्री महोदय को फ्री स्टाइल देते हैं, लेकिन जहां तक बोलने का सवाल है उसके लिये तो टाइम लिमिट कर दी जाय ।

श्री पी० के० चौधरी : जहां तक प्रायोरिटी का सवाल है हमारा जो प्लान है और जो नेशनल प्लान है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको कम्पेअर करके देखना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member will finish within 10 minutes.

श्री पी० के० चौधरी : I have spoken for half an hour only.

श्री अध्यक्ष : You have taken forty minutes.

श्री पी. के. चौधरी : I will take five or ten minutes. अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रायोरिटीज़ का सवाल है सेन्टर का जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है इसमें एग्रीकल्चर कॉम्युनिटी डेवलपमेंट और इर्रिगेशन इन सब का मिला कर जो पर्सेन्टेज आता है उसका २३ पर्सेन्ट थर्ड प्लान में अलोकेशन आता है, यह भी मेजर और मीडियम इर्रिगेशन को मिलाकर के होता है । और दूसरी तरफ हमारे यहां का एग्रीकल्चर अलॉटमेंट का पर्सेन्टेज लेते हैं तो वह करीब ८ पर्सेन्ट आता है । राजस्थान में २६ करोड़ का अलॉटमेंट होता है उसके हिसाब से १२.५ एग्रीकल्चर में अलॉटमेंट करते हैं । कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन १२॥ पर्सेन्ट करते हैं, मेजर और मीडियम के लिये ११॥ पर्सेन्ट । ऑल इन्डिया का जो पिक्चर है उसका २३ १ पर्सेन्ट है । इन्डस्ट्रीज़ के परसेन्टेज को लेते हैं तो ऑल इन्डिया का जो पिक्चर है वह लगभग २४ पर्सेन्ट के करीब आता है, २० पर्सेन्ट इन्डस्ट्रीज़ में आता है । उसके मुकाबले हम राजस्थान को देखते हैं तो इन्डस्ट्रीज़ के लिए जो फिक्स किया है, राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ के लिए ३०३ पर्सेन्ट आता है । ऑल इन्डिया की स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का अलोकेशन ३.०६ पर्सेन्ट है और राजस्थान में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के लिए अलोकेशन हम करते हैं ३.०३पर्सेन्ट। जहां तक अलोकेशन का सवाल है हमने एग्रीकल्चर में अलोकेशन ज्यादा किया है ।

दूसरी बात, एग्रीकल्चर के इन्टर-अलोकेशन की हैं । इसके लिए भी हमने दस करोड़ रुपया किया है और एनिमल हस्बेन्डरी के लिये ७करोड़ किया है, which is a dispro-

(श्री पी. के. चौधरी)

portionately large share. जहां हम एग्रीकल्चर पर १० करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां केवल एनिमल हस्बेन्डरी पर ७ करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो; यह किस प्रकार से हो सकता है? आखिर जो प्लान में प्रायोरिटी फिक्स करते हैं वह आखिर डिमान्ड्स के आधार पर ही करते हैं और उसके साथ साथ सारी धन राशि भी हमारे सामने रहती है और अलोकेशन भी उसी के माफिक होता है। तो वैसी हालत में जहां ऑल इन्डिया का टोटल ३३ पर्सेन्ट है वहां हमारा पर्सेन्टेज बहुत ज्यादा है। इसके अलावा विदिन दी एग्रीकल्चर इटसैल्फ जहां हम दस करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं वहां एनिमल हस्बेन्डरी पर ७ करोड़ खर्च कर रहे हैं। हो सकता है एनिमल हस्बेन्डरी के लिये हमारे प्रान्त में बहुत गुंजाइश हो लेकिन इतनी डिस्पेरिटी जो है वह नहीं होकर इन्डस्ट्रीज़ में यह रकम बढ़ाई जानी चाहिये थी।

(१ म० प०)

अब जहां तक इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने जो अलोकेशन रखा है उसमें स्माल इन्डस्ट्रीज़ के लिए ६॥ करोड़ में से २ करोड़ रखा है। बाकी पचास लाख हमने एक कॉर्पोरेशन के लिए रखा है। वह कार्पोरेशन मार्केटिंग पर्पज़ से है। वहां इन्डस्ट्रियल पर्पज़ नहीं है। मैं चाहता हूं सेन्टर ने जब ३.४ के हिसाब से भी रखा है तो वह भी जाकर ७॥ करोड़ होता है, जबकि हमारे यहां इन्डस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर नहीं के बराबर है दूसरों के मुकाबले में। तो कम से कम हमें साढ़े सात करोड़ तो मिलने चाहिये। यह तो एब्सोल्यूट मिनिमम मोस्ट है। तो इस ६॥ करोड़ को बढ़ा कर कम से कम ७ करोड़ कर दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, सोशियल सर्विस के लिए लगभग हमारा खर्चा २६ पर्सेन्ट से ज्यादा आता है। लगभग ५७ करोड़ होता है इस पर सेन्टर का यह ट्रेन्ड रहा है कि पहली प्लान में २२ पर्सेन्ट रहा, दूसरी में १८ और अब तीसरी प्लान में १७ पर्सेन्ट किया। In proportion to other investments, there is a downward trend. तो सोशियल सर्विस पर हमारे इन्वेस्टमेंट में कट करना चाहिये। इसको किसी प्रोडक्टिव वर्क के लिए चाहे, आप उसको राजस्थान में इन्डस्ट्री में लगावें, किसी में लगावें; पर लगावें प्रोडक्टिव वर्क में। फिर सोशियल सर्विस के लिए कोई यूज़ भी नहीं इस रकम का। पिछली साल ४५ लाख उनको दिये गये, पर उसका आधा भी वे युटीलाइज़ नहीं कर पाये। They could not spend even the half. फिर भी इस तीसरी प्लान में उनको १.५० करोड़ दिया गया है जो एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेट जम्प है। सभी प्लानों में फर्स्ट पर्फोर्मेन्स के साथ सम्पर्क जरूर रहता है पर इस सोशियल सर्विस में तो जाकर काफी जम्प लगाया गया है। ४५ लाख था जो भी खर्च नहीं कर सके, पर इस बार ४५ की बजाय उनको १.५० लाख दिया गया है। तो मैं चाहता हूं यह डिसप्रोपोर्शनेट जम्प है और इसमें कट किया जाना चाहियें।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, सोशियल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी कमी की जावे। १५ लाख एडल्ट एजुकेशन के लिये रक्खा गया है और ५ लाख सोशियल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अफसरों के लिए। तो यह

(श्री पी. के. चौधरी)

डिपार्टमेंट के अफसरों का सारा का सारा कट कर दिया जाना चाहिये। Social Education is a branch of general Education itself. इसे डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन या डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अन्डर में रखा जा सकता है और उसकी देखरेख में भी यह चल सकता है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट पर, इसके ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट पर यह खर्चा इस तरह आसानी से बचाया जा सकता है।

एक बात इसके बाद, मैं, अध्यक्ष महोदय, रोड्स के लिये कहना चाहता हूं। राजस्थान के पिछले प्लान में इसके लिये ६ करोड़ रुपया था, इसमें १८ है। अब १८ को देखते हैं तो यहां की हालत को देखते हुए यह इनसफिशियेन्ट है। जब कि हम रोड प्लान देखते हैं तो इसमें जो कमिंग २० ईयर्स में रोड डेवलपमेंन्ट का ४७० करोड़ का अलॉटमेंट है इसमें से ड्युरिंग दी पीरियड ऑफ थर्ड प्लान, इस थर्ड प्लान के दरमियान में ११ पर्सेन्ट के हिसाब से हमें अलोकेशन मिलना चाहिये और इस ११ पर्सेन्ट से ४७० करोड़ सब को मिला तो ४८ करोड़ की हमारी रोड प्लान बननी चाहिये। तब जाकर ११ पर्सेन्ट की बात ठीक हो सकती है। पर हमने १८ करोड़ का ही बनाया है जो बहुत कम है। जब रोड प्लान हमने २० वर्ष का एक्सेप्ट किया है और राजस्थान में जब दूसरे किसी तरह का ट्रान्सपोर्ट नहीं है जब कि और तमाम स्टेटों में Railway transport is there, road transport is there and over and above that inland water transport also is there. जब कि राजस्थान में यह एक मील का भी नहीं है। Quite a large proportion of traffic in other States is inland water transport. आप चाहे यू० पी० में देख लें, मद्रास में देख लें, केरल और बम्बई में देख लें, कहीं भी देख लें; जहां भी जावेंगे, पंजाब में जाइये, वहां भी इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट काफी मात्रा में मिलेगा। तो पहले तो ११ पर्सेन्ट में से भी हमें बहुत कम मिला है। इसको जब नहीं किया तो कम से कम Rajasthan being an undeveloped area from the point of view of communications अगर आप ग्यारह पर्सेन्ट यानी ४८ करोड़ भी नहीं करते तो इसका पचास पर्सेन्ट ही सही, २५ करोड़ का तो प्लान बनाना ही चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। यह १८ करोड़ का रोड प्लान देखा तो इसमें १.७५ लाख भाखरा नांगल और राजस्थान केनाल एरिया में और ६० लाख चम्बल एरिया में सड़कें बनाने के वास्ते रखा गया है। इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान केनाल जब बनेगी तो केनाल के पास भी एक सड़क बनेगी। Rajasthan Canal is going to be a very big canal fit for Navigation also. अब केनाल के पास प्रोजेक्ट एरिया में जब सड़क बन रही है और काफी बड़ी और पक्की बन रही है तो फिर इतना रुपया देकर पी० डब्ल्यू० डी० विभाग से और बनाना, यह क्यों? ये डुप्लीकेट होंगी सड़कें?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो इसमें यह १.७५ का अलोकेशन जाना नहीं चाहिये और नॉर्मल बजट ऑफ दी स्टेट में से तो और भी नहीं जाना चाहिये।

(श्री पी, के. चौधरी)

राजस्थान केनाल बजट फण्ड में से यह जाना चाहिये ।

इसी तरह चम्बल का ६० लाख भी इसमें से नहीं जाना चाहिये ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बस, अध्यक्ष महोदय, within a minute.

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद ।

श्री पी० के० चौधरी : I am still in possession of the floor.

श्री अध्यक्ष : Next speaker has been called. It is not necessary for you to touch on all the points. There are other speakers also.

श्री पी० के० चौधरी : Within a minute I will finish.

श्री अध्यक्ष : Next speaker please. I gave you ten minutes to wind up but you did not do so.

श्री पी० के० चौधरी : I am just concluding, Sir.

श्री अध्यक्ष: I have given two warnings to the Hon'ble member and if he does not listen to them and concludes his speech, then it is his own fault.

(विराम)

श्री चन्दनमल वैद ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस बात के लिये तो राजस्थान सरकार को बधाई देनी चाहिये कि दूसरी योजना से यह दुगुनी बड़ी बनाई है और इस बात के लिये भी खुशी प्रकट करनी चाहिये कि अन्न के मामले में जहां दूसरे प्रदेश अभी कमी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान, जो आम तौर पर रेगिस्तान प्रदेश माना जाता है और जिसके लिये आम तौर पर लोग सोचते हैं कि यह कमी वाला प्रदेश होना चाहिये, उस मामले में हम आत्म निर्भर हैं। यही नहीं, बल्कि दूसरों को भी भेजने लायक हैं। पर इस सारी प्रगति और सन्तोष को अगर हमने ठीक तरह से अभी से निभाना शुरू नहीं किया तो मैं समझता हूं कि आगे वह वक्त आ रहा है जब हमारे सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जावेंगी और हमारा रास्ता बन्द हो जावेगा आगे प्रगति करने का ।

इससे मेरा इशारा इस बात की ओर है कि आज देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है अगर इसके बारे में अभी से हमने सोचना और इसके लिये कारगर उपाय ढूंढना शुरू नहीं किया तो मेरा यह निश्चित मानना है कि जो प्रगति आज करते जा रहे हैं वह कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि वह प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है और एक तरह से इस प्रगति की हमारी सारी मेहनत इस तरह की हो जावेगी जिस तरह एक आदमी बड़ी तेज स्पीड से भाग रहा है और भागते भागते दस साल के बाद वह यह देखे कि मैं भागते भागते पहुंचा कहां हूं। मैंने तो जहां से भागना शुरू किया था वहीं खड़ा

(श्री चन्दनमल वैद)

हूं। मैं समझता हूं कि वही स्थिति सारे भारत की और हमारे इस राजस्थान प्रदेश की भी होने वाली है। मैं इस बात को आंकड़ों से स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य यह है कि देश में हम उत्पादन बढ़ावें, साथ ही बेरोजगारी को मिटावें और लोगों का लिविंग स्टेन्डर्ड ऊंचा करें। ये जो तीन बातें हमने इनके उद्देश्य के रूप में मान रखी हैं उनके लिये अब हम देखें कि उनको कहां तक हमने हासिल किया है।

हमने उत्पादन बहुत बढ़ाया है और बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया है। ये सब बातें हुई लेकिन उसके बावजूद भी आज जो हमारी जनता का लिविंग का स्टेन्डर्ड है वह क्यों नहीं बढ़ा? आज फिर भी हमें अमेरिका या दूसरे देशों से अन्न मंगाना पड़ रहा है। हम हर पंचवर्षीय योजना में लाखों और करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं और उसके बाद में भी यह कहना पड़ता है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में लोगों को रोजगार नहीं मिल सका; इस योजना में भी कई लोग ऐसे रह जायेंगे कि जिनको एम्प्लॉयमेन्ट नहीं मिल पायेगा। इसको हम बैकलाग ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सन् ४७ में जब हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ तो हम ४० करोड़ आदमी थे और करीब ८ करोड़ हमारे भाई अलग होकर पाकिस्तान में चले गए। लेकिन १० साल के अन्दर हमने दुनिया को दिखा दिया कि ८ करोड़ चले गये तो क्या हमारे यहां ८ करोड़ और पैदा हो गए और सन् ५७ में हमारे हिन्दुस्तान में फिर ४० करोड़ की आबादी हो गई। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस शताब्दी के समाप्त होने तक हममें से बहुत से माननीय सदस्य जिन्दा रहेंगे और उस समय तक आज हमारी जितनी आबादी है उससे भी दुगुनी हो जाने वाली है। आज हमारी आबादी ४० करोड़ की है और इस शताब्दी के अंत तक हमारे सारे हिन्दुस्तान की आबादी ६० करोड़ या ८५ करोड़ हो जाने वाली है। इसलिए अब हमें यह सोचना है कि इन सारी चीजों का क्या इलाज है और इतनी बढ़ी हुई आबादी को हम एम्प्लॉयमेंट कैसे दे पायेंगे? एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह अन्दाजा लगाया गया था कि ८० लाख लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। हम ८० लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके और ऐसा अनुमान है कि हम ६५ लाख लोगों को ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे सके और करीब १५ या २० लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी हम इतने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके। ऐसा हम सोच रहे थे कि

(१. १०. म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

८० लाख लोगों को हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे लेकिन, उसके बावजूद भी प्लानिंग कमीशन का भी सोचना है कि जिन लोगों ने आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर किया वहां २० लाख लोग रह जायेंगे कि जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकेगा। तीसरी योजना के बारे में ऐसा है

Page No.52

(श्री चन्दनमल वैद)

कि हम अन्दाजा लगाते हैं कि १४० लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें लेकिन उसमें से १० लाख लोग ऐसे रह जायेंगे कि जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह से कुछ लोग अनएम्प्लॉयड प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कुछ लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बचेंगे और इसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी बच रहेंगे। तो इस तरह से भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में करीब ५० लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और हर पंचवर्षीय योजना में हम इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इतने टैक्सों के लगाने के बाद और इतना उत्पादन बढ़ाने के बाद अगर अनएम्पलॉयड लोगों की संख्या बढ़ती जाती है तो फिर हमारी इन योजनाओं का मकसद क्या है ? हमारा सबसे पहला मकसद यह है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह सोचने की बात है कि इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम फूड प्रोडक्शन के आंकड़ों को देखें तो हमको मालूम होगा कि जहां सन् १९४९–५० में १०० मान कर चलें तो हमको मालूम होगा कि १९५५–५६ में ११५.३ फूड प्रोडक्शन होता है और १९६०–६१ में वह १३० पर आता है और इन दस सालों में जहां हमारा फूड प्रोडक्शन ३० प्रतिशत बढ़ा है वहां हमारी आबादी २२ पर्सेन्ट बढ़ी है। लेकिन अब लोग कह सकते हैं कि जब कि हमारा फूड प्रोडक्शन ३० प्रतिशत बढ़ा और आबादी २२ प्रतिशत बढ़ी है तो फिर घबराने की क्या बात है ? लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर और इशारा करना चाहता हूं और वह यह है कि जहां फूड प्रोडक्शन का मामला है वह हमारा मैथेमेटिकली बढ़ रहा है १,२,३ और ४ इस तरह से और जो हमारी पोपुलेशन है वह ज्योमेट्रीकली बढ़ रही है १,२,४ और ८ के हिसाब से। जो फिगर्स प्लानिंग कमीशन ने ड्राफ्ट प्लॉन इन्डिया का आउट किया है उसको देखने से साफ जाहिर है कि उन्होंने लिखा है कि १९५८–५९ में जहां फूड प्रोडक्शन १३० रहा और १९६०–६१ में १३१ रहा यानि एक प्रतिशत उसमें बढ़ोत्तरी हो सकेगी वहां २ साल में हमारी आबादी ४ पर्सेंट बढ़ जायेगी और आगे चलकर हमारी पापुलेशन का पर्सेन्टेज बढ़ता जायेगा और फूड प्रोडक्शन का पर्सेन्टेज कम होता जायेगा। इसी तरह से स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग के सिलसिले में भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा माना जाता है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे राष्ट्र की जो सम्पत्ति है यानि जो राष्ट्र का लिविंग स्टेन्डर्ड है वह ४२ प्रतिशत बढ़ा है और हर आदमी की आमदनी २० प्रतिशत बढ़ी है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जहां हमारे राष्ट्र की आमदनी ४२ प्रतिशत बढ़ी है वहां इन १० वर्षों में जो जीवन-निर्वाह का खर्चा है वह ५० प्रतिशत बढ़ गया है। तो हमें इस बात की तरफ भी बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि जहा हमारी आमदनी ४२ प्रतिशत बढ़ी है उसके साथ ही साथ हमारा जो खर्चा है वह भी ५० प्रतिशत बढ़ गया है। तो हमें आमदनी और उत्पादन के बढ़ाने के साथ ही साथ इस बात को भी बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये कि जो प्राइस लेवल है,

Page No.53

(श्री चन्दनमल वैद)

जो कीमतें हैं वे भी रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करने चाहिये। यह कोई बात नहीं हुई कि १० साल में एक तरफ तो हमारी कीमतें ५० प्रतिशत बढ़ जायें और हमारी आमदनी ४० प्रतिशत ही बढ़े तो इससे तो कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। जहां कि प्लानिंग कमीशन ने लिखा है कि अगर प्राईसेज़ को वही मान लिया जाये कि जो ५१ में थीं तो हमारी आमदनी ४२ प्रतिशत बढ़ी है तो प्राईसेज़ तो कॉन्स्टेन्ट नहीं हैं। खुद प्लानिंग कमीशन इस बात को मानता है कि पिछले दस सालों में जो प्राइस लेवल है पिछले पांच सालों में सेकिंड फाइव इयर प्लॉन के समाप्त होने के और थर्ड फाइव ईयर प्लॉन के चौथे साल के अन्त तक प्राइस लेवल २० प्रतिशत बढ़ गई तो जहां ४ साल में प्राइस लेवल २० प्रतिशत बढ़ गई और दस सालों में प्राइस लेवल ५० प्रतिशत बढ़ गई तो ४० प्रतिशत केवल हमारी आमदनी बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही गंभीर बात है। हम जहां समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं उसमें निश्चित बात है कि बहुत से जो उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण होगा और बहुत से लोग जो उनके अन्दर होंगे उन लोगों की आमदनी फिक्सड होगी तो एक फिक्सड आमदनी वाले लोगों के लिए रोजाना प्राईसेज़ बढ़ती हैं तो उनको बहुत मुश्किल हो जायेगी, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा और वह है पॉवर का उत्पादन। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह फरमाया था कि पॉवर का उत्पादन राजस्थान में काफी होने वाला है और उस सिलसिले में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी का भी हवाला दिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें भी शायद तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं तो चौथी या पांचवी पंचवर्षीय योजना में काफी पॉवर मिलने वाली है। पॉवर के बारे में बहुत से लोग जिक्र करते हैं। मारवाड़ी या राजस्थानी सारे हिन्दुस्तान में और बाहर दुनियां में उद्योगपति होने के कारण मशहूर हैं लेकिन वह राजस्थान में नहीं आते हैं। मेरी स्वयं की बहुत से लोगों से बातचीत हुई है। मैं कह सकता हूं कि उनका राजस्थान में नहीं आने का कारण अगर मुख्य रूप से कोई हो सकता है तो वह यह है कि यहां पॉवर की कमी है। वह महसूस करते हैं कि आज वह जमाना नहीं है कि केवल मैन पॉवर से ही उद्योग चलाये जायें। बड़े बड़े उद्योग आज विद्युत शक्ति से चलते हैं। यही कारण है कि राजस्थान में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते हैं। जब तक हम उनको पॉवर नहीं देंगे तब तक कोई भी हमारे यहां उद्योग नहीं लगायेगा। पॉवर के मामले में निस्संकोच कह सकता हूं कि हमारी सरकार इसके अन्दर बहुत हद तक नाकामयाब रही है। इसको मैं बहुत डिटेलवार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो पॉवर भाखरा से और उसका जो दूसरा पॉवर गंगवाल स्टेशन से हमको सन् ५४–५५ में मिल जाना चाहिये था वह सन् ६० के मार्च महीने में मिला है। इस तरह से पांच साल पंजाब से पॉवर लेने में हम पीछे रह गये हैं। पांच साल के लिए लेग बिहाइन्ड कर गए हैं, राजस्थान को पांच

(श्री चन्दनमल वैद)

साल के लिए लेग बिहाइन्ड करने की आखिर जिम्मेदारी किसकी है ? जब पंजाब से पॉवर लेने में हम पांच साल लेग बिहाइन्ड कर गए तो हिन्दुस्तान में हमेशा के लिए हम इस काम में पीछे रह जायेंगे। और इतना ही नहीं; अब दूसरी बार मध्य-प्रदेश से पॉवर लेने में भी हम पीछे रह गए हैं क्योंकि एक पॉवर स्टेशन गांधी-सागर डेम से शुरू हुआ और उसके पीछे दो पॉवर स्टेशन्स भी शुरू होने वाले हैं। उन दो स्टेशनों से भी हम पॉवर ले सकेंगे, मुझे इसमें संदेह है। हम मध्य प्रदेश से भी पॉवर लेने में पीछे रह जानेवाले हैं और इस तरह हम हमेशा के लिये पीछे रह जायेंगे। हिन्दुस्तान की दो स्टेटों से हम पॉवर के हिस्सेदार बने, भाखरा नांगल पंजाब से और दूसरी मध्य प्रदेश से। हम दो जगहों के हिस्सेदार हैं लेकिन हमने देखा कि हम दोनों जगह ही पीछे रह गये, हम पंजाब के साथ हिस्सा लेने में भी पीछे रहे और दूसरी बार मध्य प्रदेश से भी अपना हिस्सा लेने में पीछे रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम इतने पीछे रह जायें, सिवाय इसके कि हम कॉम्पीटेन्ट नहीं हैं, हम एफीशियेन्ट नहीं हैं कि अपना हिस्सा वक्त पर ले सकें। यह कहा जा सकता है कि हमारे पास टावर्स नहीं हैं या दूसरे औजार नहीं हैं, बहाने तो बहुत बनाए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि हमारे पास टावर्स नहीं हैं, स्विच नहीं हैं, हमारे पास ट्रान्समीटर नहीं हैं। और भी मशीनों के नाम लिए जा सकते हैं जिनके नाम बहुत सी साधारण जनता तो जानती तक नहीं है। सैकड़ों बहाने बनाए जा सकते हैं लेकिन सही बात यह है कि "नाच न आवे आंगन टेढ़ा"; नाचना तो खुद को आता नहीं है और कह दे कि आंगन टेढ़ा है। जब मध्य प्रदेश और पंजाब अपना सारा काम एक वक्त में पूरा कर सकते हैं, समय पर पॉवर ले सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान ही पीछे रहे।

भाखरा नांगल के दो हिस्सेदार थे; एक पंजाब और दूसरा राजस्थान और उसके बाद जो रिज़र्व पॉवर है वह दिल्ली को मिलनेवाला था। जो दो बड़े बड़े हिस्सेदार थे उनमें पंजाब ने तो अपना पॉवर ले लिया और रिज़र्व में से भी दिल्ली ने पॉवर ले लिया और हम पीछे रह गए। जो खास जीमनेवाले थे वे तो रह गए और कुत्ते और भिखारी जिनको सबके जीमने के बाद हिस्सा मिलना चाहिये वे पहले ही हिस्सा ले गए। यही स्थिति हमारी मध्य प्रदेश के साथ भी होने वाली है। मध्यप्रदेश अपने टॉवर्स लगा ही चुका है। जो पचास प्रतिशत हिस्सा हमको लेना है उसके लिए भी हमारी तैयारी नहीं है और इसमें भी हम पीछे रह जाने-वाले हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यौरेवार यह बताना चाहता हूं कि पॉवर्स में हमारी स्थिति क्या है ? यह हमको बताया गया है कि सेकिंड प्लॉन के बिगिनिंग में हमारी योजना ३४,६०० किलोवाट पॉवर की थी और सेकिंड प्लॉन में हमको ६०,५८२ किलोवाट पॉवर पैदा करनी है। जो हमारी सेकिंड प्लान की योजना थी कि ६०,५८२ किलोवाट पॉवर हम पैदा कर लेंगे उसका व्यौरा भी इस प्रकार दिया गया है वह यह है कि २८१४५ किलोवाट थरमल से यानी

(श्री चन्दनमल वैद)

डीज़ल से, १६,४३७ किलोवाट भाखरा से और ४६,००० किलोवाट चम्बल से प्राप्त करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि थरमल और डीज़ल इन दोनों तरीकों से हमको जो बिजली मिलनेवाली थी उसमें कुल ११,००० किलोवाट ही पैदा कर सकेंगे यानी इतनी बिजली के लिए ही इंजिन वगैरह लगा सकेंगे। आज साढ़े चार साल सेकिंड प्लॉन के समाप्त होने जा रहे हैं। हमको बताया गया है कि योजना समाप्त होते २ बाकी पॉवर का इंस्टालेशन हो जायेगा। यह हो जायेगा तो ऐसा टर्म है जिसके लिए कहा जाता है कि प्रयत्न तो बहुत किए गए लेकिन पूरा नहीं हो सका। आज हमें आश्वासन दिया जाता है कि बाकी काम पूरा हो जायेगा और आगे जाकर कह देंगे कि फलाना पुर्जा जो कि अमेरिका के पुराने शहर में पुरानी फैक्ट्री में आने वाला था वह नहीं आया और इसलिए ही यह काम पूरा नहीं हो सका। तो जहां २८,१४५ किलोवाट बिजली हमको थरमल के सोर्सेज़ से मिलने वाली थी उसकी जगह कुल ११,००० किलोवाट बिजली ही हम प्राप्त कर सकेंगे। भाखरा से जहां हमको १६,४३७ किलोवाट बिजली प्राप्त करनी थी तो उसके विषय में तो फिगर नहीं बताए गए हैं, इसलिए मैं केवल किलोवाट ही यूज़ कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस एरिया से आया हुआ हूँ जिस एरिया में भी भाखरा की पॉवर आई है। मैं जानता हूँ कि वहां की पॉवर की स्थिति क्या है ! भाखरा की पॉवर चुरू जिले में आई लेकिन उसके पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले भी एक ही बल्ब जलता था और आज भी एक भी बल्ब ज्यादा नहीं जला है, एक भी पंखा भाखरा की पॉवर से ज्यादा नहीं चला है, एक भी कुंए में ड्रिंकिंग वाटर निकालने के लिए भाखरा की ओर से कनेक्शन नहीं दिया गया है और इन्डस्ट्रीज़ को पॉवर देने की बात तो दूर की है; रोजमर्रा की जरूरत के लिए जो पॉवर चाहिये वह भी नहीं दिया जा रहा है। जब उनसे शिकायत की जाती है तो जवाब दे दिया जाता है कि पॉवर पोज़ीशन टाइट है अभी तक ईज़ी नहीं हुई है और जो वाल्टेज हंड्रेड फिफ्टी, सिक्सटी, सेवन्टी पर पहले चलता था आज भी वही आ रहा है और पहले जो दिन में १५-२० ब्रेक डाउन होते थे आज भी उसी तरह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर भाखरा से कितनी बिजली आई हमारे पास और कितने गांवों को वह दी गई। जब बार बार शिकायत करते हैं तो यह कह दिया जाता है कि हमारे ट्रांसफोर्मर्स पुराने हैं, या कह दिया जाता है कि हमारे पास बिजली के खम्भे नहीं हैं या बिजली के तार नहीं हैं। इस तरह से तो अनेकों बहाने बनाए जा सकते हैं। मैं भी सौ, दो सौ बहाने बना सकता हूं लेकिन इससे समस्या का हल नहीं हो जाता है। चूरू जिले में जहां कि भाखरा की पॉवर आई है कोई एक बल्ब नया नहीं लगा, कोई पंखा नहीं चला, किसी कुएं में से पानी निकालने के लिए भाखरा की पॉवर से कनेक्शन नहीं दिया गया; यह बिल्कुल सही बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि तीसरी उपलब्धि

(श्री चन्दनमल वैद)

पॉवर की होने वाली है चम्बल से। लेकिन इसके फिगर्स तो बिल्कुल ही निल हैं। इस तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो ६०,५८२ किलोवाट बिजली पैदा करने का टार्गेट था, जो हमारा यह लक्ष्य था कि हम ६०,५८२ किलोवाट पॉवर प्राप्त कर लेंगे, उसके अगेन्स्ट में मुश्किल से पन्द्रह-बीस हजार किलोवाट बिजली प्राप्त कर सके हैं। भाखरा का फिगर मेरे पास नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी बतावें कि भाखरा से कितनी बिजली ले सकेंगे ? हमारे टार्गेट तो बहुत बड़े थे लेकिन हमको पॉवर ज्यादा नहीं मिलने वाली है, तो इससे हमारा उत्पादन भी नहीं बढ़नेवाला है। हमारी जो योजनाएं थीं कि एग्रीकल्चर पर जो बहुत बोझा बढ़ गया है उसको हटावेंगे, इन्डस्ट्रीज़ कायम करके जो मैन पॉवर एग्रीकल्चर पर हावी है उसको इन्डस्ट्रीज़ में लगावेंगे, तो यह सम्भावना भी नहीं रही है। मैं श्री पी. के. चौधरी से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हमारे फिगर बैकवर्ड रहे हैं, फॉर्वर्ड फिर नहीं हो सकते।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है उस सिलसिले में भी मैं इशारा करना चाहता हूं। हमको यह कहा जा रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३,४०,००० किलोवाट पॉवर हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं नहीं कह सकता कि हम यह पॉवर ले सकेंगे या नहीं। लेकिन जो हमारी पीछे की उपलब्धियां हैं वे हमको बताती हैं कि हम इस काम में पीछे रहे हैं और इस वक्त पर माननीय मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद हैं मैं उनसे इस मौके पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे पर्सनली देखें कि आखिर यह गड़बड़ क्या है, ? क्यों हम लेग बिहाइन्ड करते हैं ? हमने यह आशा की थी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन जाने से इसमें सुधार होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन जाने से भी कोई सुधार नहीं हुआ है। बोर्ड बनने से पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। वही डाल के तीन पात हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यह रोग क्या है ? हमें इसका निदान करना ही चाहिए। आखिर पॉवर लेने में जो हम पीछे रहते हैं; जो राजस्थान पॉवर लेने में पीछे रह रहा है तो उसका कारण क्या है ? उस कारण का निदान होना चाहिए। इस बारे में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पॉवर या तो कोयले से पैदा किया जाता है या डिज़िल से या फिर पानी से पैदा किया जाता है और अब एक नया तरीका ऑटोमिक इनर्जी का भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देश में कोयले की कमी है और अगर आज हम स्टीम से बिजली पैदा करना चाहेंगे तो हमें कोयले की आवश्यकता होगी। हमारे देश में बहुतायत नहीं है और फिर राजस्थान में तो कोयला मिलता भी नहीं है। बंगाल, बिहार से कोयला मंगाना पड़ता है और फिर बंगाल बिहार से कोयला मिल भी जाये तो फिर ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है। उसके बाद जो पानी से बिजली पैदा की जा सकती है तो पानी से बिजली या तो उदयपुर या कोटा या पंजाब से मिलनेवाले पानी से बिजली पैदा हो सकती है। लेकिन एक तरीका और भी है और वह है लिग्नाइट का। लिग्नाइट भी इस काम के योग्य है। पलाना का जो लिगनाइट है वह इस काम के योग्य है। वह रेल के एन्जिन में नहीं

(श्री चन्दनमल वैद)

जल सकता है, लेकिन कम से कम बिजली उससे पैदा हो सकती है और बीकानेर में उससे बिजली पैदा की जाती रही है और अब भी बिजली पैदा होनी चाहिए। लेकिन पलाना कोल माइन्स का न मालूम क्या दुर्भाग्य रहा, वह शनिश्चर की दशा से ग्रसित रही है कि कोई न कोई रोक उसकी प्रगति को रोकती रही है। पहले फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर की कमी थी जिसकी वजह से १५०० टन से ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकते थे। फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर को नियुक्त करने में हमको ५ साल लगे। जब फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर नियुक्त हो गया और हम १५०० टन का उत्पादन करने के लायक घोषित कर दिये गये तो उसके बाद हमें जो सेकिण्ड फाइव इयर प्लान की किताब मिली है उसमें देखते है कि २ करोड़ रुपये पलाना कोल माइन्स पर ओपन कास्ट माइन्स को करने के लिए खर्च किये जायेंगे। लेकिन बार बार इस बारे में तवज्जह दिलाने के बावजूद भी कोई पैसा वहां पर इस काम के लिए खर्च नहीं हुआ और इस थर्ड फाइव इयर प्लान में यह पढ़ने को मिला है कि वहां पर पलाना के पास में एक जेनेरेटिंग सेट लगाया जायगा जिससे बिजली उत्पन्न की जायगी और काफी पैसा खर्च किया जायगा ! मैं कहता हूं कि शनिश्चर की दशा साढ़े सात साल की होती है। वे अब ७॥ साल संभवत: पूरे होने आये हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : इसका एसेसमेंट कैसे किया जा सकता है, शनिश्चर की दशा का। After all the Hon'ble Minister shall have to reply.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : शनिश्चर के पुजारी होंगे।

श्री चन्दनमल वैद : पुजारी तो नहीं हूं लेकिन रेफरेन्स जरूर दे रहा हूं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि जब पॉवर की हमारे पास कमी है और पॉवर का एक फर्स्ट क्लास सोर्स पॉवर पैदा करने का है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। अगर उपयोग नहीं होता है तो लोगों के मन में भावना पैदा होती है कि क्या ऐसा कारण है कि जिससे इस माइन की उन्नति नहीं हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं ज्यादा नहीं कह कर केवल एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अक्सर ऐसा होता है कि जब पंचवर्षीय योजना बनाते हैं तो बहुत सी बातों का, सारे जिलों का दृष्टिकोण रखते हुए उसमें उनका समावेश कर दिया जाता है जिससे सब तरह के लोग, सब जिलों के लोग, सब निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों और सब डिवीज़न के लोगों को संतोष हो जाये कि हमारे जिले की, हमारे डिवीज़न की सर्वांगीण उन्नति के सिलसिले में सारी बातों को इसमें रख दिया गया है। हमें कोई शिकायत नहीं हैं। लेकिन जब इम्प्लीमेन्टेशन का सवाल आता है तो

(श्री चन्दनमल वैद)

न मालूम क्या होता है कि या तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट, या स्थानीय कर्मचारी या मंत्री महोदय कुछ ऐसा इन्ट्रेस्ट लेते हैं, कुछ खास चीज़ों के लिए और खास जगहों के लिए कि उन कामों को छोड़ दिया जाता है और किसी खास जगह के ही काम लिये जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचवर्षीय योजना की हमेशा उन्नति की देखभाल करने के लिए विधान सभा की एक कमेटी होनी चाहिए। जिस तरीके से कि हम विधान सभा में जो खर्च पास करते हैं उस खर्चे की देख-रेख करने के लिए पी० ए० सी० है और जो कानून पास करते हैं उन कानूनों के अन्दर जो रूल्स बनते हैं, उन रूल्स की देख भाल करने के लिए सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन्स कमेटी है और दूसरे कामों की देखरेख करने के लिए विधान सभा की अन्य कमेटियां हैं, उसी तरह से पंचवर्षीय योजना में जिन कामों का समावेश किया गया है, उल्लेख किया गया है, उन कामों की पूर्ण रूप से सब तरीके से समीचीन उन्नति हो रही है, चारों तरफ एक तरह से काम हो रहा है या नहीं, उसकी देखभाल करने के लिए विधान सभा की एक हाई पॉवर कमेटी होनी चाहिए जो हमेशा इस बात की देख-भाल करती रहे कि जिन चीजों का उल्लेख किया गया है उन चीजों पर काम हो रहा है या नहीं। मैं एक उदाहरण देकर साबित करना चाहता हूं कि प्लान फ्रेम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में भेजा गया है उसके पेज ११४ पर यह लिखा हुआ है कि :

"at the end of the Second Plan period Rajasthan will have 2582 miles roads as follows." यह किताब, माननीय उपाध्यक्ष, मैं साफ कहना चाहता हूं कि १५ जनवरी, सन् ६० को छपी हुई है। इस पर दस्तखत हुए हैं। मार्च या अप्रेल के महीने में हमको यह मिली होगी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के करीब २ साढ़े चार साल या चार साल के गुजर जाने के बाद में यह लिखा गया है तो इसमें एज़ फोलोज़ में १३ सड़कों के नाम दिये गये हैं। उनमें एक सड़क है बीकानेर से सरदारशहर तारानगर बोर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब यह होता है कि यह लिखा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद यह सड़क पूरी हो जायेगी और मैं यह बताना चाहता हूँ कि सरदार शहर से तारानगर पहले १० साल बनी हुई सड़क है। बीकानेर से सरदार शहर १०० मील का रास्ता है। बीकानेर से तारानगर पहले एक सड़क बनी हुई है और बीकानेर से सरदार-शहर, जहां की सड़क नहीं बनी है वहां एक कंकड़ भी नहीं डाला गया है। सरदार शहर से तारानगर वह सड़क १० साल पहले बनी हुई थी, उसकी मरम्मत के लिए एक पैसे का काम नहीं हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक पैसे का काम नहीं हुआ है और चार साल बीतने के बाद एडीशनल चीफ सेक्रेटरी या प्लानिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अगर यह लिखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद बीकानेर, सरदार शहर, तारानगर जो सड़क है वह स्टेट हाई वे होगी और बन जायगी जब कि मैं समझता हूं कि उस सड़क पर एक कंकड़ भी नहीं गिरा है, एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है। यह बतलाता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट कितना सजग है; इस बात की तरफ की सारी स्टेट में जो काम

(श्री चन्दनमल वैद)

हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था वह पूरा हो और एक तरफ जब उनकी मन्शा नहीं हो तो उसको काट दिया जाय, लेकिन हमारे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट या जो मिनिस्टर कन्सर्न्ड हैं वे न मालूम कहां से इन्ट्रेस्ट लेकर उन चीजों को निकाल देते हैं और उनकी जगह दूसरे काम करवाते हैं क्योंकि मैं इस बात को साधिकार कह सकता हूं कि इस सड़क की जगह चुरू और बीकानेर जिलों मे कोई दूसरी सड़क नहीं बनी है। यह कहा जाता है कि सेकिण्ड फाइव इयर प्लान जो कि १०५ करोड़ का था उसमें करीब करीब १०० करोड़ खर्च कर दिया गया यानि ६६ प्रतिशत के लगभग खर्च कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस सड़क पर जो ५०–६० लाख रुपया खर्च होने वाला था वह पता नहीं कहां गया। वह रुपया खर्च जरूर हुआ। अगर खर्च नहीं हुआ होता तो यह ६६ प्रतिशत का एवरेज नहीं आता। वह खर्च हुआ है। न मालूम कौन आदमी कहां पर इन्ट्रेस्टेड है ? इस वास्ते मेरा सुझाव है कि जो बजट पास करते हैं, उसकी देखरेख करने के लिए पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बनी हुई है और दूसरी बातों के लिए विधान सभा की कमेटियां बनी हुई हैं, उसी प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं भी जिस तरह से पास हुई हैं समीचीन उनका इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिए। इसको देखने के लिए विधान सभा की एक हाई पॉवर कमेटी होनी चाहिए जो कि बराबर हर साल विधान सभा में रिपोर्ट पेश करेगी कि जैसा प्लान पास हुआ था उसी तरीके से प्लान का सारा काम हो रहा है, उसका इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव के साथ फिर राज्य सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत एफिकेशस प्लान बनाया है और मैं आशा रखता हूं कि पूरी सजगता और पूरी तैयारी के साथ प्लान को पूरा करने के लिए वे प्रयत्न करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जो विचार हो रहा है उस पर कई सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और उन विचारों में कोई अधिकांश चर्चा यही रही कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के क्षेत्रों को जिस प्रकार से सहायता देनी चाहिए थी वैसी नहीं दी और उस ओर भी उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। मैं उन्हीं बातों को वापिस दोहराना नहीं चाहता, परन्तु खासकर मैं राजस्थान की जो हमारी समस्याएं हैं और उसके साथ ही साथ हमारी जो प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना है और उसके साथ जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हम आज बनाने जा रहे हैं उसे कहां तक कामयाब बना सकते हैं, और उसके साथ साथ उसमें आगे जो खामियां रही हैं उनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ताकि राजस्थान का भविष्य उज्जवल कर सकें, उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

सही मायने में किसी भी योजना को देखने के पहले यह स्वाभाविक होता है कि अब तक जो योजना हमारे यहां रही है उस योजना से क्या लाभ मिला ? राजस्थान के मुख्य मंत्री ने खास करके जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने रखी, उसमें पहली और दूसरी योजना का सिंहावलोकन किया

(श्री मुरलीधर व्यास)

और उनमें कहां तक सफलता प्राप्त की, इस पर प्रकाश डाला। मैं यह समझता हूं कि किसी योजना की सफलता और असफलता का आखिर मापदण्ड क्या है ? जहां तक आंकड़ों का आधार है और डेटा या स्टेटिस्टिक्स के आधार पर हम सोचते हैं, उस पर यह कहा जा सकता है कि जिस योजना में जितना रुपया खर्च किया है इस योजना से हमारा पर केपिटा, हमारे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की औसतन आमदनी कितनी बढ़ी, हमारे राजस्थान की आमदनी कितनी रही, इस आधार पर हम इन चीजों को तोल सकते हैं। यह जो आधार है, यह इस प्रकार का है, इसके संबंध में जब तक सफल नहीं होते तब तक इसके बारे में सही रूप से नहीं कह सकते।

दूसरा आधार यदि कुछ न हो तो हम यह देख सकते हैं कि राजस्थान में जो व्यक्ति हैं, जो राजस्थान की आबादी है, उससे और राजस्थान के हर घर के चूल्हे से अन्दाज लगा सकते है कि उसकी आर्थिक स्थिति या माली हालत किस तरह से अच्छी हुई है। यह तरीका है जो व्यवहारिक है। लेकिन आंकड़ों के आधार पर, जो सरकार ने दिये हैं, खास करके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह बताया गया है कि २६४ रुपये पर केपिटा इन्कम होगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी पर केपिटा इन्कम क्या थी और दूसरी में पर केपिटा इन्कम हुई किस साल तक और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पर केपिटा इन्कम क्या होगी ? इस बारे में राजस्थान में छपी हुई एक किताब है "राजस्थान आज और कल", उसके अंदर कुछ बातें दी गई हैं। राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स के आधार पर यह बात लिखी है कि राजस्थान की पहली पंचवर्षीय योजना में....

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर व्यास, मैं यह जानना चाहूंगा कि किताब किस ऑथर की है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह पुस्तक सार्वजनिक संपर्क कार्यालय, जयपुर की ओर से १५ अगस्त, ६० को प्रकाशित हुई है। इसमें प्रति व्यक्ति आय २३२ रुपये दी है, ३१ मार्च, ५६ में २८२ रुपये की आय बता दी है। जब कि आज हमारे मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि हमारे यहां की पर केपिटा इन्कम २६४ रुपये है। यह बात वे कहते हैं सन् ६० में और हमारी सरकार के आंकड़े सन् ५६ में बताते हैं कि पर केपिटा इन्कम २८२ रुपये हो चुकी है और साथ ही साथ सन् ६१ में क्या होगी, इस बारे में भी लिखते हैं। यह आय २८२ रुपये प्रति व्यक्ति बढ़ गई थी सन् ५६ में और दूसरी योजना के अंत तक यानि ३१ मार्च, ६१ तक ३३२ रुपये तक बढ़ जाने की निश्चित संभावना है। संभावना को जाने दीजिये। जब सन् ५६ के अगस्त में आमदनी २८२ रुपये हो जाती है, तो सन् ५६ के बाद में हमने कहां तक तरक्की की है ? एक ओर तो कहा जाता है कि हमने अनाज उत्पादन ड्योढ़ा या दुगना कर दिया है, दूसरी ओर आमदनी ज्यादा हो गई है और तीसरी ओर कहते हैं कि हमारी औसत आमदनी २६४ रुपये है। यह समझ में नहीं आता कि ये आंकड़े किस प्रकार से बनाये जाते हैं। या तो यह माना जाय कि सरकार द्वारा जो भ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

किताबें अब तक प्रकाशित की गई हैं वे गलत आधार पर की गई हैं। इसके अंतिम पेज २६१ पर लिखते है कि किस आधार पर प्रकाशित की गई हैं, बेसिक स्टेटिस्टिक्स १९६० के आधार पर ये आंकड़े लिये हैं और प्रकाशित किये हैं। जहां तक इन आंकड़ों के आधार के बारे में सोचते हैं तो या तो यह माना जाय कि जो सूचना अंक पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट द्वारा दिये जाते हैं, जिस पर हम इतना रुपया खर्च करते हैं, वे गलत आंकड़े होते हैं या यह माना जाय कि आंकड़ों के बारे में मूल भूत आधार मन-माने ढंग से ले लेते हैं। तो मैं यह सोचता हूँ कि जो बुनियाद होती है सफलता असफलता को जांचने की, उस संबंध में जो आंकड़े होते हैं वे इतने संदिग्ध होते हैं कि कह नहीं सकते। तो योजना के बारे में किस प्रकार से विचार कर सकते हैं? मैं और अधिक नहीं कह कर इतना कहना चाहता हूं कि २६४ रुपये भी प्रति व्यक्ति राज्य की आमदनी मानलें और इस आधार पर भी देखें तो ठीक है, २६४ रुपये हैं तो हमने योजना पर जो खर्चा किया वह किस लक्ष्य को लेकर किया? उसमें कितनी कामयाबी हुई? आखिर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं उसमें कहां तक कामयाबी होती है, उस पर नजर रखनी चाहिये।

यदि २६४ रुपये पर कैपिटा इन्कम के आधार पर देखें और राजस्थान की कुल आमदनी को ठीक ठीक तरीके से बांटें तो एक परिवार कम से कम ५ व्यक्तियों का मानें तो उस परिवार को कितने रुपये मिलेंगे? लगभग १४०० रुपये प्रति ५ व्यक्तियों के परिवार को मिल सकते हैं, इस आधार पर हमें सोचना है। हमने जो योजना बनाई उसका लक्ष्य समाजवादी था। समाजवादी समाज का निर्माण करेंगे, गरीबों की हालत ठीक करेंगे, इस मूलभूत आधार पर योजना शुरू की थी। इस आधार पर भी सोचना चाहिये। केन्द्रीय पार्लियामेंट में इस पर बहस चली और यह सवाल आया कि हमारा उत्पादन बढ़ा, आमदनी बढ़ी, औसत आमदनी बढ़ी। यह सब कुछ होते हुए भी गरीब क्यों अब भी गरीब रह रहा है; इस आधार पर छानबीन होनी चाहिये, यदि राजस्थान में १ करोड़ ६० लाख आदमियों की आबादी मानते हैं और उन सब की आमदनी प्रति व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो औसत ५ व्यक्तियों के परिवार की आमदनी लगभग १३००,१४०० रुपये होनी चाहिये। अब इस आधार पर देखा जाय कि क्या राजस्थान में सभी लोगों को सालाना प्रति परिवार १३००,१४०० रुपये मिलते हैं? यदि नहीं मिलता तो आखिर यह आमदनी किसके पास गई? आखिर एक करोड़ आदमी ऐसे होंगे जिनमें किसान होंगे, मजदूर होंगे, चपरासी और जमादार होंगे जिनमें से किसी को वेतन के ३० रुपये मिलते होंगे, किसी को ४० रुपये मिलते होंगे, किसी को ५० या ६० रुपये मिलते होंगे। उन सब का हिसाब लगाया जाय तो मालूम होगा कि करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको १४०० रुपये प्रति ५ आदमियों के परिवार को नहीं मिलते। हमारा लक्ष्य यह था कि विषमता दूर हो। लेकिन हो यह रहा है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास एक एकड़ भूमि भी पूरी नहीं है, ऐसे साढ़े चार लाख किसान हैं और बहुतसों के पास एक एकड़ से भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

कम भूमि है। इस तरह से एक करोड़ की आबादी ऐसी है जो ३००,४०० रुपये सालाना आमदनी में अपनी जिन्दगी चलाते हैं। और आप १४०० रुपये एक परिवार की औसत आमदनी मानते हैं तो यह रकम किस के पास जाती है। आखिर आप समाजवादी समाज बनाने की योजना बनाते हैं तो विषमता दूर करने के लिये, समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिये ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे वास्तव में विषमता दूर हो सके। लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे हम विषमता को दूर कर सकें। हम कह सकते हैं कि हमारे यहां अनाज का उत्पादन बढ़ा। दूसरे मामलों में भी हमने तरक्की की। तीसरे मामले में जहां हम विषमता दूर करना चाहते हैं, उसमें हम उसी स्थान पर हैं, कोई तरक्की नहीं की। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जैसा कहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो उत्पादन होगा वह किस प्रकार से गरीबों के पास पहुँच सकता है, उनकी हालत कैसे ठीक हो सकती है, इस पर विचार करना है ? मैं आशा करता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे। आज जिस स्थान पर है उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। आज जो जमीन का मसला है, सीलिंग का मसला है उसको दबा दिया, किसानों को भूमि नहीं मिली। अब भी यदि यह तरीका रहा कि जमीन नीलाम करके बेचेंगे तो वह गरीबों को नहीं मिलेगी, पैसे वालों के पास जायगी और गरीब गरीब ही बना रहेगा। निश्चित रूप से आपको और कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। दूसरी बात आपकी इन्डस्ट्रीज़ के बारे में और तीसरी बात वेतन–स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में सोचनी पड़ेगी। जिस आदमी को ३० रुपये मिलते हैं या ४० या ५० रुपये मिलते हैं या १०० रुपये से कम पाने वाले हैं उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिये हमारे पास क्या योजना है ? मैं कहना चाहता हूं कि जो योजना है उसके आधार पर जो टैक्स लगेंगे वे १६५० करोड़ रुपयों के टैक्स लगेंगे, उसका असर जरूर होगा। गरीबों का जीवन–स्तर इस प्रकार के ढांचे में ढाला जायगा तो वे संभल नहीं सकेंगे। अब उसको सम्भालने के लिए समाजवादी तरीके पर समाजवादी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, जिससे आप उसको सम्भाल सकें। वह आपने नहीं सम्भाला तो मैं समझता हूं कि योजना आप चाहें, एक नहीं, दो, तीन, कई योजनायें बन जायें, लेकिन जब तक मूलभूत नीति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से विषमता के अन्दर अन्तर नहीं होगा। मैं खास करके इस बारे में निवेदन करता हूं मंत्री महोदय को, कि जो नीचे गिरे हुए लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह तीसरी पंचवर्षीय योजना किसी रास्ते से उन लोगों की माली हालत को ठीक करेगी और उस बारे में विचार करेगी, परन्तु इसमें इसका कोई रास्ता नहीं बताया गया है।

अब मैं खास करके योजना के बारे में कुछ विचार रखना चाहता हूं। योजना के सम्बन्ध में खास करके एक नई बात पैदा हुई, राजस्थान नहर की बात क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर के लिए काफी रकम लगा दी है, अब प्रश्न आया कि स्टेट गवर्नमेंट खुद उसको सम्भाले और उस पर रकम लगाये। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में कुछ सम्मानीय सदस्यों की राय

(श्री मुरलीधर व्यास)

है कि राजस्थान सरकार को राजस्थान नहर योजना को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। मैं इस पक्ष का नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि इतनी बड़ी योजना है, उसे अगर हम समाप्त करने की बात कहते हैं और यह सोचते हैं कि वह रकम दूसरे तरीके से लगा कर हम राजस्थान का उत्पादन बढ़ायें, तो मैं उस बात का पक्षपाती हूं। यह राष्ट्रीय योजना है, इस योजना के सम्बन्ध में पंडित नेहरू ने हिन्दुस्तान में कई जगहों पर कहा कि एक राष्ट्रीय योजना राजस्थान नहर है और उसको वहां बना देने के बाद हिन्दुस्तान हरा भरा हो जायगा। पंतजी ने जब उसका उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय योजना है और इससे राष्ट्र को लाभ मिलेगा। मैं यहां तक कहता हूं कि इस योजना का पहले आम चुनाव के समय से लेकर इतना ज्यादा प्रचार किया गया और यह कहा गया कि यह योजना हमारे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा आधार है और हमारे राष्ट्र के उत्थान और उन्नति का यह आधार है। इस बात को कह कर आज यह कहें कि नहीं, इस मौके पर इसे छोड़ दिया जाय, मैं समझता हूँ, यह ठीक नहीं होगा। ठीक बात है, राजस्थान सरकार को चाहिए कि क्योंकि यह एक राष्ट्रीय योजना है, इसलिए इस सम्बन्ध में अपनी तरफ से केन्द्रीय सरकार को कहे। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार सम्माननीय सदस्य कहते हैं कि इस स्कीम को बन्द कर देना चाहिए, कतई ठीक नहीं है। मैं इस बारे में, मुख्य मंत्रीजी ने जो कल कहा था, उसका समर्थन करता हूं। मैं इस चीज को मानने वाला हूं कि राजस्थान नहर का काम चालू रहे, चाहे कुछ भी हो। आखिर इतना क्षेत्रीय दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि यदि राजस्थान में पूरा अनाज है, अनाज काफी है, अनाज की दृष्टि से राजस्थान सरप्लस है, हमें अनाज की जरूरत नहीं है, तो इस काम को हम बन्द कर दें। मैं कहता हूं कि राजस्थान की इकोनोमी, राजस्थान का आर्थिक विकास किस चीज पर आधारित है और उसके साथ ही साथ हमारे देश का भी विकास किस चीज पर आधारित है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा और यह सोच कर हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूँ कि इस मामले के सम्बन्ध में इतना कह देना चाहिए कि जो उत्पादन होगा, वह देश में दूसरी जगह काम में आ सकेगा। आखिर हर स्थान की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, इन्डस्ट्री के बारे में हम सोचें कि राजस्थान ज्यादा तादाद में इन्डस्ट्री की बात करे, तो उतनी तरक्की और कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, जितनी दूसरे प्रान्तों में, दूसरे क्षेत्रों में होती है, क्योंकि जो साधन वहां उपलब्ध हैं, वे यहां नहीं हैं। ऐसी हालत में राजस्थान में अगर कृषि उत्पादन बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि राजस्थान के हर व्यक्ति पर इसका असर होगा क्योंकि कृषि किसी भी राज्य की औसतन आमदनी बढ़ाने में कामयाब होती है। तो इस चीज को माना जाय कि इस योजना को न चालू रखा जाय, तो मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं। मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि राजस्थान नहर योजना एक राष्ट्रीय योजना है और राजस्थान के जीवन को, राजस्थान के आर्थिक जीवन को और राजस्थान के हर व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण होगी और इसलिए इस योजना को बहुत महत्व देना चाहिए।

अब जो दूसरा सवाल है, वह यह है कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज तक हमारी योजनायें रही हैं और उन योजनाओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, इन्डस्ट्रीज़ के बारे में, दूसरों के बारे में, मैं इसके बारे में थोड़े विचार रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी कुछ योजनायें खास करके राजस्थान की वस्तुस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। राजस्थान के अन्दर कम्युनिटी प्रोजक्ट का खर्चा है और वहां पर वह खर्चा किस तरीके से होता है। उस खर्चे के लिए ऊपर से प्लान आता है और पंचायत समिति, पंचायत और जिला परिषद् को उस आधार पर कहा जाता है कि तुम इस मद में इतना इतना पर्सेन्ट खर्च कर सकते हो। राज्य सरकार के पास वह प्लान आता है केन्द्रीय सरकार के पास से, और उसी प्रकार राज्य सरकार नीचे पंचायत, जिला परिषदों को भेजती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी खर्चा कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत होता है, उस पर पंचायत समिति अपनी राय देती हैं, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमने पंचायत समितियों की राय ली। उसके बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राय नहीं ली गई और ली गई तो इस तरीके से ली गई कि जो योजनायें भेजो गई और जो खर्चा बताया कि कितना कितना खर्चा करना है, कितना तुमको दिया, वह सारा अंग्रेजी में भेज दिया। मैं एक दफा अपनी पंचायत समिति की बैठक में गया, मैंने देखा कि कोई भी पंच नहीं समझता था कि क्या योजना है, किस प्रकार की बात है और इसी प्रकार सारे राजस्थान में हुआ। इस चीज को मैं मान लेता हूं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार है, वह नीचे से आना चाहिए, उस आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी है, मैं इसको नहीं मानता। वह योजना ऊपर से भेजी गई और वह भी अंग्रेजी में, जिसको कई लोग समझ नहीं सके। उसी प्रकार, मैं नहीं जानता, यह मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे कि कितनी पंचायत समितियों ने अपने प्लान बना कर भेजे, जिन्होंने अपने प्लान बनाये। आपने जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई, उसे आपने जिस तारीख को प्रारूप दिया, उस तारीख के पहले कितनी पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रस्ताव आ गये थे? मैं मानता हूं कि हमारे इलाके में जैसी गड़बड़ी हुई, वैसी गड़बड़ी सारे राजस्थान में हुई होगी। इस प्रकार जो योजना नीचे से बननी चाहिए थी, वह नहीं बनी और ऊपर से वह थोप दी गई, ऊपर से बना कर भेज दी गई और उसी आधार पर वह पंचवर्षीय योजना बनी।

अब सवाल यह है, मैं सोचता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो खर्चा किया जाता है, उसके सम्बन्ध में खास करके कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हमको यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से हिस्से हैं जो वर्षा पर आधारित हैं, जहां बारिश होती है और दूसरे ऐसे कौनसे हिस्से हैं, जहां बारिश नहीं होती है, कभी हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, तीन साल में एक दफा होती है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हालत तीन चौथाई राजस्थान में है और दो तिहाई हिस्सा इस प्रकार का मान लें कि जहां वर्षा होती है। अब वहां के लिए कहें कि यहां ऐसा फार्म बनाना है, इस प्रकार की योजना के अन्तर्गत यह काम करना है, या अच्छे बीज पैदा करने के लिए यह फार्म बनाना है, इस पर इतना पैसा लगायें।

Page No.65

(श्री मुरलीधर व्यास)

ठीक बात है, लगा दें, परन्तु उसकी उपयोगिता नहीं हो सकती, क्योंकि साधन नहीं है, बारिश नहीं है। इस प्रकार रुपया ब्लॉक हो जायगा और जो रुपया आप खर्च कर देंगे, वह उपयोगी नहीं होगा। इस प्रकार से खास करके अनाज उत्पादन की जो योजना है, वह उन इलाकों में कामयाब नहीं होगी, यद्यपि वहां खर्चा होता है, अफसर जरूर होते हैं। न जाने १५ लाख रुपये एक एक इलाके में क्यों खर्च होते हैं? मैं समझता हूं कि ऐसे इलाकों की दूसरे ढंग की योजना होनी चाहिए। जब पंचायत समिति और जिला परिषद् से सारे काम करवाते हैं, तो उनको वहां की वस्तु स्थिति के आधार पर वहां पैसा खर्च करने का अधिकार देना चाहिए। अगर वैसा होता है तो उनको लाभ हो सकता है और अगर वैसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि उससे लाभ नहीं हो सकता है। मैं तो यहां तक समझता हूं कि जिला परिषद् मिल कर सोचें कि ऐसे इलाकों के अन्तर्गत जहां बारिश नहीं होती है; जैसे हम देखते हैं कि बीकानेर का इलाका है, चूरू है, जैसलमेर का इलाका है, नागौर का इलाका है, छोटे छोटे आस पास के इलाके हैं, वहां की वस्तुस्थिति इस प्रकार की है कि वहां वर्षा के ऊपर सारी बातें निर्भर नहीं हैं, तो हमारा रुपया उन मामलों के अन्दर व्यर्थ जाता है। मैं इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो योजना है, जो योजना आज बन चुकी है परन्तु उसके बनने के बाद भी उससे लाभ मिलेगा या नहीं, यह सोच कर उसे अन्तिम रूप देना है। मैं समझता हूं कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के मामलों में अगर पंचायत समितियों की मार्फत खर्चा होने वाला है और उनको वहां की वस्तुस्थिति को देखते हुए खर्चा करने की इजाजत देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं, जो योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कुछ प्रावधान रखे हैं, इस सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि जैसी अभी चर्चा कर रहे थे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि को ज्यादा पैसा दे दिया, हमें इस प्रकार से दिया, आज हम यह बात कर सकते हैं परन्तु राजस्थान का पैसा, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च होगा, वह कहां कहां पर किस किस प्रकार से खर्च होगा और उसमें किसी विशेष क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और बहुत से क्षेत्रों को क्यों अधिक दे दिया जाता है; अगर इसकी चर्चा करते हैं तो हममें से ही कुछ कह सकते हैं कि आप क्षेत्रीय भावना रखते हैं। जब हम यहां बैठकर यह चर्चा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने एक स्टेट में ज्यादा पैसा लगा दिया, दूसरी में कम लगाया, इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की चर्चा करने के अधिकारी होते हैं। जब इस स्टेट के अन्तर्गत इस जिले को क्यों कम पैसा दिया गया, इसको क्यों ज्यादा दिया गया, इसकी बातें करते हैं तो क्षेत्रीयता की भावना कहा जाता है....

२ म. प.

मैं इस क्षेत्रीयता की भावना के तरीके से कतई नहीं सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि सबको विकास का मौका मिले और उसमें इस योजना के आधार पर हमको जितना मिलना चाहिये मिलें। अगर हम इस आधार पर नहीं सोचते हैं तो बहुत से क्षेत्र अविकसित

(श्री मुरलीधर व्यास)

रह जाते हैं और हैं। अभी सरदारशहर से आनेवाले माननीय सदस्य ने सड़कों की मिसाल दी। मैं कहूंगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६०० करोड़ रुपया खर्चा हुआ। आप अन्दाजा लगावें कि सड़कों के मामले में कितना खर्चा वहां पर हुआ और दूसरे स्थानों पर कितना हुआ और कहां कहां पर कितना कितना खर्च करने के लिये रखा गया और वह वहां पर पूरा खर्च क्यों नहीं हुआ? मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और खास करके बीकानेर डिवीजन के लिये और चूरू जिले के लिये क्योंकि दूसरे क्षेत्रों को मैंने गहराई से नहीं देखा और न उनको देख पाया। मैं बीकानेर डिविजन को और चूरू की बात को लेता हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वे सड़क की हों चाहे पलाना की खान की हों, चाहे शिक्षा की हों, चाहे होस्पिटल का प्रश्न हो, चाहे कोई भी मामले हों, अगर मैं उन सारे मामलों में जाता हूं तो देखता हूं कि बीकानेर का काम प्रायः अधूरा रहा है। बहुत से काम तो हुए ही नहीं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में खत्म होने चाहिये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में वहां का मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग कम्पलीट होना चाहिये थी मगर वह अभी तक खत्म नहीं हुई है। उस बिल्डिंग का एक पार्ट बना है बाकी बिल्डिंग बननी ज्योंकी यों बाकी है।

हमारे यहां पोलीटैक्निक इन्स्टिट्युशन भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले थे मगर अभी तक वे नहीं खुले हैं। जब उसके लिये यह कहा जाता है तो कहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के फर्स्ट इयर में खोल दिया जाएगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में खुलना चाहिये नहीं खुला और दूसरे स्थानों पर; जैसा कोटा में खोल दिया गया, उदयपुर में खुल गया। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब दूसरे इलाकों में खुल गये तो यह इलाका ऐसे क्यों रहा जहां पर यह पोलीटैक्निक इन्स्टिट्यूशन नहीं खुला। इसी प्रकार से पलाना मुलतानी मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारखाने के प्रश्न थे और उन पर खर्च करने का प्रश्न था। वेटरनरी होस्पिटल के खर्चे थे, रोड के खर्चे थे। मगर वे वहां पर पूरे खर्च नहीं किये गये। आपने पहली पंचवर्षीय योजना में यह रखा था कि हर डिस्ट्रिक्ट को डिविजन के सेन्टर से रोड द्वारा जोड़ दिया जावेगा। मगर मैं बीकानेर से गंगानगर और चूरू से गंगानगर की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं यह कहूंगा कि बीकानेर को आपने क्यों छोड़ दिया? गंगानगर और चूरू व बीकानेर और चूरू को आपने छोड़ दिया। आप कहेंगे जैसा मैंने पढ़ा, आप कह सकते है कि पत्थर आदि वहां पर नहीं मिलते। ऐसी बातें आप कह सकते हैं। मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक इलाके के लिये जितनी धनराशि को लगाने का आपने प्रोविजन किया, वह उस इलाके के लिये लगाना चाहिये था। एक तो पहले ही आपने इस इलाके के लिये कम धनराशि प्रदान की और जो भी तय करते हैं उसको लगाते नहीं हैं। इसमें मैं यह कहूंगा कि आप बहुत पक्षपात करते हैं। इतना ही नहीं, मैं यह कहूंगा कि उदयपुर में जहां पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का खास इलाका है वहां तो जो लगने वाली रकम है वह तो लगती ही है और उसके अलावा उस स्थान पर और भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

बहुत धन राशि लग जाती है। मैंने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी देखा कि वहां पर कितना लग रहा है। मैं यह कहूंगा कि आज हमारे यहां पर जितना लग रहा है उससे १० गुना वहां पर लग रहा है। मैं यह कहूँगा कि अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री जिस क्षेत्र से हैं वहां पर इतना ज्यादा खर्च होता है तो पक्षपात नहीं तो और क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं समझता हूँ कि आप १० गुना खर्च करने की जो बात कहते हैं, अच्छा हो कि आप आंकड़े भी बतावें बगैर आंकड़े बताये यह कहना कि वहां पर १० गुना खर्च अधिक किया जा रहा है उचित नहीं। इसके अलावा राजस्थान कैनाल बीकानेर और गंगानगर में ही आती है, इसका भी ख्याल रखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गंगानगर और बीकानेर में है। राजस्थान कैनाल की बात को लेकर यह तो नहीं हो सकता कि एक इलाके को छोड़ दिया जावे और अगर उस इलाके को छोड़ दिया जाता है तो उसकी क्या हालत होगी इस पर हमें विचार करना और सोचना होगा। आपने कहा कि आंकड़े बतावें। मैं आंकड़े बताने को तैयार हूं।

मैं दूसरों की बात न कह कर चूरू की बात कहता हूं। चूरू एक अच्छा जिला है। वहां पर ५० हजार की आबादी है। वहां पर आप देखेंगे कि एक हॉस्पिटल छोटा सा बना हुआ है। वहां की आबादी ५० हजार की है। वहां पर आप देखेंगे कि उस हॉस्पिटल में कोई फीमेल डाक्टर नहीं है। वहां के लोग आज ११। साल से बराबर चिल्ला रहे हैं, मगर अभी तक वहां पर कोई लेडी डाक्टर का प्रबन्ध नहीं हो सका है। वहां पर एक लेडी डाक्टर इतना अर्सा हो गया है, नहीं पहुंच पाती है। वहां पर अतिरिक्त पैसा लगाना तो अलग रहा। एक छोटी सी बात नहीं होती है। इसके मुकाबले में सैकड़ों रुपये उदयपुर में लगाये गये हैं। अगर वहां पर एक डाक्टर की जरूरत है तो वहां पर दो डाक्टर हो जाते हैं और वहां पर डाक्टर की कमी नहीं है। दूसरी जगह यह जो हाल है, इसलिये इस पर थोड़ा सा सोचना होगा। चाहे आप मानें या न मानें, निश्चित रूप से उदयपुर में ज्यादा धनराशि खर्च की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बुराई है तो यह है कि एक आदमी अपने क्षेत्र को इसी भावना से देखता है कि वह उसका क्षेत्र है और उस पर ज्यादा से ज्यादा धनराशि खर्च करता है और जब ऐसा होता है तो मेरे जैसा एक जन साधारण एम. एल. ए., वह यही समझ लेता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की कॉन्स्टिट्युएन्सी में ज्यादा खर्च किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रश्न तो आंकड़े बताने का था। आप आंकड़े बतावें जिससे हम उसको रिड्यूस कर सकेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की स्थिति सारे राजस्थान के मुख्य मंत्री होने के नाते बहुत बड़ी है और उनका स्थान सार्वजनिक होता है। अगर वहां पर इस प्रकार की बात होती

(श्री मुरलीधर व्यास)

है और वहां पर इतना खर्चा किया जाता है तो मेरे जैसा अदना आदमी अगर यह कहे कि यह धनराशि उनके क्षेत्र में की जाती है जहां उनका चुनाव क्षेत्र है तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। लोग इसको गलत कह दें, लेकिन वस्तुस्थिति यही है। आज आप देखेंगे कि पंडित नेहरू, इलाहाबाद कॉन्स्टीटुएन्सी से हैं और ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बार फिर माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप आंकड़े रखदें, फिर इस की आलोचना करें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृषि पर ५० लाख और सिंचाई पर अलग है। इसके अलावा वहां पर सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं जिन पर काफी रुपया खर्च होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ब्लॉक्स मुख्य मंत्री की कॉन्स्टिटुएन्सी में नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी कॉन्स्टिटुएन्सी में तीन ब्लॉक बनाये गये हैं। कुल १२ ब्लॉक हैं, और ब्लॉक्स पर १५ लाख रुपया खर्च होता है तो १२ ब्लॉकों पर कितना रुपया खर्च होता है।

इसके बाद उद्योग का प्रश्न है। प्राइवेट में देखें तो ज़िन्क स्मेल्टर वहां पर है। कपड़े की मिल वहां पर होगी। मैडिकल कॉलेज पर जो एक करोड़ पचास लाख लगने वाले हैं उसमें भी काफी रुपया वहां पर लगेगा। मगर अभी यह निश्चित नहीं है कि वह अजमेर जाता है या वहां पर। मगर यह कहा गया कि एक जोधपुर और एक उदयपुर में होगा।

लघु सिंचाई का खर्चा है वह भी आपके यहां पर ज्यादा होगा। बनास का खर्चा आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है।

श्री उपाध्यक्ष : The whole district has to be condemned ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप इसके लिये कोई इन्क्वायरी कमीशन बैठा दें तो आपको मालूम होगा कि इस क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना खर्चा हुआ है, देख लें और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना है, इसको भी देख लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर आपको सबसे अधिक खर्चा मालूम होगा। मैं तो १० गुना ही कहता हूं, इससे भी ज्यादा आएगा। केन्द्रीय सरकार का कितना खर्च होता है वह भी उधर ज्यादा होता है क्योंकि यह सब आपके पास ही है और आप कह देते हैं कि यहां पर इसकी आवश्यकता है और वह वहां पर खर्चा होता है। यह १० गुना खर्चा होता है यह तो मैंने बताया है, यह बात गलत साबित नहीं होगी। आप किसी भी क्षेत्र को ले लें। होना तो चाहिये था आपका दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में व्यापक होता, मगर ऐसा नहीं है।

आप सड़कों के प्रश्न को लें, सामाजिक शिक्षण को लें, ग्राम योजना का प्रश्न है उसको लें, मकान बनाने का प्रश्न है, जावर माइन्स का प्रश्न है उसको लें, पशुपालन का हिसाब लगावें। खेल—कूद का मामला

(श्री मुरलीधर व्यास)

है । यह खेल-कूद का मामला तो मामूली बात है । हर जगह पर इसके लिए रकम मिलनी चाहिये मगर इसमें भी उदयपुर में ५ लाख रखे हैं । बीकानेर डिवीजन पूरा है उस पूरे डिवीजन में एक पैसा नहीं मिला इस मामले में । ये जो इस प्रकार की बातें हैं, उनको देखना चाहिये । यह महसूस होता है । आयुर्वेद कॉलेज कितना जल्दी बन गया, कितना खर्चा लगा, उद्योग, कपड़े के बनाने वाले हैं ये सब आपके यहां । मैंने तो दस-गुना का ही हिसाब लगाया है, बीस गुना हो जाये तो आश्चर्य नहीं । एक ही क्षेत्र में इतना खर्चा हो और इस तरह से हो । जनतन्त्र में कुछ बनाते हैं, क्षेत्रीय भावना से नहीं सोचना चाहता और न होनी चाहिये, लेकिन एक क्षेत्र तो इतना पिछड़ा हुआ रह जाय और एक इतना आगे पहुंच जाय, वे आवाज़ करते रहें, कोई सुने नहीं । मुख्य मंत्री जी से कम से कम मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि तय किया था कि राजधानियां, डिवीजनल हैडक्वार्टर्स के पुराने स्थान हैं उनकी स्थिति को बनाये रखेंगे और उजड़ने नहीं देंगे, वे उतना ही उनका खयाल रखेंगे तो वह ही ज्यादा होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया हूं । थर्ड फाइव इयर प्लान का विवेचन किया है । पलाना बीकानेर से मिला हुआ है, नजदीक है । स्टेट सेक्टर में पांच करोड़ रुपया-खर्च कर रहे हैं । दस बीस गुना दूसरी जगह हो तो २०, २५ करोड़ दूसरी जगह कर दिया !

श्री मुरलीधर व्यास : पलाना को दूसरी योजना में छोड़ दिया । तृतीय योजना में तो करेंगे जब मालूम होगा । दूसरी योजना में जो कुछ हो चुका है उसको देख लें और तीसरी योजना बनायी है उसको भी देख लें ।

तो इसमें कुछ खर्चा इस प्रकार से है जिसके लिए हमको सोचना पड़ेगा ।

जहां तक कृषि का सवाल है, उन इलाकों में वर्षा नहीं होती है । उपज उसके ऊपर निर्भर है, हो गई बरसा तो उपज हो गई, नहीं होती है तो लोगों को उस इलाके को छोड़छोड़ कर बम्बई और अहमदाबाद की तरफ जाना पड़ता है । बीकानेर और चूरू ये ऐसे इलाके हैं जहां पर कि उद्योगों की आवश्यकता है । एक छोटी सी योजना बीकानेर में ग्लास फैक्टरी की इस योजना में देखी गई है, सम्भवतः हो सकती है । झगड़ा यह है कि २०-२५ लाख रुपया लगाने से रोजगार मिलता है लोगों को जो कि वर्षा के ऊपर आधारित हैं; नहीं तो बेकारी बढ़ती है, बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, ऐसी इन्डस्ट्री हर जगह नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा? लोग भटकते रहेंगे । पहली, दूसरी और तीसरी योजना आप कर रहे हैं और उसमें यह हालत रहती है कि उन लोगों को अपने जीवनयापन के लिए बाहर घूमना पड़ता है, एक इलाके से दूसरे इलाके में भटकना पड़ता है और उस पर भी हम कहें कि हमने योजना कामयाब कर ली है । कामयाबी नहीं हुई है ।

प्रचार में काफी खर्चा होता है, बड़े लम्बे प्रचार होते हैं । काफी खर्चा भी बढ़ाया जा रहा है । प्रचार के खर्चे को देखें तो पहले ४० लाख रुपया था और अब करीब १०० लाख रुपया हो गया । तो यह प्रचार का

Page No.70

(श्री मुरलीधर व्यास)

खर्चा किस दृष्टिकोण को प्रकट करता है। क्यों होवे ? मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रचार के मामले में जो खर्चा किया जाता है उसका अधिकांश भाग पार्टी विशेष के प्रचार के लिए होता है। पार्टी विशेष के प्रचार के लिए गरीब राजस्थान की जनता पर एक करोड़ का भार डाल दिया ! पब्लिक रिलेशन्स किताबें छापता है कि यह नहर आने वाली है, इतना अन्न का उत्पादन हो गया, इतने बेकारों को काम दे दिया गया है; इतना सा प्रचार करने के लिए एक करोड़ रुपया। ज्यादा से ज्यादा यह प्रचार में कर दिया कि मुख्य मंत्री जी की फोटो फ्रन्ट पेज पर अखबारों में छाप दिये, मुख्य मंत्री ने यह बात कही, वह बात कही। यह खर्चा इस तरह से होता है तो, मैं कहता हूँ, इसमें कमी करनी चाहिये। हम तो ४० लाख रुपया पहले से ही बहुत काफी समझते थे उसकी जगह १०० लाख कर दिया। सूचना केन्द्र और खोले हैं वे अलग हैं और उनका खर्चा अलग, विकेन्द्रीकरण का अलग। ये जो इस प्रकार के खर्चे रखें हैं उनमें कटौती करनी चाहिये। ये खर्चे वाकई पार्टी विशेष के लिए होते हैं। आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये नहीं होता। ऐसे बहुत से खर्चे हैं जिनमें हम कमी कर सकते हैं और इन्डस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं। आप समझ जाओ कि ४० लाख खर्च करते हैं, यदि ६० लाख किसी इन्डस्ट्री में लगा दिया पब्लिक सेक्टर में खोल देते हैं तो उससे अधिक फायदा होगा। सरकार का यह ध्यान है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग आवेंगे। बेकारी दूर होगी। आपसे मैं इस मामले में सहमत नहीं हूं। यदि समाजवादी समाज को कायम करना चाहते हैं तो सरकार की हिम्मत होनी चाहिये कि वह पब्लिक सेक्टर में खर्च करे। प्राइवेटसेक्टर से ज्यादा आप बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकते। दिल्ली की पार्लियामेंट में जाने वाले सोमानी, आपके कांग्रेस टिकिट पर जाते हैं, गोयन्का हैं वे भी कांग्रेस पार्टी के टिकिट से और बनचनी और कई हैं करोड़पति। उनको राजस्थान की जनता से वोट दिला कर दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजते हैं। उनको यह नहीं कह सकते कि तुम राजस्थान की जनता के वोट से दिल्ली में जाकर बैठते हो, यहां की जनता के लिए खर्चा क्यों नहीं करते और बाहर ही क्यों करते हो; जब हमारे राजस्थान के बन कर जाएं और दूसरे इलाकों में खर्च करें और यहां नहीं करें। फिर दूसरों को बुलाते जाओ उद्योग खोलने के लिए, तो कौन आवेंगे। वे वस्तुस्थिति को जानते हैं, कौन काम करेंगे। इसलिये जहां हमको बेकारी की समस्या को दूर करना है। हमारे साधन हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर में लगावेंगे। इस प्रकार की कोई योजना रखनी चाहिये थी और काम प्रारम्भ करना चाहिये था।

बिजली की बात कही। ठीक है, बिजली कम भी मिली हो। कम से कम जहां बिजली मिल गई है तो वहां तो रेट्स कम करें जिससे उद्योग खुल सकें। अब भी वही पुरानी रेट है। पहले जो उद्योग को चला रहे हैं उनकी स्थिति को ठीक कर लीजिये तब ही जाकर दूसरों को उससे प्रेरणा मिल सकेगी।

तीसरी छोटी सी बात यह कहना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज के ढांचे की स्थापना की दृष्टि से यह योजना बनानी पड़ेगी कि महंगाई न बढ़े। रेट्स न बढ़े। तीसरी पंचवर्षीय योजना में

Page No.71

(श्री मुरलीधर व्यास)

रेट्स के लिए कुछ नहीं है। आगे इन पांच सालों में योजनाबद्ध विकास करने में दिक्कत खड़ी होगी। यह मान कर चलिये कि सबसे पहली जो दिक्कत बढ़ेगी वह यह दिक्कत बढ़ेगी कि महंगाई बढ़ेगी।

आप यह कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत स्टॉक सरप्लस है, हम महंगाई बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन यह होने वाला नहीं है। आखिर आपने साधारण आदमी के जीवन-स्तर को कायम रखने के लिये क्या योजना बनायी है? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग हो रहा है, कन्ट्रोल जारी कर दिया जायगा, ये जो इस प्रकार की बातें करते हैं मैं समझता हूं कि यह कन्ट्रोल और स्टेट ट्रेडिंग की बात तो ठीक है लेकिन जहां साधारण व्यक्ति के जीवन-स्तर को, जो आज है उसको कायम रखने के लिये आपको उस प्रकार का मैनेजमेंट तो करना होगा, उस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी ताकि उनका जीवन-स्तर ठीक बना रह सके। भावना में बहने की बातें तो अलग हैं लेकिन जिस स्थिति में आज हम हैं उसके लिये कोई योजना नहीं है। टीन श्री चद्दरों का सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि ब्लेक में बिकते हैं, यह तो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं! आप अधिकारी हैं आपको सारे राजस्थान के लिये मैनेजमेंट करना है। यदि भाव बढ़ जाते हैं तो आपको चाहिये कि आप उसको कम करने का प्रयत्न करें, आखिर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? योजनाबद्ध विकास के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि जो जीवन स्तर आज तक बना हुआ है, वह बना रहे, उसमें किसी प्रकार की कमी न आये। यदि हम साधारण आदमी के जीवन स्तर को बनाये नहीं रख सकते तो मैं कहूंगा कि चाहे कितनी ही योजनायें आप बनायें उसका योजनाबद्ध लाभ नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय जिन्होंने इस बारे में काफी लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दिया, वे इस पर भी गौर करेंगे। यह मैं मानता हूं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है कुछ अन्य मामलों में भी तरक्कियां की हैं लेकिन उन तरक्कियों में जो विषमता है वह हम दूर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। यह ठीक है कि लोगों को कुछ काम दिया गया और दे सकते हैं। लेकिन हमें उसमें भी यह देखना है कि इससे राज्य की स्थायी दौलत कहां तक बढ़ती है? एक आदमी को ऐसी जगह बिठा दें जहां पर बैठे हुए भी लगातार हमारे देश की दौलत बढ़ती रहे, ऐसा उपाय होना चाहिये। कुछ टेम्पोरी काम देकर, यह ठीक है कुछ लोगों को काम दिला सकते हैं लेकिन वह हमारे देश की औसत आमदनी को बढ़ाने में कामयाब नहीं होगी। जहां हम स्थायी काम देने का इन्तजाम करते हैं तो उस स्थायी इन्तजाम से राज्य की दौलत बढ़ सकती है।

इसके साथ साथ मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि उन्हें बेकारी की समस्या के बारे में भी पूर्ण रूप से गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। हम किस तरह से और किस प्रकार से इस समस्या को हल कर सकते हैं? इस पर विचार करना होगा। इस योजना के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा उस पर मुख्य मंत्री महोदय, मेरे इस

Page No.72

(श्री मुरलीधर व्यास)

कथन पर भी ध्यान देंगे कि पिछड़ा इलाका जो निग्लेक्टेड रह गया है, जिसका ध्यान नहीं रहा, वाकई उस बारे में ध्यान देंगे। इसके साथ साथ पुरानी राजधानियों के बारे में जो हमारा पहले दृष्टिकोण था, किसी भी राजधानी को उजड़ने नहीं दिया जायगा, जो स्तर उनका पहले था उसी स्तर को बनाये रखेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कृषि मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा एवं श्री श्रीभानसिंह के बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : I will give you the chance after Mr. Sribhan Singh has spoken, Hon'ble Minister.

Shri Sribhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this House is discussing the Third Five Year Plan of Rajasthan. Before I discuss certain problems regarding the Plan in this State, I would like to associate myself with the Hon'ble Member who spoke before me that when the leader of the House...

श्री उपाध्यक्ष : If not inconvenient to you, can I request you to deliver your speech in Hindi so that most of the members may have benefit out of your learned speech.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Members would excuse me but I would like to benefit myself.

As I was saying, I would like to associate myself with the Hon'ble Member who spoke before me that when we put forward our claims for reducing the disparities between the States, the Leader of the House should not forget that disparities between divisions and districts of Rajasthan also exist here. I will not labour to produce facts and figures in support of this, but he may himself ask his Planning Department to produce them.

While initiating the discussion on the Third Plan, the Hon'ble Leader told the House regarding the progress achieved during the First and the Second Plan. I have no doubt about that progress and I extend my congratulations for making the economy of this State developed. But out of his speech regarding progress achieved, certain basic issues came out- the basic issues which should have governed our approach to the formulation of the Third Plan. These issues cropped up from the First and Second Five Year Plans, but they were completely disregarded when the Planning Board of this State formulated the Third Five Year Plan. Broadly speaking, these issues were stated, in the language of the Hon'ble Leader, as, (i) that the per capita income of this State has not increased, (ii) the employment potential

(श्री श्रीमानसिंह)

which should have been created during the First and Second Plans, have not been created, and (iii) the Second Plan was a plan to make the economy, in economic jargon, at a 'take off' stage, and the issue for the Third Plan is to make the economy self sustained. These three issues were placed before us, that the per capital income of this State must increase so that living standards must rise and, secondly, the employment opportunities should be equal to the extent of labour force created, and the third is that the economy must become self sustained.

However, Sir, as I said, in the formulation of the Third Plan none of these issues was taken into consideration, and if this is an attempt to grapple with these problems, then I must say that it is a very timid attempt. Knowing fully well that the per capita income has not increased, that the opportunities of employment have not increased and that with the present structure of investment or expenditure, we will not be able to make the economy self sustained we reduced our Plan expenditure by about 200 crores or so. Though the Chief Minister put forward the claim that the investment potential in the Third Plan should have been near about 400 crores, yet in formulating the Plan it is completely missing and I must frankly say that probably the influence of that super-Cabinet-what we call the Central Planning Board is much greater on our State. This timid attempt will not help to solve our economic problems.

Similarly, I was surprised to see that this Third Plan is devoid of the ideology of a socialist economy which this very party has put forward before the country. That ideology which is reflected in the Third Five Year Plan of the Centre is not there in our Plan. Our Plan is in a chaos as far as that ideology is concerned; it has a minus ideology and our Plan is not the one which goes to achieve a socialistic pattern of society, nor will socialist values be implemented in Rajasthan under this Plan. If we look into the Central Five Year Plan, there is a certain type of organisation there which the State has put before the people. First, there is the public sector, then the private sector and the third one is the co-operative sector. Broadly, the Central Plan can be divided into these three sectors and this is called socialist ideology or socialist values or the achievement of a socialistic pattern of society. But in our Third Plan the public sector is conspicuous by its absence, and when there is no lead from the State or Central Government, the private sector is also silent. There is co-operative sector in a rudimentary form taking the State to co-operative credit institutions and co-operative farming. That is all. So our Third Plan is completely devoid of any ideology

(श्री श्रीमानसिंह)

which the party has put before the country and I am surprised how this oversight has been committed. Therefore, I cannot compliment this Third Plan as a plan which will achieve, in the words of the Directive Principles of our Constitution, "justice-social, economic and political". In a plan, where individual initiative predominates, the private sector in its rudimentary form, agriculture and small scale institutions predominate, then the Hon'ble Leader will excuse me, I have no other word for such plan except to say very humbly that it is a capitalist plan. This is the term I can use for it. Or, in other words, it is a Plan which has no ideology.

While initiating the debate in the Parliament, the Prime Minister laid more emphasis on the achivement of socialist values in the country, but while initiating the debate in this House the Hon'ble Leader dwett at length on the achivement of targets, at the investment and other potentialities of the State, wholly neglecting the ideological side of the Plan. As I said, Sir, this Plan does not tackle the problems of the State or the issues which were brought before us. We are trying to utilise our man-power, the vast man-power in our State that lies idle, through democratic decentralisation, through Panchavats and Panchayat Samitis. Let us hope the results will be very good and beneficial to the State. But one fault that somehow or other has been overlooked is that we are making these democratic institutions monetary-conscious. While expenditure on every item was cut in the Plan, expenditure on Agriculture, industrial Development and Power was cut, somehow or the other, the expenditure on democratic decentralisation was increased. It shows one thing, that we have created these institutions in order to take increasing grants from the State, to extract and to take the labour, to utilise the labour on country side. in producing the capital in the country side-is our ideal. If we are getting that, then I am afraid if that can be done through any agency other than these Panchayats or the Panchayat Samitis. Therefore, in the initial stage 'Shramdan' or the slogan of 'giving one day to the nation,' if that is to be implemented, we should keep the resources at the minimum. But somehow or the other because in every work, though there is nothing of the democratic docentralisation, I think it has become a mania and phobia with our officers. It is not the industrial or power dovelopment of the State. I am unable to understand when we have got those institutions like Panchayats and Panchayat Samities now, what is the need of having these N. E. S. Blocks ? Why not amalgamate both these and give them a lump sum grant ? After all what will they do ? They have to be coterminus with your blocks. For the

(श्री श्रीमानसिंह)

continuance of these two co-terminus institutions, I see no reason for it. I will prefer that they should be amalgamated. One beneficial aspect of the Planning is the utilisation of the manpower. Uptil the Second Plan, people in rural areas were feeling that their needs were included in the Plan but on account of the huge and gigantic items like Rajasthan Canal, Rana Pratap Sagar Dam, and Gandhi Sagar Dam' etc., they have not been fulfilled. Our rural people want schools, cooperative Societies, housing and other drinking amenities. These were the basic preblems. These are the good aspects and I can assure the House that if these problems are tackled, a well-desired contribution will come. They will certainly welcome the Planing and they will like to contribute. But, [Sir, with all these good things, I cannot understand that the Plan has put for a priority itself. Whatever it is,I welcome it. It is more on Social welfare and more on backward classes, but in these things, some blocks come in. But the Plan does not benefit these classes. It is not an overall plan. It means development of everybody. Planning is nothing but it is a sort of arrangement of choices. Planning on India cannot prosper within ten years or fifteen years. We can make our choices in production. We, may have minimum benefits. But I cannot agree with the priority given to the Agriculture. I will not labour in order to put facts and figures but I take all these figuresplaced before theHouse as true,then we exceeded our targets in the Seond Plan and we hope to excced in the Third Plan too. But, Sir, as one of my predecessors stated that agricultural economy is a backward economy, and the per capita income is low, in our First Plan we gave more attention to agriculure and it was given in the Second Plan also and we can again pay our attention to Agriculture in the Third Plan also but per capita income will always remain low. These people who are industrial employees in the urban areas they will have greater per capita income. If we want to raise that per capita income at the national level, we will have to produce more agriculture production. If I may draw the attention of the House towards the fact that we achieved II lac tons exceeding the targets by about 3 lac tons. In the Third Plan target we have placed it at 18 lac tons. With an investment of 1000.00 crores we propose to achieve only 18 lac tons. I think, there is something wrong in the caloulations but it we reduce it from agriculture by just two crores and place at 800.00, if we place it on this figure, I can assure this House that by taking that figure, we will have 22 lac tons. Thereby it can easily be cut down to two crores and additional allotment can be made to industrial development.

I would much prefer that adequate allotment should be made to industries. As I said, the Plan is an

(श्री श्रीमानसिंह)

arrangement of choices. A State can choose to be agriculturist, but there should be a balanced development; and balanced development needs that first agriculture must precede, but at the same time industrial development should not lag behind. In all the countries of the world, agriculture gets precedence, but their industrial development also does not lag behind. If we take at random France and England, there agriculture is important, but they are far more advanced industrially. My predecessor speaker calculated our food requirements on the basis of 18 ozs. per person, but I can give 20 ozs. per person and still we can export the foodgrains. We have reached a balanced development in agriculture with the pressent resources and present circumstances and our agriculture potential is fully utilised. I am speaking without taking into consideration the Rajasthan Canal. With the present investment and at the present rate of economic growth, we can say that we have reached a stage when our agriculture potential is fully utilised. Then we should not lag behind in industrial growth. It should be realised that it can be done only when we allocate more funds to industries. If we continue to invest more in agrciulture, I can assure you that per capita income will continue to be the same. If we continue in the same occupational structure in our economy, I can assure you that unemployment will continue to be the same, and if the expenditure on Third Plan will not be on industries, I can assure you that our economy will never be self-sustained. This is the weakness of the Plan. Industrial development is now the crux of our problem. As I said, if there had been an ideology behind the Plan, then there would have been certain things which the State would have taken in the public sector and left the others to the private sector and still others to the co-operative sector. In a backward economy it is the State which has to give a lead to the people, but in Rajasthan it has not been able to give this lead.

In this State there must be industrialisation. If you want the State to prosper, then industrialise by any means. Since we have not included any ideology in the Plan, we must have the public sector take up heavy industries. An argument may be put forward that those metals which are not found in Rajasthan, we should not have any industries depending on them. Let me tell you that in Japan, iron and steel is imported from outside and still they produce goods cheaper and earn foreign exchange. It should be placed before the Centre that it is not necessary that the metal should be available here. Only the conditions for industrialisation must exist, and they do exist in Japan as well as in Rajasthan. If Japan can do it, certainly the Centre can invest in Jaipur, Uaipur or Bikaner. I have

(श्री श्रीमानसिंह)

delineated at length the industrial aspect because the Hon'ble Leader may say that we have allocated Rs. 6. 50 crores to industries. As the Hon'ble. Lleader of the Jan Sangha pointed out, out of the previous allotment of 5.64 crores for industries, we were able to spend only about 3 crores. So 2 crores is the savings of Second Plan and that saving has been included in the Third Plan. In fact if we take this factor into consideration, then the allocation for industrial development in the Third Plan is less than what it was in the Second Plan. If this is our policy towards industries, the progress of our economy will be postponed, and postponed for a very long time.

In the end I would deal with the power problem because without power there cannot bo any industrial development. I would not be very harsh in my criticism. Some steps have of course been taken but they are not satisfactory, because generation of electricity from thermal power at the beginning of the First Plan was 34,000 k. w.s and at the end of the Secod Plan it would remain at 34,000 k . w. s. Therefore, the progress regarding thermal power would remain just constant. We have to increase power and to give it on cheap rates. I agree that there are limitations before the State, but the Centre may come to your aid. Besides, I see no objection, when there is a growing demand for power and there is a wide gap between the demand and supply of electricity, why we should not allow private sector to come forward and instal power houses in the State to meet this gap. Either the Cen tre should be prepared to meet our demad or, in the alternative, we should allow private sector to instal power houses in the State so that in the Third Plan our power needs are well met.

Similarly, industries will not be attracted to Rajasthan, unless, besides giving them power, we give them some concessions regarding raw materials. In some industries the State will have to give exemption from octroi duty. Some exporting industries would require raw materials from outside and they will have to be exempted from paying octroi on their raw materials. Some other concessions will also have to be given Therefore, in order to achieve the industrial development, in order to give employment to our people and in order to increase the per capita income of the people to the Union level and to make the economy self-sustained, my request is that the Plan ceiling should be raised to Rs. 400 crores. There is no other way.

A difficulty on which nobody has thrown light, is the administrative difficulty. Somehow or the other, even during the two Plans, administrative efficiency has not gone up. Therefore, we will have to raise our administrative efficiency, honesty

(श्री श्रीभानसिंह)

and speed in the work. If we want to execute this Third Plan quickly, we have to gear up our administration. Then only we can succeed in executing our Third Plan. There will be gigantic expenditure and that may create another problem. That problem is the inflationery trend. The State will have to devise machinery with which to stabilise the prices. The people have become inflation-conscious. If the prices continue to rise, you will find that demand for increase in salaries will come; and if salaries are increased, there will be dearth of consumer goods. So in order to check the inflationery trends, the State must devise a machinery.

In the end, in order to place the economy of Rajasthan on an even keel, I would once again make out a case of increasing the Plan ceiling to Rs. 400 crores.

(श्री चन्दनमल वैद व कृषि मन्त्री श्री नाथूराम मिर्धा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister will make some clarifications, after which Shri Baid will have his chance.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(दो तीन अन्य माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि पहले मन्त्री महोदय कुछ मामलों का क्लेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद में दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में तृतीय पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में जो प्रस्ताव राज्य के मुख्य मंत्री जी ने पेश किया उसके बाद से सदन के माननीय सदस्यों ने प्लान के कई आस्पेक्ट्स पर अपने विचार रखे। मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हो गया बीच में कि कुछ चर्चाएं जो प्लान के बारे में चल रही हैं उनमें प्लान का एक महत्वपूर्ण अंग उन डिपार्टमेंट्स से सम्बन्धित है जिनको कि मैं डील करता हूं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण की शुरूआत में यह कहा कि राजस्थान का जो प्रोडक्शन का टार्गेट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए रखा था उसमें राजस्थान उससे ज्यादा करता रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार जब बजट के मौके या दूसरे मौकों पर चर्चा हुई है तो मैंने समय समय पर यह कोशिश की है कि प्रोडक्शन के सही आंकड़े जो कि कई तरह से वेरीफाई किए जा चुके हैं वे सदन के समक्ष रखूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जिस समय हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी उस समय राजस्थान करीब डेढ़-दो लाख टन से डेफिशियेट था और वह आंकड़ा पिछले राजस्थान का इन्टीग्रेशन होने के बाद और जब राजस्थान एक हो गया तो हमको बाहर से कितना नाज एक साल में मंगाना पड़ता था लोगों के खाने के लिए और खर्च करने के लिए ? उन आंकड़ों के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आधार पर इस बात की पूरी जानकारी करके पता किया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना बनने से पहिले राजस्थान करीब डेढ़ लाख टन से डेफिशियेंट स्टेट थी। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में दो लाख टन एडीशनल फूड प्रोडक्शन का प्रोग्राम बनाया और जो कुछ प्रोविज़न रखा और जो कुछ काम काज प्रथम पंचवर्षीय योजना में चले उनके केल्कुलेशन के बाद में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में हमारा फूड प्रोडक्शन तीन लाख टन सरप्लस के रूप में हुआ। दो लाख टन के बजाय में हमने तीन लाख एडीशनल प्रोडक्शन किया जबकि एक-डेढ़ लाख टन का इम्पोर्ट करना पड़ता था, इसके बजाय में प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक सेल्फ सफिशियेंट प्रोविंस फूड के मामले में राजस्थान बन गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जैसा अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने बताया कि करीब साढ़े चार करोड़ के आउट ले से हमने एडीशनल प्रोडक्शन की जो उम्मीद की थी वह सीरियसली १.१२ के एडीशनल प्रोडक्शन का टार्गेट था और उसके बारे में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चालू हुई उस समय हमारे राजस्थान के टोटल प्रोडक्शन के आंकड़े ३६.२५ लेक्स टन के करीब टोटल प्रोडक्शन बनता है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह ८.१२ एडीश्नल प्रोडक्शन का टार्गेट रखा उसके बारे में कल श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फिर यह कहा कि इन आंकड़ों से संतोष नहीं होता, ये ठीक आंकड़े नहीं हैं, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि मेजर इर्रिगेशन के जो टार्गेट्स एडीशनल इर्रिगेशन के रखे थे करीब १२ लाख एडीशनल एकड़ की पिलाई का टार्गेट जो रखा था वहां करीब ५॥ लाख एकड़ ही पूरा हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक माइनर इर्रिगेशन के टार्गेट जो हैं, बीज और खाद भी जितने हद तक दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया जा सका। यह भी कहा कि जानवर जो हैं एक तरफ तो कहा जाता है कि उनमें सुधार हुआ है, वे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ काफी तादाद में मर रहे हैं; इस वजह से खाद कम होता है। तो एक तरह से इस मामले को भी लिंक करने की कोशिश की थी कि जानवर ज्यादा मर रहे हैं, इसलिए खाद कम हो रहा है। खाद कम हो रहा है और एक तरफ कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन बढ़ा है तो ये सारी चीजें कैसे एक साथ चल रही हैं और उन्होंने जो कुछ कहा साफ साफ उनके दिमाग में इस बात का संतोष नहीं हो पाया कि ८.१२ लाख टन एडीश्नल प्रोडक्शन करने की बात सोची थी और इस प्रकार कमी जो उन्होंने बताई है कि हो रही है तो फिर एडीनश्ल ८.१२ लाख टन का प्रोडक्शन कैसे हो गया है? मैंने आगे भी इस के बारे में काफी सफाई के साथ जवाब दिया है कि हमने ८.१२ लाख टन्स के टार्गेटस जो एडीश्नल प्रोडक्शन के रखे थे उनका विभाजन इस प्रकार से था कि मेजर इर्रिगेशन से जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वह २.५६ लाख टन्स का बढ़ेगा, माइनर इर्रिगेशन की वजह से ०.८३ लाख टन्स बढ़ेगा। लैंड डेवलपमेंट की वजह से ०.२४ लाख टन्स बढ़ेगा, मेन्योर्स एन्ड फर्टीलाइज़र्स की वजह से ०.६० लाख टन्स बढ़ेगा, इम्प्रूव्ड सीड्स की वजह से २.०४ लाख टन्स प्रोड-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

क्शन बढ़ेगा, इम्प्रूव्ड कल्चरल प्रेक्टिसेज़ की वजह से १.५२ लाख टन्स प्रोडक्शन बढ़ेगा। इन सब का योग कुल मिलाकर ८.१२ लाख टन्स होता है और यह किस प्रकार से सेकिण्ड फाइव इयर प्लान तक होगा और कितना किस की वजह से बढ़ेगा और कितना शोर्टफाल रहेगा, उन आकड़ों से पता लगेगा।

मेजर इर्रिगेशन में शोर्टफाल रहेगा। मैं अब भी कह सकता हूं कि जैसा कि हमने सोचा था कि २.५६ लाख हो, वह नहीं होगा। वह इस वजह से नहीं होगा कि १२ लाख एकड़ का जो टार्गेट सोचा था मेजर इर्रिगेशन की वजह से वह क्योंकि कम रह गया इस वजह से हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा और आज भी जो कहते हैं उस बात को उसी बेसिस पर कहते है। माइनर इर्रिगेशन में इसमें लिखा है कि ०.८३ का वह ०.७६ ही होगा। वह भी कम होगा। परन्तु इस माइनर इर्रिगेशन में भी कई हैड्स हैं जिनको आगे चल कर डील करूंगा और मैं आपके सामने बताऊंगा। लैंड डेवलप-मेंट से जहां हमने ०.२४ की उम्मीद की थी वहां पर सब से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, जो कि उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया था। उससे ५.७२ का एडीशनल प्रोडक्शन हुआ है और इसके बारे में मैंने पहले भी सदन के सामने निवेदन किया था कि पिछले ५ साल में राजस्थान में करीब करीब नई ५० लाख एकड़ जमीन अन्डर कल्टीवेशन आई है और वह जमीन बारानी जमीन भी है कुछ नई इर्रिगेशन लैंड भी है और कुछ ऐसी लैंड है जो कि पहले सिर्फ सिंगल क्रॉप थी और कुंए बन्ध आने की वजह से डबल क्रॉप की हुई है। इस प्रकार का एरिया कम नहीं हुआ है। जो डबल क्रॉप एरिया हुआ है राजस्थान में वह पिछले ५ साल में १० हजार एकड़ जो सिंगल क्रॉप एरिया था कुओं की इर्रिगेशन की वजह से डबल क्राप एरिया बना है। इस तरह से इसमें नई टोटल ५० लाख एकड़ जमीन आई है उसके लिए अभी आंकड़े ५३ लाख के किसी किसी साल में आये हैं। उस मार्जिनल लैंड को छोड़ दें जो कि हो सकता है कि बारिश की कमी होने की वजह से या प्राइसेज़ में कमी होने की वजह से कल्टीवेट नहीं होती है। उस मार्जीनल लैंड को जो कि कल्टीवेशन में है उसको नहीं मानें जो कि ५३–५४ लाख एडीशनल एकड़ तक जाती है, तो कम से कम ५० लाख एकड़ पिछले ५ सालों में नई लैंड कल्टीवेशन में आई है। उसकी वजह से हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। नई लैंड के कल्टीवेशन में आने से बढ़ा है। जहां हमने ०.२४ लाख टन्स का एडीशनल प्रोडक्शन सोचा था नई लैंड के कल्टीवेशन में आने से वहां बहुत ज्यादा बढ़ा है वह ५.७२ के करीब एडीशनल प्रोडक्शन होता है।

इसी प्रकार से मेन्योर्स और फर्टीलाइ-ज़र्स की वजह से जहां ०.६० का सोचा था वहां १.१ लाख टन्स का एडीशनल प्रोड-क्शन उसकी वजह से होगा। फर्टीलाइज़र्स में दो कम्पोनेन्ट्स हैं, एक केमीकल फर्टीलाइ-ज़र्स और दूसरी हमारी कम्पोस्ट की स्कीम है जो कि म्युनिसिपैलिटीज़ के जरिये और ग्राम पंचायतों के जरिये चल रही है, जिसमें गोबर का खाद भी आता है, मेढ़ का खाद भी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आता है और सभी प्रकार का खाद आता है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये बताना चाहता हूँ कि सेकिण्ड प्लॉन में केमिकल फर्टीलाइज़र्स के जो टार्गेट्स रखे थे उसके मुताबिक केमिकल फर्टीलाइज़र्स हम लोगों को सप्लाई नहीं कर पाये। लोगों की डिमान्ड आज भी ज्यादा है। सेकिण्ड फाइव इयर प्लॉन में भी ज्यादा थी, जैसा कि मैं आपके सामने रखूं कि इस साल करीब १० हजार नाइट्रोजिनस फर्टीलाइज़र्स देने चाहिए थे, लेकिन अभी साल के दौरान में बड़ी डिमान्ड के बाद भी सप्लाई नहीं हो पाया है और २५०० तक की ही सप्लाई पहुंच चुकी है और लोगों को नहीं दे पाये हैं, लेकिन केमिकल फर्टीलाइज़र्स के अन्दर बहुत कमी रही है। दूसरा कम्पोस्ट का है जिसके लिए आपने जिक्र किया है कि जानवर ज्यादा मरने लगे हैं और खाद कम हो गया है। खाद कम हो गया है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया? तो, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कम्पोस्ट की स्कीम राजस्थान में दूसरी स्टेटों के बजाय काफी तेज़ी के साथ चल रही है। इसके लिए ग्राम पंचायतों ने भी लोन्स लिये हैं और खाद बनाना शुरू किया है। इन्डिविजुअल लोगों ने भी खाद को ज्यादा बढ़ाने की तजवीज की बात को सोचा है और जानवरों की मोर्टेलिटी की वह बात कहते हैं तो कैसे उन्होंने कहा कि सेंसस के आंकड़े जो कि अभी जानवरों की सेन्सस हुई है सब आंकड़ों को देखेंगे तो हमारी केटल वेल्थ सब जगह बढ़ी है। भेड़, बकरी, गाय, ऊंट और घोड़े सब बढ़े हैं, सब जानवर बढ़े हैं। घटने का सवाल नहीं है। अगर मोर्टेलिटी के फीगर्स को चेक अप करें तो बहुत कम होने के बजाय उनकी पोपुलेशन बढ़ी है। जानवरों के जीने की रफ्तार वही है जो कि पहले थी। मोर्टेलिटी कम हुई है, इस वजह से जानवरों की संख्या बढ़ी है, इस वजह से खाद कम हुई है, वह न सेकण्ड प्लॉन में हुई है और न थर्ड प्लॉन में कम होने की उम्मीद है। इसलिए मेन्योर का....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह मैंने नहीं कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मोर्टेलिटी के कारण से आपके पास फर्टीलाइज़र्स में कमी आई है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा मैंने नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कहा है कि मोर्टेलिटी की वजह से हुई है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कहा है कि मोर्टेलिटी ज्यादा हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यादा हुई या नहीं, वह सेन्सस के फिगर्स देखें जो कि पिछले ही साल हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह : फीगर्स देखकर कहें। आप बता दें। आप कम्पेरेटिवली बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : फीगर्स सेन्सस वगैरह के देखकर मैं कह रहा हूं कि वे फैक्ट्स सही नहीं हैं। आप देख सकते हैं, आप बैठकर कम्पेअर कर सकते हैं। इस वजह से खाद हिन्दुस्तान के अन्दर बढ़ा है। फर्टीलाइज़र्स के कम्पोस्ट के रूप में काम में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ज्यादा आने से प्रोडक्शन इस हैड में जितना बढ़ने की बात सोची थी उससे ज्यादा बढ़ा है ।

सबसे ज्यादा हमारा इम्प्रूव्ड सीड के अन्दर शोर्टफाल है । अब भी कुछ जितना इम्प्रूव्ड सीड के अन्दर सोचा था, नहीं कर पाये हैं । हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म अभी पूरे सेट अप होकर बराबर सीड फार्म के फन्क्शन करने के ज्यादा लायक हो गये हैं । ४२ सीड फार्म बनाने थे सौ-सौ एकड़ के । उनमें से ३६ सीड फार्म सेट अप कर लिये हैं । एन ३६ में से ३४ सीड फार्म इस पोज़ीशन में हैं कि उन्होंने सीड प्रोडक्शन करना चालू कर दिया है पिछले साल से । ५ इस साल से काम करना शुरू कर देंगे और दो और जो एस्टेब्लिश करने बाकी रह जायेंगे । वह इस साल के अन्त तक एस्टेब्लिश कर पायेंगें और फस्ट इयर ऑफ दी थर्ड प्लॉन तक वह प्रोडक्शन सीड का दे देंगें । इसलिए सीड का जो कुछ सोचा था वह सीड के फार्म एस्टेब्लिश होने में कुछ देरी ज्यादा लगी है, इस वजह से जितना अच्छा सीड देने की बात सोची थी उतना नहीं दे पाये हैं, परन्तु थर्ड प्लोन में यह मामला बहुत तेजी के साथ चलने लगेगा और सीड को ज्यादा अच्छे रूप में ज्यादा तादाद में दे पायेंगे । इस वजह से आगे इसका रीएक्शन होगा प्रोडक्शन पर ।

सबसे अच्छा इम्प्रूव्ड कल्चरल प्रेक्टिसेज़ की वजह से हमारे टार्गेट्स पर बहुत फर्क पड़ा है और इसका कारण यह भी माननीय सदस्य सब जानते हैं कि हमारी विकेन्द्रीकरण योजना की वजह से और उससे पहले विकास की जो योजनाएं गांवों में काम कर रही हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट वे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बहुत कुछ मदद करने वाले अंग हैं । इस वजह से कई प्रेक्टिसेज़ जो गांवों के अन्दर बड़े इलाके में हिन्दुस्तान में और जगह नहीं हुई है ये राजस्थान के अन्दर ज्यादा हुई हैं. जैसे मेंढ़ बन्दी का प्रोग्राम ड्राइ फार्मिंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेन्ट अंग है । बहुत कुछ लम्बे चौड़े पैमाने पर मेढबन्दी का प्रोग्राम चला और इस प्रकार से कलचरल प्रेक्टिसेज़ में बहुत सारी प्रकार की हैं, जैसे गांवों में डिमान्स्ट्रेशन फार्म्स, उन चीजों का इम्पलीकेशन, कुछ इम्प्लीमेन्ट्स के यूज़ करने के तरीकों के कारण प्रोडक्शन का ज्यादा रिज़ल्ट आया है । ऐसा इवेल्युएशन किया गया है । जो कुछ इकइवेल्युएशन कमेटी ने बैठकर इवेल्युएशन किया है उसकी वजह से यह परिणाम आया है । उसकी वजह १.५२ के प्रोडक्शन के बजाय २.५२ का प्रोडक्शन हम मानकर चलते हैं, सेकिन्ड प्लान के अन्त तक ।

तो इस प्रकार से इन आंकड़ों का टोटल ११. ७६ लाख एडीशनल टन्स आता है तो एप्रोक्सीमेटली एडीशनल १२ लाख टन्स का प्रोडक्शन सेकन्ड प्लान के अन्त तक बढ़ेगा । आंकड़ों के लिए यह कह दें कि गलत हैं, नहीं माने तो....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : हम लोग मानते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो बहुत से मानमीय सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है, यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा !

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खास तौर से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य और बयाना से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन जैसा कहते हैं ठीक है कि बढ़ गया है । अब इतना बढ़ गया है कि इसको थर्ड फाइव इयर प्लान में थोड़ा स्लो कर दें और उसके बजाय जहां १० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था है वहां ८ करोड़ ही रुपया खर्च करें तो भी राजस्थान को घाटा नहीं रहेगा क्योंकि इन्डस्ट्रियली राजस्थान के आगे बढ़ाने की जरूरत है, वह इस वजह से कि एग्रीकल्चरल इकोनोमी वह बेकवर्ड इकोनोमी होती है—

(३ म. प.)

और इस वजह से इन्डस्ट्रियल एडवान्समेंट करने के लिए और पर केपिटा इन्कम बढ़ाने के लिये हम तेजी से आगे बढ़ें तो दो करोड़ रुपये इसमें से कट कर भी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगावें तो यह सही तरीका होगा और राजस्थान की पर केपिटा इन्कम बढ़ेगी । जब तक इन्डस्ट्रियली आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पर केपिटा इन्कम नहीं बढ़गी । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह आर्गुमेंट जितना सिंपल तरीके से रखा गया उतना सिम्पल नहीं है । हमको सब तरह ध्यान देना होगा । हम सब चाहते हैं कि राजस्थान तेजी से आगे बढ़े । लेकिन हमें सारे देश के, पूरे देश के कांटेक्स्ट में देखना होगा। राजस्थान हिन्दुस्तान का एक अंग है । इसी प्रकार से दूसरे प्रान्त भी हिन्दुस्तान के अंग हैं । सभी अलग अलग प्रान्तों को मिलाने से हिन्दुस्तान बनता है । हिन्दुस्तान आज भी खाद्य के मामले में सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है करोड़ों टन अनाज आज भी बाहर से मंगाना पड़ता है एग्रीकल्चरल पोटेन्शियलिटी को ज्यादा बढ़ाना इसलिये जरूरी है कि हम खाद्य के मामले में सेल्फ सपोरटिंग हो जावें ! इन्डस्ट्रियल एडवान्समेंट से पर केपिटा इन्कम बढ़नेका फायदा जरूर होगा लेकिन हमको इस नेरो दृष्टिकोण से बायान नहीं देना चाहिये । इस दृष्टिकोण से सोचना सही तरीका नहीं होगा । आज भी हमारे प्रधान मंत्री और दूसरे नेता इस बात को मानते हैं कि इन्डस्ट्रियली हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिये लेकिन साथ साथ खेती का उत्पादन भी कम से कम इतना बढ़ाना चाहिये कि जिससे हम सब का पेट भर सके । सारे स्ट्रक्चर को इन्डस्ट्रियली आगे बढ़ाने के पहले हमको यह जरूर करना होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जरिये हम अपनी नीड को पूरा कर सकें; खाली खाने के मामले में ही नहीं बल्कि उसके अलावा जितना रॉ मेटीरियल आवश्यक है; जैसे शुगर है, कॉटन है वह काफी मात्रा में एग्रीकल्चर के जरिये उपलब्ध नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे और वह भी एक स्टेट में नहीं, सारी स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन करके उपलब्ध करेंगे तो हमारा जो प्लान है और जितना इन्डस्ट्रियल इजेक्शन हम करना चाहते हैं उतना कर सकेंगे वरना नहीं कर सकेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर सब मामलों में बेस है । इसी वजह से हमने १८ लाख टन का एडीशनल टार्गेट रखा है और इसकेलिये हमने १०करोड़ रुपयों का अलग प्रावधान रखा है जिसका अलग अलग ब्रेक अप माननीय सदस्यों के पास है जिसमें बताया है कि कितना सीड में खर्च करेंगे, कितना एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खर्च करेंगे, कितना फर्टिलाइजर्स में खर्च करेंगे और कितना सॉयल इम्प्रूवमेंट में खर्च करेंगे। इनके डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। नोट के साथ में जो अपेन्डिक्स आपके पास भेजे हैं उसमें लिखा है कि हमको १८ लाख टन एडीशनल फूड प्रोडक्शन कैसे कर सकेंगे? जो १८ लाख टन प्रोडक्शन का टार्गेट रखा है वह १० करोड़ रुपये ज्यादा मिलने से अचीव कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी अचीव हो सकता है लेकिन इस बारे में अभी कहने की जरूरत नहीं है लेकिन यह कहना जरूरी है कि हिन्दुस्तान के कांटेक्स्ट में हमें सारी चीजों को देखना चाहिये। यह कहना कि इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन को बढ़ाया जाय, लैंड पर से प्रेशर कम किया जाय, ठीक नहीं होगा क्योंकि राजस्थान अकेला यह काम नहीं कर सकता। देश की इकोनोमी जब ऐसी हो जाय कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेल्फ सपोर्टिंग हो जाय उसके बाद इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट में राजस्थान को हिस्सा मिले तो वह सही बात होगी।

दूसरी बात यह है कि हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में कम होता है। जैसा आप कहते हैं कि २ करोड़ कम कर दें और १८ लाख टन एडीनशल हो जाता है तो उसका प्राइसेज़ पर प्लान पीरियड में क्या असर पड़ता है, प्रोडक्शन कम होता है

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): यह किसी ने नहीं कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है। आप यह कहते हैं कि जब ४ करोड़ रुपये थे तब ८ लाख टन से ११ या १२ लाख टन प्रोडक्शन हो गया और अब रकम दुगुनी कर दी जाय उसी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ सकता है यानी २२ लाख टन प्रोडक्शन बढ़ सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको इतना सिम्पल नहीं मानना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह: आप इसको कॉम्पलीकेटेड कैसे बनाते हैं। आप यह बता दीजिये कि साढ़े चार करोड़ थे तब आपने ८ लाख टन से ११ लाख टन कर दिये। अब आपने रकम १० करोड़ कर दी तो आप १८ लाख टन प्रोडक्शन करेंगे....

श्री नाराम मिर्धा : मेरे ख्याल से यह केल्कुलेशन भ्रम में डालने वाला है।

श्री श्रीभानसिंह : आप समझाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि प्लान में टोटल रकम को दुगुना इसलिए रखा जाता है कि पर केपिटा इन्कम दुगुनी करनी है। पहली पंचवर्षीय योजना १०० करोड़ की थी और दूसरी २०० करोड़ की रखी गई और तीसरी ३०० करोड़ की रखी गई, यही हाल सेन्टर का है। आप डबलिंग को ध्यान में रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका ख्याल है कि साढ़ चार करोड़ रुपयों से ८ लाख टन से बढ़ा कर १२ लाख टन प्रोडक्शन कर दिया ....

श्री श्रीभानसिंह : आपके कहने के मुताबिक।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते हैं कि अब आप क्योंकि एडीशनल १० करोड़ रुपया रख रहे हैं इसलिए १८ लाख टन से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे क्योंकि साढ़े चार करोड़

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से ८ लाख टन से बढ़ा कर १२ लाख टन कर लेंगे इसलिये १० करोड़ रुपये से प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की दलील सही नहीं है । इसका मतलब यह है कि हमने १० करोड़ का खर्चा आइटमवाइज़ रखा है । आप यह बतावें की यह आइटम काट दीजिये और फिगर बढ़ाइये तब तो मैं अच्छी तरह से जवाब दे सकता हूं । हमने बराबर हैड्स बताये हैं । कितने कुएं खोदेंगे, कितने पुराने कुओं की मरम्मत करावेंगे, कितने नये कुओं में पांम्पिंग सेट लगायेंगे, कितना नया सीड देंगे, कितना फर्टिलाइज़, देंगे इन सब का इस प्लान में जिक्र है । इतना फिज़िकल टार्गेट पूरा करने से इतनी जमीन का इम्प्रूवमेंट इस तरह से होगा और प्रोडक्शन बढेगा । आर्बिट्रेरिली यह कह दें कि साढ़े चार करोड़ से १२ लाख टन हो गया इसलिये १० करोड रखने से १८ लाख से ज्यादा हो जायगा, सही नहीं होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : आपका कॉम्पलीकेटेड केल्कुलेशन समझ में नहीं आया कि आप क्या बता रहे है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी समझ में नहीं आया हो, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के समझ में आ रहा है । इस वजह से १० करोड़ का प्रोवीजन रखा है ।

श्री श्रीभानसिंह : ये माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री हरिप्रसाद यादव(वल्लभनगर—स.): उनको मैं फिर समझा दूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो एग्रीकल्चर के लिये १० करोड़ का जो प्रोवीजन रखा है उससे राजस्थान की एग्रीकल्चरल पोटेन्शियेलिटी बढ़ेगी ।

दूसरी ओर इस बात का जोर दिया गया कि माइनर इर्रिगेशन के लिये ज्यादा रखना चाहिये क्योंकि उनका परिणाम तुरन्त आ सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कहना चाहता हूँ कि माइनर इर्रिगेशन के तीन टुकड़े हैं । एक तो वह है जो डेवलपमेंट के हैड में आता है और पंचायतों के अन्डर में है

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माइनर इर्रिगेशन के लिए सेपरेट मिनिस्टर हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास इसका जो हिस्सा है उसी को मैं डील करूंगा ।

वह माइनर इर्रिगेशन का हिस्सा, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, वह है, जो नये कुएं बनाने के लिए तकावी देने की बात है, पुराने कुओं की मरम्मत करने के लिए तकावी देने की बात है और उसके बाद वे टैंक, जिनकी २५ हजार तक की वेल्यू है, और जिनको पंचायत समिति एक्ज़ाक्यूट करती हैं, उसके अन्दर आधा रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी के रूप में देता है और आधा रुपया पंचायत समिति श्रमदान के रूप में लगाती हैं । वह पैसा जो एग्रीकल्चर हैड में रखा है, वह करीब ३८० लाख रुपया है और उसमें कुओं के लिए दो करोड़ रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा है । पहली पंचवर्षीय योजना, नहीं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रोवीजन था, वह १४१ लाख रुपयों का था और उसके बजाय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

१६० लाख रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च करेंगे और अब तो वह फिगर और बढ़ रहा है क्योंकि जैसी दो तीन दिनों में चर्चा सुनाई दी कि सेकिंड फाइव इयर प्लान के दौरान में माइनर इर्रिगेशन में कुओं को बनाने के लिए ७५ लाख रुपये ओवर एन्ड अबव सीलिंग, इसी साल, इसी पंचवर्षीय योजना में और दिये हैं, जब कि हमने एक करोड़ रुपये की मांग और रखी थी तो ओवर एन्ड अबव सीलिंग हमको ७५ लाख रुपया नये कुए के लिए खर्च करने के लिए दिया है राजस्थान की सरकार को, क्योंकि कुओं की बहुत युटीलिटी है और इसके परिणाम तुरन्त आ सकते हैं; परिणाम आया भी है, इसलिए भी इसमें ज्यादा प्रोवीजन होना चाहिए। मैंने बताया कि सेकिंड फाइव इयर प्लान में जो प्रोवीज़न था, उससे भी ज्यादा हमने खर्च किया है और जो रुपया इस साल और आयेगा, उसको खर्च किया जायगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर में ३.८० लाख रुपयों का प्रोवीजन इसमें रखा गया है, जो कि पहले के प्रोवीजन को देखते हुए काफी बड़ा प्रोवीजन है, करीब दुगुने से ज्यादा है और यह प्रोवीजन इसकी इम्पोर्टेन्स और महत्व को देखते हुए ही रखा गया है। माइनर इर्रीगेशन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में चार करोड़ रूपया खर्च करने का प्रोवीज़न है, जिसके लिए कि ब्लॉक्स में 'सर्वे' हो रही है और उसके एग्ज़ीक्यूशन के लिए हमारा डिपार्टमेंट फाइव इयर प्लान के पहले वर्ष में तैयार रहेगा। जो चार करोड़ रुपयों का प्रोवीजन रखा है माइनर इर्रिगेशन के लिए, वह ७ करोड़ ८० लाख रुपये का प्रोवीजन बन जाता है। वह कम्पेरेटिवली दूसरे फिगर्स को देखेंगे, प्लान के दूसरे प्रोवीड़न्स होंगे, उनसे काफी बड़ा प्रोवीजन है।

तीसरा पोइन्ट जिस पर काफी जोर दिया गया है और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस पर काफी जोर दिया है, वह एनीमल हस्बेन्डरी है। एनीमल सेक्टर, वे देखते हैं, काफी बढ़ गया है और उसको ज्यादातर इन्डस्ट्रीज़ की तरफ जोड़ देने की दलील दी है। अभी जो प्लान बोर्ड की मीटिंग हुई थी, यह पोइन्ट उन्होंने उसके सामने कहा और इस सदन में भी कहा। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये....

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य ने कहीं कुछ बात कही है, वह इस सदन में कहने की है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे नहीं कहा, प्लान बोर्ड राजस्थान का इम्पोर्टेन्ट बोर्ड है....

श्री श्रीभानसिंह : नहीं, यह नहीं कह सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझको नहीं कहा, प्लान बोर्ड के सामने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : The reference should not be made in the House of whatever is said outside the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां की बात ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्ष

(श्री नाथूराम मिर्धा)

महोदय, मैं आपके जरिये उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान एनीमल हस्बेन्डरी की, मेरे ख्याल से, पोटेन्शियलिटी को कम इम्पोर्टेन्ट महसूस करते हों, जैसा सदन के बहुत से माननीय सदस्य समझते होंगे और एक दो ने कहा भी है और कुछ आगे बोलने वाले माननीय सदस्य कह सकते हैं कि वे क्या महसूस करते हैं। इस बारे में, आपके जरिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर देना चाहिता हूं कि पशुधन राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेन्ट, ज्यादा आमदनी करने वाला, आमदनी का पूरक है, जो उनकी आमदनी को बढ़ाता है ...

श्री चन्दनमल वैद : चूरू जिले में मुख्य है, पूरक क्या है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, मुख्य है। मैं आपके जरिये निवेदन कर देना चाहता हूं और नागोर जिले का ही इन्स्टान्स रखता हूं कि वहां एक साल में तीन बार मेला भरता है, उन तीन मेलों के जरिये जो लोगों की कुल आमदनी होती है, वह पंच करोड़ और छः करोड़ के बीच में होती है। वह आमदनी एक आदमी को नहीं होती है, बल्कि वहां किसानों की पांच लाख फेमिलीज़ हैं, उन सब में बंटती है। यह एक प्रकार की कॉटेज इन्डस्ट्री है, जिसकी वजह से पांच करोड़, छः करोड़ का बंटवारा पांच लाख फेमिलीज़ में करीब करीब बराबर रूप में बंटता है और पंजाब, यू. पी. या आसपास के दूसरे प्रोविन्सेज़ हैं, उन प्रोविन्सेज़ की खेती बाड़ी को तरक्की मिलती है और उनको आमदनी होती है। मैंने यह एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान एनीमल हस्बेन्डरी के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में प्रीमिअर स्टेट है। इस बात को स्वीकार राजस्थान के लोग करें या न करें....

श्री भैरोंसिंह : करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह उनके सोचने की बात है, पर हिन्दुस्तान में यह बात मान्य है कि एनीमल हस्बेन्डरी के पोइन्ट पर राजस्थान प्रीमिअर स्टेट है। राजस्थान को एनीमल हस्बेन्डरी से एक साल में जो एक्सपोर्ट करने से आमदनी होती है, वह करीब २० करोड़, २५ करोड़ के करीब होती है। एनीमल हबेस्न्डरी का सारा टोटल प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होता है, उससे २५ करोड़ की आमदनी होती है, वह राजस्थान को होती है...

श्री भैरोंसिंह : २५ करोड़ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लेटेस्ट फिगर्स मैंने बताये हैं। बोन्स, हड्डियां, क्रीम, मिल्क, भेड़, मांस आदि जो बिकता है, बैल जो बिकते हैं, इन सारी चीजों की कुल आमदनी है, वह आमदनी २० करोड़, २५ करोड़ है, यह पिछले पांच साल का औसत रहा है। इसी तरह जो राजस्थान में ब्रीड है, गाय, कैटल, की ब्रीड़, इनकी इम्प्रूव्ड ब्रीड, घोड़ों की इम्प्रूव्ड ब्रीड, ऊंट की इम्प्रूव्ड ब्रीड, जो सिलेक्टेड ब्रीड, अपग्रेड ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, पौल्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें जितनी स्कीम आप देखेंगे, जो सात करोड़ का प्लान बनाया है, उस सात करोड़ में जितनी स्कीम है, डेयरी की स्कीम है, कुछ और स्कीम्स हैं, वे भारत सरकार की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कोस्ट पर राजस्थान के अन्दर हैं। वे स्कीम कम नहीं है, वे करीब करीब २४०.८० लाख की स्कीम्स हैं, उनका सेन्ट पर्सेन्ट खर्च भारत सरकार दे रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्कीमें हैं, जो हमारी और भारत सरकार की मिली–जुली हैं और उनके ऊपर जो टोटल खर्चा है, उसमें से १३६ लाख रुपया का खर्चा भारत सरकार का हागा और १४६ लाख हमारा खर्चा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ स्कीस हैं जो प्योरली स्टेट बेसिस पर चलती हैं। इस प्रकार जो टोटल एक्सपेन्डोचर पाच वर्ष के अन्दर राजस्थान अकेला खर्च करने जा रहा है, एनीमल हस्बेन्डरी के लिए, वह १७४ लाख रुपया है। कुल मिला कर सात करोड़ का खर्चा है, जिसका प्लान आपके सामने है, इसमें ३८० लाख रुपया भारत सरकार का खर्चा है और स्टेट का खर्चा है ३२० रुपये। इस डिपार्टमेंट से राजस्थान को इतनी बड़ी आमदनी है और इतने बड़े स्केल पर लोगों को फायदा डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके लिए फर्स्ट प्लान में बहुत कम ध्यान दिया गया, २८ लाख का टोटल प्लान था, उसमें शार्ट फॉल रहे, क्योंकि कई काम हम कर नहीं पाये, हम तैयार नहीं थे, उसमें से २३ लाख रुपये खर्च कर पाये। सेकिंड प्लान में दो करोड़ का प्रोवीजन था, उसमें इतना रुपया खर्च कर दिया जायगा। इसके अलावा दूसरे महकमों के शार्ट फॉल हैं, उनको युटीलाइज़ इस महकमे ने किया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे काफी आमदनी राजस्थान को और उन सब को होती है, जो कि इक्वीटेबली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका सात करोड़ का प्लान रखना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज भारत सरकार की इस प्रकार की डिपार्टमेंट के लिए ऑफर्स मौजूद हैं कि सेन्ट्रल स्कीम में और रुपया ले लीजिये, जोइन्ट स्कीम में और रुपया ले लीजिये, राजस्थान के एनीमल हस्बेन्डरी के लिए सात करोड़ रुपया नहीं, १४ करोड़ रुपया ले लीजिये, तब तक रुपया देने को तैयार है। यह दिक्कत है कि राजस्थान की सीलिंग में फिट इन होना मुश्किल हो रहा है। अब माननीय सदस्यों के सोचने की बात है कि इसको अधिक दिलाया जाय और लोन की कोशिश की जाय, या इसको कम किया जाय। कई जगहों में जहां आप ज्यादा मांग रहे है, उसमें कमी होगी और जहां ज्यादा मिलने की गुन्जाइश है, वहां कम कर दें, उसको काट दें, तो फिर प्लान की कैसी तस्वीर बनेगी, कैसा प्लान बनाना चाहते हैं ? मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं, मैं सदन की जानकारी के लिए यह बात कहना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि जैसा आपने बताया २५ करोड़ की आमदनी हुई....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member to please......

श्री भैरोंसिंह : आपकी आज्ञा से, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फिर जानकारी दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यह आमदनी पांच वर्ष में होती है या प्रत्येक वर्ष होती है ?

Page No.89

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रत्येक वर्ष ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान का बजट कितना है, जिसमें एनीमल हसबेन्डरी की आमदनी आप २५ करोड़ कहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसके ब्रेक अप दे सकता हूं। मेरी जो इसके बारे में जानकारी है वह यह है कि २० करोड़, २५ करोड़ के बीच राजस्थान को एवरी इयर इन्कम होती है। यह अगर आप चाहें तो बता सकता हूं कि किस किस हैड में होता है । मैंने यह ब्रोड आउट लाइन आपके सामने रखी है।

एक बात कोऑपरेटिव की रह गई है। उसका ५ करोड़ का है । कुछ डिसीज़न्स इस संबन्ध में हमको लेने हैं श्रीनगर की मीटिंग में।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Hari Prasad will not disturb the House and I will request the whip of the House to fix up his seat somewhere. He is changing his seat :from one place to another.

श्री भैरोंसिंह : Probably he has not understood what you have said, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी रिपोर्ट जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के सम्बन्ध में मेहता कमेटी ने दी है उसको आपने अखबारों में देखा होगा। भारत सरकार ने उसे करीब करीब एक्सेप्ट कर लिया है। इसके हिसाब से स्टेट सैक्टर में एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, फिर भी ५ करोड़ का टेन्टेटिव प्रोग्राम होगा जिसको फिज़िकल टार्गेट रखा है कि जिससे रूरल जनता को ८० पर्सेन्ट तक ले जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यह ५ करोड़ रुपया कोई इसके लिए ज्यादा नहीं है। मैंने कहा है कि यह subject to revision है। आगे चल कर इसका क्या नक्शा होगा वह आपके सामने बाद में आवेगा । यह एक एग्रीकल्चरल इम्पलीकेशन है और इसके लिए पोटेन्शियेलिटी मोजूद है और हम एचोव करना चाहते हैं वह कर पायेंगे । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन सारी बातों को समझ गये होंगे और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार सदन में रखेंगे ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है और उसमें अभी माननीय कृषि मन्त्री ने जो क्लेरीफिकेशन दिया है वह वाजिब है और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारी इकोनोमी की बैक बोन एग्रीकल्चरिस्ट है; लेकिन हमारे यहां खेती को सबसे अच्छा पहले से ही माना है और कहावत है : "उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान" । एग्रीकल्चर हमारे यहां का मुख्य धन्धा रहा है। मैं राजस्थान के गांवों की बात आपको बताऊं तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान के गांवों में लोग ७६.६० प्रतिशत खेती पर आधारित हैं और इसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर खेती के माध्यम को रखा है वह ठीक है। हमने इस मामले में अपने टार्गेट

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को पूरा कर लिया हैं और हमने अधिक अन्न का उत्पादन किया है लेकिन मैं समझता हूं कि हमें यह सोच कर कि हमने अपने अन्न उत्पादन के टारेंट को पूरा कर लिया है, निश्चिन्त होकर नहीं बैठना चाहिये, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। हम खाद्यान्नों में अपने आप निर्भर हैं लेकिन हमको हमारे देश के सामने खाद्यान्नों की जो समस्या है उसको भी देखना है। ऐसी हालत में राजस्थान का परम कर्तव्य है कि राजस्थान में यदि हम खाद्यान्नों को बढ़ा सकते हैं तो हमें अधिक बढ़ाना चाहिये। राजस्थान में अभी भी बहुत सी जमीन है जिनको हमें बुक आउट करना है। ठीक है, हमने ५० हजार एकड़ ठीक की है और हमारे यहां उससे पैदावार बढ़ी है। मैं यह कहूंगा कि अभी भी बहुत जमीन ऐसी है जो पड़ी है, जिसको देने की समस्या है। हमें काश्तकार की जो समस्या है उसकी ओर ध्यान देना है तो हमें बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा और तभी हमारी पैदावार बढ़ सकती है। जो प्लान हमारे सामने आया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का और दूसरी पंचवर्षीय योजना का, उसी अनुरूप से इस बात को लेकर आगे बढ़े हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज आजादी और प्लानिंग के १० वर्ष बीत जाने के बाद भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार की तरक्की हमको दिखाई देनी चाहिये वह नहीं दिखाई देती है। मैं यह कहूंगा कि हमारे प्लानिंग का आधार बहुत गलत है। वह यह है कि हम शहरों की बातों को सोच कर चलते हैं और गांवों का ध्यान नहीं रखते हैं। मेरा यह निश्चित मत है और बार बार कहता आया हूं कि जब तक ग्रामों की योजना नहीं बनाएंगे देश का विकास नहीं होगा। राजस्थान में जब हम देखते हैं कि हमारे यहां कितने गांव हैं तो मालूम होगा कि राजस्थान में बहुत गांव हैं और मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पूरे ग्रामों की संख्या २१,७०४ है और इन गांवों में बसने वाले लोगों की संख्या जन-संख्या के टोटल का काफी अनुपात है। जब हमारे गांवों में लोग रहते हैं उन पर उसी अनुपात से पैसा खर्च नहीं होता है। आज आजादी के १४ वर्षों के अन्दर भी प्लानिंग के लिए सरकार पैसा गांवों में खर्च नहीं कर सकी और प्लानिंग के लिए टैक्स लगाना पड़ता है, वह उन लोगों पर लगाना उचित नहीं होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजधानियों के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। उनका विकास हो रहा है और मेरा दावा है कि सारी योजनाओं को हमारे गावों के विकास के आधार पर बनाना चाहिये, जहां पर हमारी बहुत सारी जनता रहती है और जहां पर विकास नहीं हो रहा है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब हम वर्षा के समय गांवों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर दल दल है और जाने के लिए कोई सड़क नहीं, न कोई रास्ता है, न वहां के लोगों के लिए पाठशाला है, न कोई मास्टर के रहने के लिए मकान है और न शिक्षा का भवन पाठशाला के लिए है। यह सारी प्राथमिक आवश्यकता है जो ग्रामों में रहने वाले लोगों को मिलनी चाहिये, जो नहीं मिलती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और अब हमारी सरकार भी २० करोड़ के

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नये टैक्स लगाना चाहती है, और पहले भी १२ करोड़ के टैक्स लगाये थे। मैं यह कहूंगा कि ग्रामवासियों ने भी उन टैक्सों को देने में भाग लिया है। जो उनका फर्ज था उसको उन्होंने अदा किया है लेकिन आज इस योजना में उसके पास उसका कोई फल नहीं पहुंचा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे सड़कों की बात थी। आपने सड़कों के लिए पैसे रखे। आपने जिला सेन्टर केन्द्र से मिलाने की बात कही, मैं यह कहूँगा कि यह बहुत अच्छी बात है आपको मिलनी चाहिये लेकिन मैं साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि आपको इस प्लानिंग में ध्यान देना चाहिये कि गांवों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए तो कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। मैं इसके लिये एक नया सुझाव देना चाहता हूं कि यदि हम छोटे २ गांवों को मिलाने के लिए दो फुट की जिस प्रकार से पगडन्डी होती है उसी तरह से पगडन्डी बना दी जावे तो वे लोग बरसात में कहीं भी आ-जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गांवों में बरसात में नहीं जा सकेंगे। जब तक गांवों में सड़कें बनें तब तक के लिए यह रखना बहुत जरूरी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने गांवों के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

इसके अलावा आज हम गांवों में देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जंगलों की लकड़ी की आती है। किस तरह से जंगल आज काटे जा रहे हैं उनको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस प्रकार से यदि वन काटे गये तो गांव के काश्तकारों को लकड़ी नहीं मिलेगी। आज सरकार ने कुछ टार्गेट रखा है। मैं सुझाव दूंगा कि काश्तकार के लिए काम में आने वाली लकड़ी की योजना में कुछ रखा जाना चाहिये। जिस तरह से काश्तकार के काम में आने वाली चीजें हैं उसकी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिये। अभी माननीय मन्त्री ने छोटी सी मिसाल दी और कहा है कि सरकार ने छोटी छोटी योजना पर ध्यान दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हम छोटी २ योजनाओं पर प्रारम्भ से ही चलते तो काफी प्रगति कर सकते थे; कारण, इन बड़ी योजनाओं पर बड़ा खर्चा होता है। ये बड़ी सिंचाई योजनायें दीर्घ कालीन होती हैं और इनको पूरा करने में बड़ा समय लगता है। इनके निर्माण में पांच-सात वर्ष खर्च हो जाते हैं। बाद में जाकर योजनायें बनती हैं। उनका लाभ भी लम्बे अर्से के बाद मिलता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे उधर चम्बल योजना को लिया गया है। इससे अगले साल पानी आवेगा। पानी दिया गया तो उससे वाटर लोगिंग की वहां पर समस्या उत्पन्न होगी, गांव वालों के सामने जब यह समस्या आवेगी तो हो सकता है कि सीमेन्ट कॉन्क्रीट करें और चाहे पम्प के जरिये से उस पानी को फैंके, हो सकता है कि यह समस्या न भी आवे। यह तो मानना पड़ेगा कि यह बहुत बड़े खर्च की योजना है। यदि इतना ही रुपया उन छोटी योजनाओं पर लगा देते तो आज हम देखते कि गांव गांव में, खेत खेत पर कुए होते और काफी एकड़ जमीन उनसे सींची जा सकती थी। वैसे नहरों के खोदने में ही काफी जमीन समाप्त हो जाती है। जो नहीं होती। मेरा तो दृष्टिकोण छोटी छोटी योजनाओं की ओर रहता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। मैं मानता हूं कि सिंचाई का युग एक स्वर्णिम युग के नाम से इतिहास में पुकारा जावेगा। यदि उन योजनाओं से निश्चित रूप से लाभ हुआ तो हमारा राजस्थान प्रोग्रेस करेगा और विकास की दृष्टि से आगे

(३.४० म० प०)

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

बढ़ेगा। मै इस सम्बन्ध में यह बात अवश्य कहना चाहूँगा, जो उचित भी है कि सिंचाई की दृष्टि से जितनी योजनायें हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अन्य २ विभागों के द्वारा ये योजनायें चलाई जाती हैं। उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया है। अलग अलग विभाग उनको चलाते हैं। जैसे जहां जंगल में सड़कों का प्रश्न आता है तो जंगल विभाग, वन विभाग उसको बनाता है, नहर के आस-पास जहां सड़कों का सवाल आता है तो उनको सिंचाई विभाग बनाता है और अन्य सड़कें हैं वे पी. डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा बनाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि ओवर लेपिंग खर्चा होता है और जहां पर बननी चाहिये वहां पर नहीं बन पाती हैं। सड़कों के ऊपर रुपया कम रखा गया है। आज इस बात की पूरी २ आवश्यकता है कि गांव गांव के आदमी शहरों में आ सकें, उनकी पैदावार शहरों तक अच्छी तरह से आ सके जिससे उनके यहां का व्यापार बढ़ सके। आज राजस्थान मेंजिस प्रकार से उपज बढ़ी है, पैदावार राजस्थान में बढ़ी है उसके बाद भी लगता है कि जो पैदा करते हैं उनके पेट में वह अन्न न जाकर दूसरे लोगों के पास वह चला जाता है। काश्तकारों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है। जो ताकत उनकी क्रय की बढ़नी चाहिये थी वह नहीं बढ़ी है। यदि उस क्रय शक्ति की ओर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो हमारा राजस्थान विकास नहीं कर सकता। किसी काश्तकार के पास या तो एक एकड़ जमीन है और किसी के पास ज्यादा है। किसी के पास इतनी सी जमीन है जिससे उसका पेट नहीं भरता है और किसी के पास इतनी जमीन है कि जिससे वह एक्सपोर्ट करता है। एक प्रकार की काश्तकार काश्तकार में विषमता पैदा हो गई है। जब तक भूमि-कानून को, सीलिंग को हम पूरी तरह से राजस्थान में लागू नहीं कर देंगे और इस प्रकार की विषमता को खत्म नहीं कर देते हैं तब तक हम हर आदमी को आजीविका नहीं दे सकते। काश्तकार ही जमीन पर मालिक रहे, उसको इस बात की निश्चिन्तता दी जाय जिससे कि पर्याप्त पैदावार उसको हो सके और वह अपना पेट भर सके। भूमि सुधार द्वारा यह चीज़ हमको काश्तकारों को जल्दी ही देनी होगी। चाहे पैदावार कितनी ही बढ़ जाय, गांव के किसान, मज़दूर और खेतिहर लोग हैं उनकी यदि क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है, पैसा यदि उनके पास पूरा नहीं आता है तो केवल कृषि का उत्पादन बढ़ना अच्छा नहीं रहेगा।

बिजली राजस्थान में भाखरा और गांधीसागर बांध से आ रही है। फिर भी उससे राजस्थान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राणाप्रताप सागर का काम शुरू हो रहा है। उसकी ओर और जल्दी ध्यान देना चाहिये जिससे कि उससे बिजली की आवश्यकता पूरी हो सके और उस बांध को पूरा करने के लिए इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिये कि जिससे औद्योगिक क्षेत्र आगे बढ सकें।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जहां तक राजस्थान के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र की बात है राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है और इस दिशा में हमको प्रगति करनी पड़ेगी। उनसे पहले इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे साधन क्या हैं और उनके द्वारा हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान में सब ही तरह के खनिज मिल सकते हैं। तृतीय योजना में पढ़ा है कि कपास की खेती में गिरावट आयी है। जमीन पहले से काफी कल्टीवेशन में आयी है, तब भी यह कहा जा रहा है कि कपास की पैदावार गिर रही है। जब कपास की पैदावार गिर रही है तो यह देखा जाना चाहिये कि किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं। यदि कपास और गन्ना आदि की पैदावार में गिरावट आ रही है तो उनकी उन्नति में ध्यान देना चाहिये।

जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है हमको इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि राजस्थान का ही नहीं केन्द्र का भी पैसा खादी की ओर लग रहा है, ग्रामोद्योगों की ओर पैसा नही लगा रहे हैं। इसमें ग्रामोद्योगों के लिए कुछ पैसा रखा गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वह पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। गांव के काश्तकार का काफी समय फ्री रहता है। यदि आंकड़े बताऊं तो आपको वह ज्ञात होगा कि साल में कम से कम तीन महीने एक काश्तकार बिल्कुल फ्री रहता है। काश्तकारों की आजीविका की पूर्ति के लिए छोटे २ उद्योग शुरू किये जांय तो काश्तकार की जो आज उन्नति नहीं हो रही है, उनकी जो क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है, तो वह आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि काश्तकारी बेकवर्ड इकोनोमी है, वह दूर हो जायगी। काश्तकारी के साथ साथ छोटे २ उद्योग बराबर चलते रहने चाहिये। आज हम देखते हैं कि जितने उद्योग आज हमको गांवों से मिलते हैं उतने शहरों में नहीं मिलते हैं, जुलाहे हैं वे आपको आज गांवों में मिलेंगे, शहरों में उतने नहीं मिलेंगे, बांस आदि का जो काम करने वाले हैं जितने आपको आज वे गांव में मिलेंगे उतने शहर में नहीं मिलेंगे। आपके गांवों में हर प्रकार के उद्योग मिलेंगे जो सदियों से प्राकृतिक साधनों पर चलते आये हैं। आज उन प्राकृतिक साधनों से चलने वाले छोटे २ उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और न दिया जा रहा हैं; इसलिए इन छोटे २ गांवों में चलने वाले प्राकृतिक साधनों के चलने वाले उद्योगों की ओर ध्यान दिया जाय और काश्तकारों को इस ओर अधिक से अधिक प्रेरित किया जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे यहां बिजली बढ़ रही है; भाखरा, चम्बल, राणाप्रताप सागर से वह बिजली आवेगी उनका उचित उपयोग गांवों में हो सके, पहले से ही उसके लिए योजना होनी चाहिये। इसके लिए हमारे गांवों में छोटे छोटे उद्योग हो सकते हैं। इसके लिए हमको अभी से ही प्रबन्ध कर लेना चाहिये ताकि गांवों में बिजली से चलने वाले उद्योग शुरू हो सकें। हाथ से चलाये जाने वाले उद्योग लाभकर सिद्ध नहीं होते हैं। उनको बिजली से चलाने के लिए प्रबन्ध करें; चाहे हाथ कर्घा हो या दूसरे उद्योग हो। यदि हम तेजी से चलने वाले उद्योगों को लगायेंगे तो उनसे हमारी पैदावार बढ़ेगी और आदमी के हाथ बेकार नहीं होंगे।

जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वह यह है कि आज हम कोऑपरेटिव के बड़े बड़े

(श्री दयाकृष्ण विजय)

फार्म्स बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा देते हैं, लेकिन जो जनशक्ति आज राजस्थान में विद्यमान है उसको काम पर नहीं लगाते हैं और उनको बेकार करके हम बड़े उद्योगों के द्वारा उन्नति करते हैं तो उसको सही माने में उन्नति नहीं कहा जा सकता है । हमारी योजनाओं में यह होना चाहिये कि बिजली से चलने वाले उद्योग चलायें लेकिन यह न भूल जांय कि कहीं हमारे आदमी बेकार न हो जांय, हाथ बेकार न हो जांय । उनकी आय के साधनों को बढ़ाते रहना चाहिये ।

इसमें थोड़ी बदल होनी चाहिये । जहां शहरों की ओर देखते हैं वहां हम गांवों की ओर जाय, जहां बड़े बड़े उद्योगों को लेते हैं वहां छोटे२ उद्योगों को पहले लें, जहां बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं को लेते हैं वहां छोटी २ सिंचाई की योजनाओं को लें । तो हमको बड़े २ टैक्सेज़ भी जनता के ऊपर नहीं लगाने पड़ेंगे । अतिरिक्त आय के जो साधन हैं, पहले जो साधन थे उनसे अधिक लिये हैं इसका कारण यह है कि जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक करने की कोशिश की । इस बार भी ८१.७७ करोड़ बाहरी साधनों से लेना चाहते हैं ।

अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन योजनाओं के कारण अतिरिक्त कर न लगें तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि आज तक जो कर हमने लगाये हैं उसके कारण मैं समझता हूं जरूर कुछ जीवन–स्तर शहरों के लोगों का तो ऊंचा उठा है किन्तु जहां तक गांवों में लोगों के जीवन–स्तर का सवाल है उनमें तो किसी प्रकार की खुशहाली नजर नहीं आती और दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि उन उर टैक्सेज़ का भार बढ़ाते जा रहे हैं । इस प्रकार जहां हम टैक्सेज़ में वृद्धि करते जाते हैं उससे गांवों के साथ किसी भी प्रकार से सामाजिक न्याय नहीं होगा ।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि विकास भी किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा किया जाता है और कुछ को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है । मुझे भी याद है कि हमारे कोटा में पहले कई बड़े बड़े विभाग थे उनको हटाया जा रहा है, वन विभाग तो हटा ही दिया गया है; आबकारी विभाग भी वहां से हटाया जा रहा है । इस तरह की जो नीति है उसमें मेरा यही निवेदन है कि हरएक जिले के साथ न्याय होना चाहिये और जो स्थिति उनकी बनी हुई है उसमें वृद्धि होनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग में भी हमने पैसा रखा है, जो राशि समाज कल्याण के लिये निर्धारित की जाती है वह पंचायत समितियों को सौंप दी जाय, यह मैंने पहले भी कहा था । यदि उनको सौंप दी जाती है तो इस क्षेत्र में काफी काम हो सकता है । आज हमारा समाज कल्याण विभाग जिस प्रकार से रकम खर्च करता है उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो पाता । यदि यह रुपया पंचायत समिति को सौंप दिया जाता है तो वह ठीक प्रकार से उसको उपयोग में ला सकती है ।

इसके अतिरिक्त लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हमने किया । हमने इसके द्वारा गांवों के अन्दर एक चेतना फैलायी है, लेकिन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसके लिये भी पंचायत समिति को रकम नहीं दी है; उसके लिये कहा गया है कि वह अतिरिक्त कर लगा सकती है, अगर आगे बढ़ना चाहती है तो गांव के ऊपर अतिरिक्त कर लगेंगे और उन्हीं के करों से उनकी तरक्की होती है तो यह ठीक नहीं है। यदि इस बारे में जो रकम हमने रखी है वह सारी पंचायत समिति को सौंप दी जाती है और उन्हीं के द्वारा खर्च करने का प्रावधान करते हैं तो उसमें ज्यादा तरक्की हो सकती है। यह कहा जरूर गया कि यह जो प्लान बनकर आया है वह पंचायत समितियों द्वारा बनकर आया है लेकिन मेरा कहना यह है कि पंचायत समिति ने जिस प्रकार से इसमें कार्य किया है, वह एक प्रकार से जल्दी का काम था और जो टार्गेट फिक्स करके भेजे थे उसी के अनुसार उन्होंने करके भेज दिया ज्यादा डिटेल्स में वे जा नहीं सके। इसके लिये बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि सब जगह ग्राम सभायें होतीं और उसमें प्लान के बारे में समझाया जाता और उनको अलग अलग कितना कितना खर्चा हम करने जा रहे हैं यह बताया जाता तब जाकर जो प्लान हमारे सामने आता वह उसके अनुरूप आ सकता था और उनके लिये यह ज्यादा उपयोगी प्रश्न हो सकता था। नया प्लान बनाया उस पर भी पंचायतों को पूरी तरह से राय नहीं ली गई, यह ठीक नहीं किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने डेढ़ गुना श्रम लेना आवश्यक माना है, मैं समझता हूँ वह बहुत अधिक है। चालीस प्रतिशत तो स्टेट से ग्रान्ट मिलेगी और साठ प्रतिशत पंचायत समिति लगाये यह एक तरह से ठीक नहीं है।

राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रान्त है। खनिज के मामलों में हमने हमेशा मोनोपोली सिस्टम को प्रोत्साहित किया है। हमारा राज्य केपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं बने, यह जब हम अपना उद्देश्य रखते हैं तो हमें इस मोनोपोली सिस्टम को दूर कर देना चाहिये। अगर हम खनिज की दृष्टि से देखें तो यहां पर अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ है, सर्वे होने की बड़ी आवश्यकता है। शाहबाद तहसील के अन्दर कई जगहों पर लोहा मिलने की सम्भावनायें हैं, इसके लिये सर्वे की बहुत आवश्यकता है। सेन्टर की ओर से सर्वे हुआ भी लेकिन उसके परिणाम जितने आने चाहिये थे वे सामने नहीं आ पाये क्योंकि वह विशाल तरीके पर नहीं हुआ इसलिये सर्वे वहां का कराया जाना निहायत आवश्यक है।

पशुपालन योजना का सवाल है; बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य केन्द्र या दूध वितरण की योजना का सवाल था। इसी प्रकार की कई योजना थी लेकिन उसमें प्रगति नहीं कर पाये। इस दिशा में कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि शहरों के अन्दर उनके द्वारा ये कार्य हो सकें।

राजस्थान के अन्दर सब से अधिक केटल है; हिन्दुस्तान का २५ प्रतिशत केटल हमारे राजस्थान में है। इतना होते हुए भी जहां पशु चिकित्सालय का सवाल आता है उसका अभाव हम बड़े बड़े कस्बों में भी देखते हैं। कहीं पर एक कम्पाउन्डर को रख दिया, वह उससे काम चलाता है। इसलिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जब कभी पशुओं में बीमारियां फैल जाती हैं तो बड़े बड़े चिकित्सालय के अभाव के कारण बीमारी को रोकने में काफी समय लग जाता है और इस बीच काफी पशुओं की हानि हो जाती है। इसके लिये हमें चल चिकित्सालय भी कायम करने होंगे जो कि समय आने पर गांवों के अन्दर चिकित्सा सहायता एकदम पहुँचा सकें। इस तरह से हमें पशु चिकित्सालयों की तरफ भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जहां आदमियों के लिये बड़े बड़े चिकित्सालय खोलते है तो वहां हमें पशुओं की चिकित्सा की तरफ काफी बहुत ध्यान देना होगा।

इसके अतिरिक्त अभी अभी मैंने अनुभव किया कि हमारे यहां चारे की भी बहुत समस्या है। अभी अभी कुछ दिनों पहले जब वर्षा नहीं हुई थी उस समय लोगों ने अपने पास का सारा स्टॉक खिला दिया और वे गांव से बाहर पशुओं को ले जाने के लिये तैयार हो गये। चारे की समस्या भी हमारे यहां विकट है, इसके विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। आज हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर पर-पशु कितना चरागाह है? हमारे यहां चरागाहों की सब से बड़ी कमी है। पशुओं के लिये चारे का स्टॉक हमेशा रिज़र्व की तौर पर होना चाहिये।

हम इसमें संस्कृत शिक्षा के लिये देखते हैं कि बहुत बड़ी रकम नहीं रखी गई है, आठ लाख रुपया जो रखा गया है वह बहुत कम है। संस्कृत के महत्व को आज बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि पहले जहां हाई स्कूल में संस्कृत को ऐच्छिक विषय की तौर पर रखा हुआ था वहां हायर सेकन्डरी में इसको हटा दिया गया है; उसमें संस्कृत के लिये किसी प्रकार का प्रावधान नहीं। मेरे पास भीमगंज मन्डी के कुछ छात्र आये थे और वे कहने लगे कि हम संस्कृत हायर सेकन्डरी में लेना चाहते हैं। किन्तु उनके यहां संस्कृत पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं। जहां पर कि २०, २५ छात्र संस्कृत पढ़ना चाहते थे फिर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इसलिये हमें संस्कृत की तरक्की को ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

आयुर्वेद के लिये ८० लाख रुपया रखा गया जो बहुत थोड़ा है। आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बहुत सस्ती और सुलभ है। आज गांवों के अन्दर हम जाते हैं, वहां भी हमें चिकित्सा का प्रबन्ध दिखाई नहीं देता। लोग दौड़ दौड़ कर बड़े बड़े कस्बों की ओर जाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को उन्नति के लिये हम ज्यादा से ज्यादा रकम रखें। कम से कम प्रत्येक गांव में जिसकी आबादी एक हजार की हो वहां पर एक वैद्य तो प्रोवाइड करें। आज हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर वैद्यों का बिल्कुल अभाव है, एक भी वैद्य नहीं है। इस तरह से हम टार्गेट फिक्स करते हैं तो आयुर्वेद की उन्नति काफी हो सकती है।

सड़कों की हालत को देखें तो वह भी बहुत गिरी हुई है, उसके लिये भी बहुत पैसा रखने की आवश्यकता है। पुराने जो पुलिया बने हुए हैं उनके कारण भी इतने रास्ते रुक जाते हैं कि उनको ऊंचा करना बहुत आवश्यक है। कोटा और बारां को जाने वाली

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सड़क और बारां से शाहबाद को मिलाने वाली जो सड़कें हैं उन पर जो पुलिया बने हुए हैं वे इतने नीचे हैं कि बरसात के दिनों में काफी समय तक रास्ते रुके रहते हैं हालांकि ये पुलिया छोटे हैं उनको ऊंचा उठाने की बहुत आवश्यकता है ताकि आवागमन में किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसके लिये भी प्रावधान होना जरूरी है।

(४ म० प०)

तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारे प्लॉन का काफी पैसा ऐसे कामों में लगाया जा रहा है कि जिनकी शायद आज अधिक आवश्यकता नहीं है। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के जितने तीस–इकत्तीस हजार गांव हैं उनकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय। आज हमारी पहली और दूसरी योजनाओं का जो पैसा लगा उसमें से इन गांवों के १।४ गांवों में कोई पैसा नहीं पहुंच पाया है। मैं इस की बात जांच के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव देना चाहता हूं। वह जांच करे कि जिन गांवों का नाम लेकर हमने अपनी दो प्लानों का पैसा लगाया है उसमें से कितना पैसा वास्तव में गांवों में पहुँचा है। यह कमेटी यह भी जांच करे कि किन गांवों ने कितना पैसा टैक्सों और रेवेन्यू के नाम से दिया है और इसके बदलने में उनको कितना रिटर्न सरकार ने दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं पहुँचा है। इस जांच के आधार पर तृतीय योजना के लक्ष्य रखे जावें। हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब छोटे गांवों की हम उन्नति कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि हमने पिछली योजनाओं में कुछ तथ्य या लक्ष्य प्राप्त किये हैं पर वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है वह गांवों की समृद्धि ही है। यह जब तक प्राप्त नहीं की जावेगी, हमारे सारे लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्तियां अधूरी ही रहेंगी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि १४ वर्ष के बाद भी हम ऐसी कोई योजना नहीं बना पाये हैं कि जिससे हरेक गांव में खुशहाली हो सके।

शिक्षा की यह दशा है कि गांवों के स्कूलों में आज भी कोई साधन नहीं है। गांवों में किसी तरह कोशिश करके स्कूल खुलवा दीं तो अध्यापक नहीं जाते। कारण यह है कि उनको तनख्वाह कम है। तनख्वाह भी बढ़ा सकते हैं, तो रहने और उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। वास्तविक तरक्की तब होगी जब कि हम ६–७ साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देंगे, स्कूल अभियान चलावेंगे; पर इस अभियान के बावजूद कितने साधन आप स्कूल को दे पाये हैं; यह देखना है; कितनी सहूलियतें आप स्कूल मास्टरों को दे पाये हैं। इसकी ओर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक सच्ची तरक्की नहीं हो सकती। हम सारी योजना बनावें पर इनका, मूल आधार जब तक हम गांव को और उसकी प्राथमिक आवश्यकता को नहीं बनावेंगे और नीचे से नहीं चलेंगे तब तक दिल्ली से भले ही आप जयपुर को जोड़ें या जयपुर को कोटा से या बारां से जोड़ें आपकी सफलता संदिग्ध है। आप इसकी बजाय नीचे से चलते आप अपना केन्द्र–बिन्दु एक गांव को बनाते, तो ज्यादा तरक्की होती और सही माने में तरक्की हो सकती थी।

Page No.98

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारी योजनाओं में काफी पैसा है । हमारी योजना महत्वाकांक्षी है । पहली योजना सौ करोड़ की थी, अब २१२ करोड़ की आपने बना दी है, बननी चाहिये । पर आप जिनको लाभ नहीं पहुंचा पाये हैं उनसे पैसा वसूल करें, यह सामाजिक अन्याय है । आपका फर्ज है कि आप जिनसे पैसा लेना चाहें उसका रिटर्न उसका प्रतिफल उनको अवश्य दें ।

एक बात और है । आप योजना महत्वाकांक्षी बना लेते हैं, पर टार्गेट्स पूरे अचीव नहीं कर पाते, काफी पैसा बच जाता है, सारे पैसे का पूरा उपयोग नहीं कर पाते और इसके बावजूद भी आप योजना बनाते जा रहे हैं, यह उचित नहीं है । आप इसके लिए अपने प्रशासनिक ढांचे को ठीक करिये, आप शासन की मशीनरी को तेज करिये । इसको गति दीजिये तभी इस प्लान को राजस्थान की जनता के हित में गति देने में सफल हो सकेंगे । जब तक ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ आप अपनी मशीनरी को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कितनी ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनावें, सब अधूरी रहेंगी और पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा या उसका दुरुपयोग होगा । यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री रामचन्द्र (डग–सु.) : सभापति महोदय, देश के विकास की यात्रा की दो मंजिलें करीब करीब खत्म होने वाली हैं । अब हम तीसरी मंजिल एनकरीब आरम्भ करने वाले हैं । हमारी सदा से यह प्रणाली रही है कि किसी भी यात्रा को आरम्भ करने के पहले उसके ऊपर भली प्रकार से सोच–विचार करके आगे बढ़ते हैं । राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वे केवल इस राजस्थान की ही नहीं, बल्कि समस्त भारत के विकास की यात्रा का एक अंग हैं और ऐसी हालत में यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारी योजनाएं भी करीब करीब वैसी ही हों जिनके ऊपर या जिस प्रोग्राम के अनुसार देश के अन्य राज्य चलना चाहते हैं या चल रहे हैं ।

हमें एक नई प्रकार की योजना बनाकर नहीं चलना हैं बल्कि प्लॉनिंग कमीशन ने जो योजना के भिन्न भिन्न अंग निश्चित किये हैं उन्हीं को अपने सामने रखकर और उसी के प्रोग्राम के अनुसार अपने प्रान्त की सुख समृद्धि की यात्रा आरम्भ करनी चाहिये ।

सभापति महोदय, कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने तीसरी योजना की एक रूपरेखा रखते समय सदन में पहली दो योजनाओं का दिग्दर्शन कराया था कि इनमें हमारे क्या क्या लक्ष्य थे और हमने उनमें कहां तक कामयाबी हासिल की है । इससे हमें यह मालूम हुआ है कि हम अपने एक निर्धारित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं । इससे हमें सन्तोष है और खुशी है कि राजस्थान में दिन प्रतिदिन प्लान के अनुसार उन्नति हो रही है ।

लेकिन सभापति महोदय, जिस प्रकार बुद्धिमान अपनी अगली मंजिल पर चलने से पूर्व पिछली मंजिल के अनुभव को ध्यान में रखता है । इसी तरह हमें अपने कदम एक स्टीरियोटाइप ढंग से नहीं बढ़ाना हैं, बल्कि अपने प्रदेश की विशेष परिस्थितियों, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों और हमारे यहां

(श्री रामचन्द्र)

के निवासियों की आर्थिक दशा को और सामाजिक दशा को ध्यान में रखकर जो अपनी एक विशेषता रखते हैं, आगे बढ़ना चाहिये और इस विशेषता के अनुरूप ही हमें अपने प्रोग्राम में अगर कहीं कोई आवश्यकता के अनुसार रद्दोबदल भी करना पड़े तो उसके लिये तैयार रहना चाहिये। अपने प्रोग्राम को इतना रिजिड नहीं बनाना चाहिये बल्कि अगर इसके अनुसार चलने में हमें आगे कठिनाइयां आवें और अपने लक्ष्य पर ही नहीं पहुँच सकें तो हमको अपना प्रोग्राम बदलना चाहिये; हमारा प्रोग्राम हमेशा फ्लैक्सिबिल होना चाहिये। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम उनमें रद्दोबदल कर सकें, ऐसी योजना बनानी चाहिये।

कल मुख्य मन्त्रीजी ने इस योजना के भिन्न भिन्न मदों के आंकड़े उपस्थित किये थे। उनको देखने से मालूम होता है कि राजस्थान अपने रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करने की दिशा में भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पहली योजना में केवल ६४ करोड़ रुपयों का लक्ष्य रखा गया था और दूसरी योजना में १०५ और अब तीसरी में २१२ करोड का लक्ष्य रखा गया है। मैं यह कहूंगा कि ये जो टार्गेट्स रखे हैं रिसोर्सेज़ के, मेरे ख्याल से कम हैं। हमेशा से हमारा लक्ष्य यह रहा है कि हम २५ वर्षों में अपने देश की आमदनी को डबल कर दें और इस प्रकार प्रति वर्ष की आमदनी भी डबल हो जानी चाहिये। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी तक राजस्थान की इन्कम पर कैपिटा किस प्रकार बढ़ी है। इसको देखते हुए यदि हम अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहें यानी २५ वर्षों में अपनी आमदनी को दुगुना करना चाहें तो हमको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे क्योंकि जो अभी देश का प्रत्येक वर्ग और देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि वास्तव में ये योजनाएं देश को आगे ले जाने वाली हैं और इसलिए प्रत्येक वर्ग इसमें अधिक दिलचस्पी के साथ काम कर रहा है। अभी अभी हाल में शासन का जो विकेन्द्रीकरण किया गया है उससे तो गांव से लेकर शहर तक की जनता अपने देश के विकास में जुट गई है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें देश में एक जागृति पैदा करनी है। पिछली योजनाओं में जितना रुपया खर्च किया गया, इस योजना में इससे कई गुना अधिक खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। लोग उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों का विकास करना चाहेंगे और इसके लिये रिसोर्सेज़ की भी काफी जरूरत पड़ेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमने अपना एक्सपेन्डीचर का टार्गेट रखा है यह कम है इसको अवश्य बढ़ाना चाहिये।

इसके अलावा कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी कुछ दिक्कतें भी पेश की थीं हमारी जैसी मौजूदा दशा है उसे देखते हुए हम केवल ८० करोड़ के लगभग ही धन जुटा सकेंगे। इसलिये राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से बाकी की सहायता लेने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं यहां यह कहूंगा कि राजस्थान का विकास केवल राजस्थान के लिये ही नहीं है, राजस्थान का विकास समस्त देश के लिये है। राजस्थान इतना लम्बा-चौड़ा फैला हुआ राज्य है कि

(श्री रामचन्द्र)

यहां के जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें कि राजस्थान के तमाम प्राकृतिक रिसोर्सेज़ का विकास कर लिया जाये तो उनसे जो देश को फायदा पहुँचने वाला है वह इतना ज्यादा होगा कि राजस्थान की १।। करोड़ जनता की अवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इतना सरप्लस बच रहेगा कि वह शेष भारत की बहुत सी जरूरतों को पूरा कर सकने में समर्थ होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि राजस्थान का डेवलपमेन्ट न केवल राजस्थान के लिए ही लाभदायक है बल्कि राजस्थान का डेवलपमेंट समस्त भारत के लिये हो रहा है। इसलिए जैसा कि हमें अभी एग्रीकल्चर के आंकड़ों से पता लगा कि हमारी खाद्यान्न में जो डेफीशियेन्सी थी वह पहली पंचवर्षीय योजना में पूरी हो गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हम उस परिस्थिति में पहुंच गये हैं कि हम अपनी पैदावार का बहुत सा हिस्सा राज्य के बाहर भेज भी सकते हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि हमारी दो योजनाओं के द्वारा ही हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो गये हैं और हमारे यहां जब चम्बल वैली प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनाल का विकास हो जायेगा तो उस विकास के फलस्वरूप जो सरप्लस अन्न पैदा होगा वह राजस्थान के काम में ही नहीं आये, बल्कि वह भारत के जो अन्न की कमी वाले क्षेत्र हैं उनको सहायता पहुंचाने में सहायक होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार को राजस्थान के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यह देखना चाहिये कि राजस्थान का विकास राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारत के लिये है। इसलिए अधिक से अधिक सहायता केन्द्रीय सरकार को राजस्थान के लिए देनी चाहिए। यही बात मैं खनिज रिसोर्सेज़ में भी देखता हूं। राजस्थान में दूसरी बड़ी पैदावार का यहां के खनिज पदार्थ हैं। यह खनिज पदार्थ हमारे यहां इतनी ज्यादा मात्रायें हैं कि मैं कह सकता हूं कि इसमें भी राजस्थान अन्य राज्यों के सरपास कर सकता है लेकिन दुःख की बात यह है कि अभी तक राजस्थान के खनिज का प्रोस्पेक्टिंग इतना नहीं हुआ है और जब कभी खनिज विकास का जिक्र आता है तो यह कह दिया जाता है कि रुपये की कमी है और हमारे पास यंत्र नहीं है और हमारे पास अच्छे आदमी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में खनिज सम्पत्ति इतनी ज्यादा है कि वह राजस्थान के लिए ही काफी नहीं होगी बल्कि राजस्थान से बाहर जो बड़े बड़े कारखाने लगने वाले हैं उनको भी यह कच्चा माल सप्लाई करने में प्रमुख भाग लेगा। इसलिए यहां पर मुझे फिर यही निवेदन करना पड़ता है कि राजस्थान के प्राकृतिक रिसोर्सेज़ इतने अधिक मात्रा में हैं; यदि इनका भरपूर विकास किया जाए तो यह अन्य अन्य राज्यों के लिए और समस्त भारत को लाभ पहुँचाने में सहायक हो सकते हैं। सभापति महोदय, पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं से जो अनुभव हुए उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक राजस्थान की नीति मार्च ऑन अर्थात् आगे बढ़ रही है, लुक बैक अर्थात् नतीजे की तरफ भी ध्यान दो, की नीति नहीं। हम आगे भी बढ़ते जायें लेकिन साथ ही साथ हमको पीछे भी देखना चाहिए कि हम कितने मील आगे बढ़ गये हैं। याने हम अपने देश के विकास के प्रोग्राम बराबर काम में लाते रहें, लेकिन साथ ही साथ

(श्री रामचन्द्र)

हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जितना पैसा हमने खर्च किया है, जितना पैसा भिन्न भिन्न योजनाओं में पिछले दस वर्षों में लगाया है उसका कितना नतीजा हमको मिला है। हमारा जितना धन लग रहा है वास्तव में उसी के अनुसार हमको लाभ पहुँच रहा है या नहीं ? अगर नहीं पहुंच रहा है तो हमको देखना चाहिये कि गलती कहां पर है, इस तरफ भी हमें पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। इसलिए सरकार को केवल प्रोग्राम को अमल में लाने के ऊपर ही ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि देखना चाहिये कि हर स्टेज के ऊपर, प्रतिवर्ष, हर क्षेत्र में जो कुछ विकास हुआ उसका मूल्यांकन भी कराते रहना चाहिये कि हमने जो धन लगाया है वह कितना लाभदायक सिद्ध हुआ है। यदि सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो मैं समझूंगा कि समय समय पर उसको चेतना मिलती रहेगी कि जो कुछ सरकार पैसा लगा रही है वह ठीक दिशा में खर्च हो रहा है और नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं तो इसके विपरीत ही देखता आ रहा हूँ। हर एक योजना जो, वार्षिक लक्ष्य मुकर्रर किए जाते हैं मान लीजिए कि एनीमल हस्बेन्डरी में में राजस्थान को इस वर्ष एक करोड़ रुपया खर्च करना है ; लक्ष्य हमारा यह रहता है कि एक करोड़ रुपया खर्च हो जाए। इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता कि एक करोड़ रुपया वास्तव में ठीक तरीके से खर्च हुआ या नहीं। डिपार्टमेंट के ऊपर इस बात का नियंत्रण होता है कि वह योजना का ६० या ६५ प्रतिशत खर्च करके बताए। इस बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि हमने जो ६० प्रतिशत रुपया खर्च किया है वह वास्तव में उपयोगी हुआ या नहीं। दूसरी कमी सभापति महोदय, मैं देखता हूं कि जो यह योजना का निर्धारित धन यूनीफार्म तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा है। हमारी योजना का ज्यादातर पैसा साल के आखिर के एक–दो महीने में खर्च कर दिया जाता है और यह समय इतना कम रह जाता है और ऑफिसर्स के ऊपर डिपार्टमेंट का इतना दबाव होता है कि किसी किसी तरह से इस रुपये को खर्च करना चाहिए। तो इस थोड़े समय में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वह रुपया खर्च कर दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का खर्चा जो सरकार करती रहे तो मुझे शक है कि हम उस धन का जितना फायदा उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार को इस पालिसी पर अमल करना चाहिए था, "मार्च ऑन बट लुक बैक" अर्थात् "आगे भी बढ़ो लेकिन पीछे की तरफ भी ध्यान रखो।" इस समय हमने दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त की हैं और तीसरी योजना में पदार्पण करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि पिछली दो योजनाओं में जो खर्चा किया है उससे कितना फायदा हो रहा है ?

तीसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि अभी यह बहस हो रही थी कि ४ करोड़ रुपये के खर्चे से गवर्नमेंट ने ४ लाख टन अन्न अधिक उपजाने में कामयाबी प्राप्त की, उसके बाद दूसरी योजनाओं में ८ करोड़ रुपया लगाये तो उसकी उपज दुगुनी हो जावेगी। अब इसी तरह से अगर १० करोड़ रुपया लगा दिया जायेगा तो एडीशनल फूड प्रोडक्शन १८ लाख टन बढ़ जायेगा।

(श्री रामचन्द्र)

मैं यह कहूंगा कि वास्तव में यह ठीक है और मैं तो यह कहूंगा कि जब कोई विकास प्रोग्राम इम्पीटस पकड़ लेता है, तो उसकी दशा स्थिर हो जाती है तो अगले वर्षों में उसकी पैदावार और आगे ही बढ़ती जाती है। तो मेरा तो यह निश्चय है कि १० करोड़ रुपये का जो लक्ष्य एग्रीकल्चर में रखा है, वास्तव में इससे १८ लाख टन अधिक उपजेगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जैसा कि सरकारी कर्मचारी देखेंगे कि तीसरी योजना के अन्त में मुझे विश्वास है कि इस १० करोड़ के खर्चे से २५ लाख टन अधिक अन्न उपजाने में सरकार कामयाब होगी। इसी तरह से और और बातों से भी मुझे विश्वास है कि जब कोई विकास योजना इम्पीटस ग्रहण कर लेती है तो उसके नतीजे भी अच्छे निकलते है।

सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार ने गरीबों की गरीबी दूर करने का एलान किया है अर्थात् राज्य में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता फैली हुई है उसको दूर करने का सरकार का लक्ष्य है और उसके लिए सरकार ने उचित कदम भी उठाया है, लेकिन ये जो कदम उठाए गए हैं वे नाकाफी हैं। काश्तकारों के और जागीरदारों के और सरकार के, तीनों के रिलेशन ऐसे जुड़े थे कि काश्तकार जो अन्न उपजाता था उसका फायदा गवर्नमेंट तक पहुंचाता था। इन दोनों के बीच में इन्टरमीडियरीज़ जागीरदार थे वे उसका फायदा अकारण ही उठाते थे। उन इन्टरमीजियरीज़ को हटाने के लिए सरकार ने पूरे कदम उठाए हैं लेकिन मैं देखता हूं कि वह गरीब लोगों का, जिनका खून आज खनिज और जंगलात के ठेकेदार चूस रहे हैं, सरकार ने अभी तक उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। अब भी सरकार और लेबर के बीच में ठेकेदार एक इन्टरमीजियरी खड़ा हुआ है, अब भी यह इन्टरमीजियरीज़ कायम है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार यदि गरीबों की इन्कम पर केपिटा बढ़ाना चाहती है तो इन्टरमीजियरीज़ जो ठेकेदार के नाम से कायम हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए सरकार को कोई न कोई कानून या कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं कि एक मज़दूर खानों पर, सुबह से शाम तक काम करता है और उसका फायदा ठेकेदार उठाते हैं और मज़दूर, मजदूर ही बना रह जाता है और ठेकेदार को वह सारा नफा मिल जाता है। यद्यपि सरकार ने उसके लिए एक पोलिसी निर्धारित की है लेकिन मैं देखता हूं कि इस उदार पोलिसी के फलस्वरूप आज लेबर लेबर ही बना हुआ है, अब भी जंगल में लकड़ी काटने वाला लकड़हारा ही बना हुआ है और ठेकेदार तमाम फायदा ले रहे हैं। यही हालत मिनरल्स की है। खानों को खोदने वालों को फायदा नहीं पहुँच रहा है और नफा उन लोगों को मिल रहा है जो उनका खून चूसने के लिए बहुत अर्से से आदी हो चुके हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिसमें कि सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि आमदनी पर केपिटा बढ़े तो यदि गरीबों की आमदनी पर केपिटा बढ़ाना चाहते हैं तो उनके शोषण का जो एक कारण बने हुए हैं उस कारण को

(श्री रामचन्द्र)

जल्दी से जल्दी दूर करें, तो ही इन गरीबों की रक्षा हो सकती है और उन गरीबों की गरीबी दूर हो सकती है । वैसे कहा जाता है कि राजस्थान की इन्कम पर केपिटा बढ़ी है, जरूर बढ़ी है लेकिन इन्कम प्रति गरीब नहीं बढ़ी है. एवरेज इन्कम बढ़ी है । अमीरों की आमदनी पर केपिटा जरूर बढ़ी है, अर्थात् ठेकेदार हैं उनकी इन्कम पर केपिटा बढ़ी है, किसानों की इन्कम पर केपिटा बढ़ी है लेकिन गरीब मजदूरों की इन्कम पर केपिटा नहीं बढ़ी है । यदि आप राजस्थान के लोगों की इन्कम पर केपिटा बढ़ाना चाहते हैं, इस बात की जांच करना चाहते हैं कि गरीबों की इन्कम भी बढ़ी या नहीं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वर्गवाइज़ जांच कराइए और फिर देखिए कि लेबर क्लास की क्या इन्कम बढ़ी है और इसी तरह से एग्रीकल्चरिस्ट की पर केपिटा क्या इन्कम बढ़ी है और इन्डस्ट्रियलिस्ट इत्यादि जो राजस्थान के भिन्न २ वर्ग के लोग हैं उनकी इन्कम पर आप हिसाब लगायेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन्कम वास्तव में बड़े लोगों की बढ़ रही है, गरीबों की नहीं; उनका अभी कोई इजाफा नहीं हुआ है । यदि आप गरीबों की इन्कम का इजाफा करना चाहते हैं तो गरीबों के शोषण का जो एक जरिया बना हुआ है और जो अर्से से इनकी दया पर रहते आए हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करना सरकार का कर्त्तव्य है ।

अन्त में सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस साल इस पंचवर्षीय योजना में यह एलान किया है कि हमारे यहां पर बड़ी २ इन्टस्ट्रीज़ खुलेंगी और उनके वास्ते अभी से हमारे मुख्य मन्त्रीजी तथा अन्य मन्त्रीगण और राज्य कर्मचारी इस पर बराबर प्रयास करने लगे हैं । राजस्थान के भिन्न २ भागों में जब कि बिजली का अधिक के अधिक प्रयास हो रहा है और साधन भी बढ़ते जा रहे हैं तो राजस्थान में उद्योगों का विकास जल्दी से जल्दी होना चाहिये । यह बड़ो खुशी की बात है कि कल जैसा कि मुख्य मन्त्री ने एलान किया था कि राजस्थान में बड़ी २ कपड़े की मिलें खुलने वाली हैं, वास्तव में यह एक सुख की बात है । राजस्थान अब तक इस योग्य नहीं था कि वह अपने तन को अपने ही कपड़े से ढक सके । बम्बई, कलकत्ता या कानपुर जैसे स्थानों से कपड़ा ला करके राजस्थान के लोग अपने शरीर को ढकते थे । लेकिन यह जो कदम राजस्थान सरकार उठा रही है कि यहां पर तीन बड़ी मिलें खुलने वाली हैं, मुझे विश्वास है कि कपड़े के लिए भी राजस्थान अवश्य ही आत्म निर्भर हो जायगा । इन तीन मिलों में एक मिल किशनगढ़ में, एक मिल भीलवाड़ा में और तीसरी मिल जिसके लिए कि मुझे राजस्थान सरकार को अत्यन्त हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए कि वह मिल भवानीमंडी में खुल रही है, जिसके लिए झालावाड़ की जनता एक अर्से से मांग कर रही थी । मुझे इसके साथ यह भी निवेदन करना है कि इस एक मिल के साथ साथ यदि सरकार उसे एक इण्डस्ट्रियल एस्टेट भी कायम कर दे तो उस जिले का औद्यागिक विकास अच्छा हो सकता है । लेकिन प्राय: यह देखा जाता है कि राजस्थान सरकार तो हमारे विकास की तरफ कदम उठाती है, लेकिन उस विकास

(श्री रामचन्द्र)

में रोड़े अटकाने के लिए भी कुछ साधन होते हैं। आज भवानीमंडी में मिल बनने जा रही है. मन्जूरी भी हो गई है और तैयारी भी हो गई है, लेकिन वह जमीन जिस पर मिल की बिल्डिंग बनने जा रही है उस पर किसी महानुभाव ने बिला वजह जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के नाजायज़ कब्जों को, उस जमीन से हटा करके जिस सेठ ने नया मिल खोलने के लिए प्रयास किया है उनको यह जमीन जल्दी से जल्दी दिलाई जावे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मोगजी भाई।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय चेयरमैन महोदय, आज हमारी तृतीत पंचवर्षीय योजना पर कल से विचार हो रहा है। यह हमको बड़ी खुशी है कि हम हमारे देश के जन-जीवन और निर्माण के लिए कदम, चाहे वह किसी भी रफ्तार से उठा रहे हो बढ़ा रहे हैं। माननीय चेयरमैन महोदय, यहां कल मुख्य मन्त्रीजी ने अपना प्रस्ताव रखते समय सारी स्थिति पर प्रकाश डाला था और कहा कि कई कार्यों में असफल रहे या घाटे में रहे और कई कार्यों में आगे बढ़े, उस तरह से एक दुनिया को अपनी स्पीच के आधार से अच्छी तरह रजामन्दी रखने की यहां पर अच्छी २ बातें कहीं गई और आंकड़े भी अच्छे २ बताए। लेकिन माननीय चेयरमैन महोदय, जब हमारे आंकड़े करीब करीब ड्योढ़े दूने पर पहुँच रहे हैं और उसमें जो पिछली पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल असफल भी रहे हैं उसी आधार पर जहां तक मैं समझता हूं कि यहां पर आयन्दा की स्थिति भी उसी प्रकार होगी। माननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम खुशी की तरफ जा रहे हैं और हमारे राजस्थान में अधिक से अधिक जन-संख्या बढ़ती जा रही है, किन्तु उसके आंकड़ों का हमको मालूम नहीं है। माननीय चेयरमैन महोदय, एक इसी बात से कि हमारे राजस्थान में भी प्रगति हुई है, लेकिन एक कहावत है और उस कहावत में एक आदमी....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): परिवार यह नियोजन पर नहीं पंचवर्षीय योजना पर बात करो, शिड्यूल कास्ट के लिए कितना खर्चा हो, इसके लिए बोलो।

श्री सभापित : आॅर्डर ! आॅर्डर !!

श्री मोगजी भाई : माननीय चेयरमैन महोदय, योजना की ही बात है, लेकिन योजना किस तरह से असफल रहती है और मतलब कि खाडे में ही हम लोग दबते जा रहे हैं।

माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे यहां राजस्थान के सरकारी मिनिस्टर हैं वे अपना समय निकालने के लिए महमान बन कर गये थे किसी विदेश में। वहां पर १० मकानों में एक एक दिन रहे। आखिर में घर लौटकर जब आये तो उनके घर पर कम से कम ११ आदमी बैठे थे। उन्होंने पूछा कि आप कहां गये थे तो उन्होंने कहा कि कहीं नहीं घर पर ही था। उनका मतलब यही था कि वे यह समझते थे कि

(श्री मोगजी भाई)

उनके बाहर जाने से घर पर बचत रहेगी लेकिन जब वे घर पर आये तो उतने ही आदमी घर पर बैठे हुए मिले । तो, माननीय चेअरमैन महोदय, इसी तरह घाटे की पूर्ति के बजाय पूरा घाटा कायम रहा। तो उसी तरह से हमारे राजस्थान के आंकड़ों को बढ़ाकर दुनियां को खुश कर दें, लेकिन बढ़ती हुई आबादी को देखें तो फिर जहां पहले थे, वहीं के वहीं रहे । बहुत सारी सीढ़ियों के चढ़ने पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चढ़ जायेंगे लेकिन पहली और दूसरी सीढ़ी पर थे वहीं के वहीं तीसरी सीढ़ी में जाने वाले हैं ।

माननीय चेअरमैन महोदय, आज हमको चाहिये था कि देश में जितने बेकार हैं और कम से कम दूसरे अनपढ़ लोग हैं उनको, जहां तक मैं समझता हूँ कि उनसे बहुत अच्छी बातें कही जाती हैं लेकिन अन्दर से आज तक उनकी गिनती में और गरीबों की गिनती में काफी अन्तर है । माननीय चेअरमैन महोदय, कुछ पढ़े-लिखे लोग बहुत अच्छे मजे और मौज में रहते हैं, और उनको दिनों दिन अच्छा पैसा दिया जा रहा है। माननीय चेअरमैन महोदय इस योजना से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जो स्थिति है वह की वह स्थिति आज होने वाली है । आज हमारे यहां हमारे एक मुख्य कर्मचारी को १०००) से २०००)रु. या ३०००)रु. तनख्वाह और ५००)रु.या १०००)रु. मासिक भत्ता होता है। लेकिन उनसे छोटे तबके के लोग जिनको कि हम चपरासी कहते हैं, वे कर्मचारी ८ घन्टे सरकारी नौकरी करते हैं और उन ८ घन्टों के बाद में बाकी १२ या १६ घन्टे इन कर्मचारियों की ड्युटी बजाते हैं। माननीय चेअरमैन महोदय, इसके विषय में आज हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी कोई ऐसी बात कह देते तब तो मैं उनको धन्यवाद भी दे सकता था। लेकिन, माननीय चेअरमैन महोदय, आज की स्थिति ऐसी है कि जो आदमी कम पढ़ा हुआ है उसके साथ में हजारों की तादाद में उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन पंचवर्षीय योजना में जहां तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लोग हैं, जिनके पास में १० मनुष्य हैं, पूरी फेमिली है या ड्योढ़ी फेमिली है वही गजटेड ऑफिसर के पास में है, लेकिन गजटेड ऑफिसर को १०००)रु. या ५०००)रु. तक की आय है और उसको मुश्किल से २५) रु० तक की आय है और वे उस कर्मचारी को गुलाम बना कर रखते हैं। ऐसी हालत में आज कहा जाय कि उनका वेतन कम करके उनका ज्यादा वेतन बढ़ाया जाय तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और राज्य का संचालन करने वाले हमारे मुख्य अधिकारी लोग कहते हैं कि पहले आप बजट बढ़ाओ और बाद में उसकी दलील दें। लेकिन....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेर): There is no quorum, Sir.

श्री मोगजी भाई: माननीय चेअरमैन महोदय, यह योजना के....

श्री सभापति: There is. Including myself the number is 17.

श्री पी० के० चौधरी: No, Sir, you are not included.

(कुछ माननीय सदस्यों के पदार्पण पर)

श्री सभापति : Now the quorum is complete.

श्री मोगजी भाई : माननीय चेअरमैन महोदय, आज हमारी पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जा रहा है और सदन के नेता, वे हाजिर भी नहीं रहते हैं, इसलिए माननीय चेअरमैन महोदय, हमारे विकास की क्या स्थिति होगी ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आपकी आवाज वहां तक पहुंच जायेगी ।

श्री मोगजी भाई : तो, माननीय चेअरमैन महोदय, मैं कह रहा था चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ाने की बात करें तो घाटा बताते हैं, लेकिन जब गजटेड ऑफिसर का वेतन बढ़ाने की बात करें तो मिनिस्टर या वेतन आयोग समिति उनकी सिफारिश कर गवर्नमेंट से मन्जूर करवा लेती है । उस हालत में यह हो सकता है कि बजट के आंकड़ों की जरूरत नहीं है । हमारा जो बजट है उसमें भी यह हो सकता है । मान लें कि १००००)रु. वेतन तीन हजार वेतन पाने वालों को ५००) रुपया बांट दे तो ७, ८ कर्मचारियों का जो पूरा वेतन है वह एक कर्मचारी बटोर रहा है । उसी स्थिति में आंकड़ें बढ़ाकर आप कहते हैं कि स्थिति अच्छी रफ्तार से चल रही है । लेकिन मैं समझता हूँ कि गरीबी दिनों-दिन बढ़ रही है । आज बड़े बड़े सेठ साहूकारों के घरों में और बड़े बड़े ऑफिसर्स के कुत्तों तक को अच्छी तरह से मोटर में हिफाज़त से रखा जाता है, लेकिन हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से ऑफिसर की कोठी में बर्तन साफ कराये जाते हैं और मियां-बीबी के कपड़े धुलाये जाते हैं । माननीय चेअरमैन महोदय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आखिर गरीब के गरीब ही हैं । मैं गरीब लोगों से यही अर्ज करना चाहता हूं कि वे नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दें । एक तरफ हमारे देश को स्वतन्त्र बनाया और दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको पूरे राज्य का नौकर बनाकर बड़े बड़े लोगों का गुलाम बना दिया है और उनसे १६ घन्टे तक काम लिया जाता है और वही उनका काम-आज चल रहा है ।

तो, माननीय चेअरमैन महोदय, अब यह कहें कि अच्छी तरह से योजना सफल होगी तो यह होने वाली नहीं है । गरीब तो जहां खाडे में था वहीं होगा, क्योंकि १० नौकरों के बजाय ५० नौकर लिये जायेंगे । उनकी स्थिति वही की वही रहेगी, और बैठकर खाने वाले वही के वही होंगे । इसी आधार पर आज हमारा देश उस तरफ जा रहा है ।

माननीय चेअरमैन महोदय, दूसरी बात हमारे देश में सड़कों की है । मैं दूर की मिसालें यहां पर नहीं ला सकता हूं, लेकिन मैं जहां पर रहता हूँ वहां की सड़कों की स्थिति को मैं जहां तक समझा और आप भी वहां पर देखेंगे तो आपको भी दुःख होगा । हमको तो इतना दुःख नहीं होगा क्योंकि हम तो २४ घन्टे पहाड़ों पर घूमने वाले हैं । हम इनके कायल नहीं हैं, लेकिन वहां की जनता के लिए और अगर आप थोड़े दिन वहां पर रहें तो बड़ी मुश्किल की बात हो जायगी । तो, माननीय चेअरमैन महोदय, आज यह सड़कों की भावना है और हमारे यहां सड़कों का जो कुछ कार्यक्रम अभी तक

(श्री मोगजी भाई)

बना है वहां किसकी गलती है ? यह मैं समझता हूँ कि हमारे पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर की गलती है या उस विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी गलती है ! आज एक थोड़ा सा ६ मील का टुकड़ा है। रियासत के टाइम में कम से कम २-३ मील बन चुका है, वह टुकड़ा आज १५ साल होने आये हैं नहीं बन सका है। मैंने कई बार इसके लिए अर्ज किया है लेकिन विरोधी नेताओं की पुकार को हजम करने की कोशिश हमारे मिनिस्टर महोदय करते हैं। बड़े खेद की बात है कि ऐसी स्थिति कई देहातों की है और वे कहते क्या हैं और करते क्या हैं।

ऐसी ही हालत छोटी छोटी संस्थाओं की है। हम कहते हैं कि हमारी संस्थाओं का हमेशा विस्तार होना चाहिए और संस्थाओं के द्वारा वह पूरे का पूरा हमारे देश का निर्माण होना चाहिए, लेकिन संस्थाओं के प्रति पक्षपात की भावना रहने के कारण, और हमारी वोट लेने की भावना के कारण संस्थाएं भी उसी तरह से काम करती हैं जैसा कि पक्षपात का काम होना चाहिए। वहां पर भी जो छोटे छोटे कर्मचारी रखे गये हैं उन कर्मचारियों को ३०) रु० से ज्यादा वेतन नहीं दिया जाता है। एक तरफ ५०००)रु. और एक तरफ ३०) रु० हैं और आप जो देश को बड़ा अच्छा हराभरा बताते हैं, और हमारे देश को सफल बनाने की बात बताते हैं तो यह कुछ हद तक ठीक नहीं है।

माननीय चेअरमैन महोदय, जहां तक मैं समझता हूँ कि जिला बांसवाड़े में ६०-६० मील की दूरी पर वहां पर, लोग बिल्कुल बिखरे हुए एरिया में रहते हैं।

वहां पर अस्पताल का और दवाइयों का ऐसा इन्तजाम है कि जहां पर ५०,००० की आबादी है वहां ३ हजार का बजट है। पहले डेढ़ दो हजार का बजट था लेकिन अब तीन हजार का हो गया है। माननीय सभापति महोदय, जब कभी ऐसा मौसम आता है, सर्दी में या गर्मी में जबकि बुखार वगैरह की समस्या पैदा होती है तब तीन तीन हजार लोग एक ही दिन में बीमार होते हैं। वे सब अगर अस्पताल में कहीं आ गये तो एक ही दिन में वह ३ हजार का बजट खत्म हो सकता है। दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि गरीबों के लिये इस प्रकार की योजना बनाकर देश की उन्नति कर रहे हैं लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि सौतेली मां के व्यवहार को तरह योजना में रखा गया पैसा अच्छे अच्छे लोगों के लिये खर्च किया जाता है। मैंने आपके सामने अपने यहां के अस्पताल की मिसाल दी। मैंने कम से कम १५-२० औरतों को मरते हुए अपनी आंखों से देखा है जहां पर बच्चा जनमते समय न कोई व्यवस्था है और न वहां पर डाक्टरनी या नर्सेज़ वगैरह की व्यवस्था है। डॉक्टर २५०-३०० रुपयों का जरूर रखा है लेकिन वहां पर दवाइयां वगैरह के पूरे साधन नहीं होने से बड़ी तकलीफ होती है। यह थोड़े ही हो सकता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब अच्छे अस्पताल में पैदा होवे। बच्चा तो जब टाइम आता है तभी जना जाता है। लेकिन स्थानीय अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने के कारण दूसरी अस्पताल में भेजा जाता है तो रास्ते में ही उस औरत की मृत्यु हो जाती है। मैं जहां तक समझता हूं पहले के शासकों के जमाने में भी अच्छी

(श्री मोगजी भाई)

व्यवस्था थी हालांकि वे जनता के साथ अत्याचार करते थे लेकिन मैं उनको फिर भी अच्छा समझता हूं ।

जहां तक बजट का सवाल है, मंत्रीजी ने कहा था कि गधों की संख्या का नाम नहीं लेता । उन्होंने कहा था कि उनकी संख्या के बारे में कहना नहीं है । जहां गरीब आदमी चौबीसों घंटे मेहनत करते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, छोटे काश्तकार और गरीब मजदूर उनके साथ साथ ५०० रुपये घोड़े को खिलायेंगे तो वह रोज काम आने वाला नहीं है, लेकिन ज्यादा काम आने वाले गधे ही हैं । घोड़ा तो कभी कभी काम आ सकता है । गधों और गरीबों में कोई अन्तर नहीं है । उनका नाम लेने से हमारे मंत्रीजी और मुख्य अधिकारी लोग हिचकते हैं । ऐसी हालत में जहां तक दवाइयों का यह रवैया रहा, सड़कों का यह रवैया रहा और खाद्य स्थिति का भी वही रवैया रहा ।

सभापति महोदय, अनाज जहां पैदा होता है वहां उसकी कमी नहीं रहनी चाहिये लेकिन अनाज जहां पैदा होता है वहां उसको समेटने वाले, शोषण करने वाले साहूकारों को हमारी सरकार ने पैदा किया है जो गरीबों को नीचे से ऊपर नहीं आने देते । वे जो ६ महीनों में पैदा करते हैं उसको खून की तरह चूस जाते हैं । ऐसे लोग गरीबों को लूटते हैं और जब उनके बारे में कहते हैं तो मंत्रीजी आश्वासन देते हैं कि उनके करने से क्या होता है । माननीय चेअरमैन महोदय, आपको हमारे इलाके का अनुभव नहीं होगा, लेकिन कर्जे का व्याज चार महीनों में सवाया लेते हैं, फिर दूसरे चार महीनों में और सवाया ले लेते हैं और अगले चार महीनों में और सवाया ले लेते हैं । इस तरह से ये लोग लोगों का शोषण करते हैं । राजस्थान सरकार जो कानून बनाती है वे बड़े बड़े बंगलों में ही पड़े रहते हैं, मालूम नहीं उनकी पूजा भी होती होगी या नहीं । गरीबों को यह मालूम नहीं है कि वे क्या कार्यवाही करें । ऐसी स्थिति में बर्दाश्त करते हुए वे जो ६ महीनों और ८ महीनों की मेहनत करके जो अनाज पैदा करते हैं उसको ये साहूकार लोग समेट कर ले जाते हैं । इस तरह से वे लोग वैसे ही नंगे और भूखे रह जाते हैं ।

मैं यह बात कहूंगा तो मंत्रीजी कहेंगे कि हमने सहकारी समितियां खोली हैं और सहायता और तकावी की व्यवस्था कर दी है । लेकिन चेअरमैन महोदय, यह व्यवस्था पूरे लोगों के लिये २० साल बाद हो सकती है । लेकिन हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह सब को संभाल ले इसलिये शोषण करने वालों को कैद नहीं कर सकते । अब सवाल रहा सहकारी समितियों का । सहकारी समितियों के बारे में यह बताया कि हमारे यहां वह काम कर रही हैं, उनको हम सफल बना रहे हैं । लेकिन सहकारी समितियों के कर्मचारी और सहकारी विभाग इतना लापरवाह है कि १२ महीनों तक तो सहकारी समितियां रजिस्टर नहीं होती हैं । उनको रजिस्टर कराने में और मेम्बर बनाने में उड़ने वाले कागजों पर लोगों को वजन रखना पड़ता है और आने जाने में जो खर्चा करना पड़ता है वह लोगों से उधार लेकर करना पड़ता है । बाद में क्या होता है कि जितनी रकम मिलती है उतनी

(श्री मोगजी भाई)

ही रकम सामने वाले के ब्याज की हो जाती है। चेअरमैन महोदय, ऐसी स्थिति में वह सफल नहीं हो सकती बल्कि खतरनाक है। वह तो उस तरह से है जैसे एक गधी ने १२ बच्चे जने, फिर भी बोझ उसके सर पर ही रहा इसी तरह से गधों के रवैये और लापरवाही से बुरा हाल है। पंचवर्षीय योजनाएं कितनी ही बनाते रहें, यहां की स्थिति वैसी ही रहने वाली है। जहां तक मैं समझता हूं सहकारी समितियों का सवाल जहां तक है, १ महीने में वह रजिस्टर होनी चाहिये लेकिन साल भर तक रजिस्टर नहीं होतीं। लोगों से उधार लेते हैं। एक साल बाद लोगों को अविश्वास हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि कर्जे में डूबने की बात होती है इसलिये लोगों को सहकारी समितियों के प्रति अविश्वास हो जाता है। सहकारी समितियां लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है बल्कि वे लोगों को अपंग बना रही हैं। सरकार के नहीं संभालने के कारण ऐसा हो रहा है।

माननीय चेयरमैन, दूसरी बात ठेकेदारों की रह जाती है। यह कहा जाता है कि ठेकेदार शोषण कर रहे हैं लेकिन ठेकेदार खुद शोषण नहीं करते। उनको सहायता देकर सरकार उनसे शोषण कराती है। हमारे यहां की एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। हमने वन श्रमिक समिति १६५६ में बनाई थी। हमने समिति बनाई। २००), २५०) रुपये कर्जा लेकर बनाई और यह सोचा था कि एक बार बनाने के बाद काम आसान हो जायगा और उसको अच्छी तरह से संभालेंगे। सन् ५८ में सरकार मंजूरी देती है और सन् ६० में ठेका चालू करने की मंजूरी दी जाती है।

माननीय चेअरमैन महोदय, वहां बड़ी मुश्किल हुई। जब बांस वाड़ा के अन्दर केबिनेट की बैठक हुई तो मंत्री महोदय से सारी घटनायें निवेदन की। उस वक्त चीफ कन्ज़र्वेटर और डी० एफ० ओ० दौड़े दौड़े आये और हाथ पकड़ कर कहने लगे, देखो भाई, अभी यह बात मंत्री महोदय के सामने रखने की जरूरत नहीं, हम तुमको ठेका दिला देंगे। मैंने कहा कि दो साल कोई हाथ पकड़ने नहीं आये, मैं कैसे नहीं कहूं। मैंने मंत्री महोदय को सारी घटना कह दी और मंत्री महोदय ने, चीफ कन्ज़र्वेटर साहब से। जंगल काटने की मंजूरी थी। यह मंजूरी जनवरी में मिली थी। जनवरी के बाद मैंने कहा कि समय निकल गया है और समय निकलने के बाद आप ठेका दे रहे हैं, अब जंगल कब कटेगा, कब क्या होगा? उस वक्त कन्जरवेटर साहब ने कहा कि मैं मेरी तरफ से एक महीना दे दूंगा, आप इसे मुझ पर छोड़ें। हमने मान लिया क्योंकि वे मुख्य वन अधिकारी हैं, इतना झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन ३१ मार्च को ठेका स्थगित कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि ठेका बन्द कर दिया जाय और कानून के अनुसार ठेका बन्द कर दिया गया। तब उन्होंने किस मुंह से कहा था कि एक महीना और बढ़ा देंगे और वन मंत्री महोदय ने भी कहा था कि हम दिला देंगे और कानूनन समय दिया जा सकता है लेकिन कानून तो कागजों में रह गया। अगर हम पैसा देने की, रिश्वत देने की कोशिश करते तब तो यह काम हम सात दिन में करा सकते थे। लेकिन मेरी तो नीति यह है कि हमारा चाहे कुछ भी हो जाय, चाहे हम किसी खड्डे में जायं, लेकिन

(श्री मोगजी भाई)

रिश्वत देने की भावना न रखें । तो इस प्रकार की इस डिपार्टमेंट के लोगों की भावना है और इस प्रकार सहकारी समितियां चलाना चाहती है सरकार । अगर ऐसी स्थिति रही तो जितनी पंचवर्षीय योजनायें हैं, वे फेल रहेंगी और हमारी भावनायें कभी पूरी होने वाली नहीं हैं। यह हो सकता है कि हमको मौका मिला है, हम एम० एल० ए० बने, XXXXहम अपने समय में मौज उठा लें; यह बात अलग है, लेकिन हमारी जनता को तरक्की नहीं मिलेगी....

श्री सभापति : आॅर्डर ! आॅर्डर, !! XXXXये शब्द हैं, ये निकाल दिये जायं ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : XXXXशब्द हैं', ये निकाल दिये जायं ।

श्री सभापति : "सरकार की धूम' कह सकते हैं XXXXशब्द नहीं कह सकते ।

श्री मोगजी भाई : मैं निवेदन करूंगा कि एम० एल० एज० को कहने की बात नहीं है । हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं । यहां कहने का मौका आया है, कि लोग किस तरह सरकार का समर्थन करते हैं । चाहे हम कहते कैसा भी हैं लेकिन सरकार को अच्छा बताते हैं। कहने का मौका आया है, तो सभी एम० एल० एज० को छोड़ दीजिये, मैं अपने लिये कहता हूं....

श्री सभापति : आप विषय पर बोलिये ।

XXXXअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री हरिप्रसाद यादव :वन पर बोलिये, फोरेस्ट पर ।

श्री मोगजी भाई : ऐसी स्थिति में हमारे खनिज पदार्थ और माइन्स का सवाल रहा । माननीय चेअरमैन महोदय, वहां पर मजदूरों की रेट्स लिमिटेड नहीं हैं, सरकार की तरफ से लिमिटेड होगी, लेकिन वहां कोई देखने वाले नहीं हैं । अगर उनकी शिकायत की जाती है तो एक गरीब आदमी एक रुपये के लिए, दो रुपये के लिए साल भर लड़े, २५ रुपये खर्च करें, उसके बाद भी वह गरीब लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार की जो सरकार की नीति है, उसमें जब तक सुधार न हो, तब तक उनको कोई लाभ नहीं हो सकता । बारह आने में, आठ आने में, एक रुपये में वहां के मजदूरों को खान वाले तबाह करते हैं । इसके साथ ही उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता । उनकी जमीन जो खान में चली जाती है, उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करें, उस पर कोई निर्णय लें, यह बात तो अलग रही, लेकिन उनके मामलों में जांच तक नहीं होती । ऐसी स्थिति में, माननीय चेअरमैन महोदय, वहां भूमिहीनों की समस्या वह की वह है । आज भूमिहीन लोगों की इतनी बड़ी संख्या है, कि वे जितना काम कर रहे हैं, उसमें से वे अपने परिवार का छः महीने तक भी पेट नहीं भर सकते । माननीय चेअरमैन महोदय, पुराने आंकड़ों को लेकर देखें, जो पहले एक फैमिली थी और उसको जो जमीन दी गई आज तक उसे फेमिली मान कर चलते हैं । आज तक इसका दुबारा निरीक्षण नहीं हुआ है, इस आधार पर कि जिनके पास दस बीघा जमीन थी, वह तीन भागों में बंट गई है, दस

(श्री मोगजी भाई)

बीघा जमीन तीन तीन बीघा के तीन टुकड़ों में बंट गई है। माननीय चेअरमैन महोदय, आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह जमीन तीन भागों में बंट गई है, लेकिन अभी तक वह एक नाम से, मुखिया के नाम से चल रही है और जिनके पास एक बीघा, दो बीघा जमीन है, उनको भूमिहीनों में नहीं मानते हैं। माननीय चेअरमैन महोदय, पहले जो दस बीघा जमीन थी, एक काश्तकार के पास, जो कुटुम्ब का मालिक था, उसकी जमीन आज तीन भागों में बंट गई, तो तीनों भूमिहीन हो गये। उनकी जांच करने का सरकार के पास में कोई तरीका नहीं है। वे पुराने आंकड़ों के आधार पर ही यह कहते हैं कि राजस्थान के अन्दर भूमिहीनों की समस्या हल हो गई है, हमने उनको भूमि दे दी है, जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीनों का नाम निशान नहीं है। माननीय चेअरमैन महोदय, यह दु:ख की बात है। हमारा जो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहा आप पधारें और वहां जाकर मिनिस्टर महोदय समय नष्ट करें और देखें सब काश्तकारों की हालत, तो मैं समझता हूं कि ५० आदमियों, १०० आदमियों के अन्दर से आपको मुश्किल से दो या तीन ऐसे आदमी मिलेंगे, जो अच्छी तरह से पेट भर सकते हैं और पूरे साल भर का खर्चा निकाल सकते हैं। बाकी जितने आदमी हैं वे दिन पर दिन भूमिहीन होते जा रहे हैं। सरकार एक तरफ तो कहती है कि अधिक उत्पादन की जरूरत है, दूसरी तरफ जिनको भूमि का बंटवारा होता है, वे भी भूमिहीन हो जाते हैं। अगर वे दरख्वास्त देते हैं तो उनको जमीन दी नहीं जाती है। पुराने आंकड़े हैं, उनके आधार पर जमीन देने की कोई नीति नहीं है। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जो माही बांध बन रहा है, उसमें २० हजार किसानों की जमीन डूब जायगी। उसकी वजह से पूरे बांसवाड़ा जिले में जमीन की मंजूरी देना बन्द कर दिया। उनको यह कह दिया जाता है कि क्या हुआ, बाद में जिन काश्तकारों की जमीन आ जायगी, उनको जमीन दें और दूसरों को न दें। जब बांध पूरा बन जायगा, उसके बाद लोगों को जमीन दी जायगी। अब वे लोग, जिनके पास जमीन नहीं है, वे चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? वे सरकारी कानून को भंग न करें तो क्या करें? अगर ये बातें यहां कहें तो फिर कहेंगे कि सरकार की बुराई करते हैं। मैं सही हालत, सही स्थिति बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि बुराई करने से तो दिन निकलना मुश्किल है और हम जनता में खड़े भी नहीं रह सकते। आज सही स्थिति इस तरह की है कि आज छोटा बच्चा तक समझ लेता है कि जहां तक जमीन की मंजूरी देने का सवाल है, जिनके पास दो बीघा, चार बीघा जमीन है, वे और जमीन की मंजूरी मांगते हैं तो उनको एक-दो बीघा जमीन की मंजूरी नहीं मिलने वाली है और जिनके पास ज्यादा जमीन पड़ी है, उनसे जमीन लेकर ज्यादा लोगों को बसाने जायेंगे, तो २१ हजार आदमियों को बसा सकते हैं....

श्री पी० के० चौधरी : Time is up.

श्री सभापति : आप अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री मोगजी भाई : वहां की स्थिति सरकार जानती नहीं है और अगर जानती है तो जान-बूझ कर भूल जाने वाली है। मैं कहता

(श्री मोगजी भाई)

हूं कि वहां पर जो बांध बनाये जा रहे हैं, वे जरूर बनाने चाहिये। लेकिन जो सरकार का रवैया है, वह ठीक नहीं है। माननीय चेअरमैन महोदय, वहां पर जो काश्तकार हैं उनके पास दस बीघा, पन्द्रह बीघा जमीन रखेगी नहीं और आधा बीघा, एक बीघा पर उनको बसा देंगे तो फिर कैसे ज्यादा अन्न पैदा कर देंगे? लेकिन यह मालूम नहीं पड़ता है कि सरकार ऐसी कौनसी नीति अपना रही है कि जब तक वह बांध बनेगा नहीं, किसानों के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं होगी, उनको जमीन की मंजुरी नहीं देंगे। यह देखने लायक बात है इसी तरह....

श्री सभापति : समय समाप्त हो गया है।

श्री मोगजी भाई : कल के लिए टाइम देंगे।

श्री सभापति : आप भाषण समाप्त कर दीजिये, काफी बोल चुके हैं।

श्री मोगजी भाई : माननीय चेअरमैन महोदय, मैं वह निवेदन कर रहा था कि मेरे कहने से सरकार का पूरा विभाग डरने वाला नहीं है और न कोई काम को करने वाला है। मैं यह कहूंगा कि मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे कहने को विरोधी पक्ष की बात मान कर नहीं टालेंगे और इसको सोच कर, सतर्क होकर पूरा काम इस योजना को सफल बनाने में करेंगे तो यह योजना सफल रहेगी; वरना यह तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहेगी। इसलिये मैं मानता हूं कि सरकार अपनी भूलों को भूल जावे और योजना को सफल बनाने की कोशिश करे।

श्री सभापति : अब सदन की कार्यवाही दिनांक ८ सितम्बर, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर १ मिनट पर दिनांक ८ सितम्बर, १९६० के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ७ सितम्बर, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२४४५		

आयुर्वेद सलाहकार मण्डल।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा बजट में स्वीकृत रकम से अधिक की दवाइयों की खरीद।

वन विभाग, जिला कार्यालय, जयपुर के भूतपूर्व अकाउन्टेन्ट का ग्रॉस फार्म बिल्डिंग खातीपुरा में निवास।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ द्वारा छापर की फर्म जे. एन्ड ब्रादर्स को ड्रग्स एक्ट के तहत दिये गये लाइसेन्स।

ग्राम पंचायत जोगीवाला, तहसील भादरा के भूतपूर्व सरपंच, श्री रामजीलाल द्वारा आबादी भूमि के अवैध विक्रय विलेख जारी किया जाना।

अजमेर जिले के रूपनगढ़ कस्बे व उसके आसपास के गांवों में जल-कष्ट का निवारण।

सरपंच, ग्राम पंचायत अलीगढ, तहसील उनियारा द्वारा अलीगढ़ मिडिल स्कूल के निर्माण हेतु पंचायत कोष से प्रदत्त धनराशि।

सारूडा (नोखा) गांव के सरपंच द्वारा गांव के कुएं में नल लगवाने हेतु एकत्रित किये गये द्रव्य का हिसाब-किताब।

ओसियां तहसील के ग्राम मथानिया के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के डाक्टर के विरुद्ध की गई शिकायतों पर कार्यवाही।

जिला जालोर के हाडेचा ग्राम में बोरिंग कार्य की शुरूआत।

जयपुर विकास खंड के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्र।

पंचायत समिति के अधीनस्थ प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा की रात्रि पाठशालाएं चलाने का अलाउन्स।

Page No.114

स्कम्भ

राजस्थान निर्माण के उपरान्त बने नये अस्पताल एवं उनमें लगी धनराशि।

रूपवास तहसील के गांवों में सिंचाई हेतु बांध या नहर न होते हुए भी सिंचाई करों की वसूली।

उदयपुर जिले के शैडो ब्लॉक्स में आयोजित कृषि प्रशिक्षण शिविरों पर हुआ खर्चा।

मत्स्य क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु कांच की वस्तुओं की खरीद में गबन।

सिरोही के मर्दाने अस्पाल में चौड़ी चारपाई वाले जनरल वार्ड का निर्माण।

रूपवास तथा बयाना तहसीलों में सिंचाई के बांधों की मरम्मत।

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर आदि शहरों में मई व जून के महीनों में होने वाले जल कष्ट का निवारण।

बांसवाड़ा अस्पताल और टी. बी. अस्पताल में बगैर टेन्डर आमन्त्रित किये कपड़े की खरीद एवं धुलाई।

स्कम्भ

ग्राम विकास निधि का निर्माण।

जिला जालोर के कृषि अधिकारी के कार्यालय में मोटर किराये के पड़े हुये पेंन्डिंग बिल्स का भुगतान।

यज्ञनारायण अस्पताल किशनगढ़ के कर्मचारियों का फिक्सेशन।

पशुपालन विभाग द्वारा खरीदे गये औजार एवं सामग्री।

बडोदिया भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर।

गोशाला व्यवस्था सिरोही द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में टेलीफोन्स की वृद्धि।

राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड।

सी. ए. एस. प्रथम श्रेणी के डाक्टरों का चयन एवं अस्पतालों की श्रेणी विभाजन।

स्थगन—प्रस्ताव २५०६

राजस्थान नहर सम्बन्धी श्री भैरोंसिंह (१४) तथा कुछ डाकुओं

द्वारा आत्म–समर्पण के सम्बन्ध में श्री होतीलाल के स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

कार्य–सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २५११

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के सत्तरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

अविलम्बनीय लोक–महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना २५११

श्री श्रीमानसिंह, सदस्य, विधान सभा, ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत भरतपुर जिले में बाढ़ से हुई क्षति एवं तत्सम्बन्धी राहत कार्यों की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया। राजस्व मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार २५१७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सत्तरहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार २५१७

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा दिनांक ६ सितम्बर, १९६० को प्रस्तुत किए गए निम्नांकित प्रस्ताव पर आज भी विचार किया गया :—

"राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा से सम्बन्धित विभिन्न मदों के ज्ञापन, जिनकी प्रति दिनांक २ सितम्बर, १९६० को सदन की मेज पर रखी गई थी, को विचारार्थ लिया जाय।"

बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री पी. के. चौधरी
(२) श्री चन्दनमल वैद
(३) श्री मुरलीधर व्यास
(४) श्री श्रीमानसिंह
(५) श्री दयाकृष्ण विजय
(६) श्री रामचन्द्र (१२६)

Page No.116

(७) श्री मोगजीभाई

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री ने अपने विभागों से सम्बन्धित मामलों का स्पष्टीकरण किया।

सदन की बैठक ५ बजकर १ मिनट पर गुरुवार दिनांक ८ सितम्बर, १६६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

कार्य-विवरण दिनांक ८ सितम्बर, १६६० की कार्य-सूची

प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा पर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८० का उत्तर देखिये)

LIST OF PERSONS, OTHER THAN SRI SANWATMA 1, LIVING AT THE GRASS FARM NURSERY COMPOUND.

S. No.	Name of person	Designation	Portion of the building being occupied.	Date from which occupying.	Charges being recovered		REMARKS.
					House rent	Electricity	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sri Durga Singh	Head Guard In-charge, Nursery.	Incharge Nursery's quaters.	For the last 8 months.	Entitled to rent free accommoda-tion.	Rs. 2/- p. m.	
2.	Sri Lal Singh	Mechanic & Turbine Pump driver.	One small room.	For the last 18 months.	Not charged	Rs. 1/- p. m.	As the mechanic has to stay at the nursery late in the evening in connetion with the working of the tube well no rent is charged from him at present.

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Sri Gordhan Lal	Forest Guard Rest House	One small room	For the last 12 months.	Entitled to rent free accommodation.	Rs. 1/- p. m.	
4.	Sri Sundar Ram and Mohra Ram	Forest Guards	One tin shed small room	for the last many years.	-do-	Rs. 1/- p. m.	
5.	15 Nursery Labourers.	Casual Labourers.	5 tin shed small rooms	Being Casual labour date of occupation not known.	Not charged.	—	
6.	Sri Raghunath Singh	Peon, CCFS' Office	One small room.	1956.	Not charged	Rs. 2/- p. m.	As the peons have to keep a watch on the CCFS' office.
7.	Sri Kalyan Singh	-do-	-do-	-do-	-do-	Rs. 1/- p. m.	Stores kept in the building no rent is being charged at present.

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Sri Badri Lal	Driver C.C.Fs' office.	One small room	1956	Not charged	Rs. 1/- p. m.	As the driver has to keep a watch on the machinery and vehicles kept in the Nursery compound no rent is being charged.

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८१ का उत्तर देखिये)

FOR FIRM M/S J. AND BROTHERS

Shri Ram Singh S/o Shri Surajmalji Mundhra

date of issue of Licence. 16-8-59

For Firm M/S Mundra Brothers.

Shri Ram Singh S/o Shri Surajmalji Mundhra.

Date of issue of Licence. 25-11-59.

Copy of letter No. Nil dated 17-8-60 from M/S Moondhra Bros. Chhapar, to the Distt. Medical & Health officer, Ratangarh.

Sub:—Application for Drug Licence.

Ref:—Your office No. 7626/ Drug/60 dated 15-8-60 and 7627/Drug/60 dated 23-8-60

I want to inform you that the firm M/S J. & Brothers is not more in existence and the name of the firm J. & Brothers has been Changed to Messrs Mundhra Brothers. The name of the father of all the Brothers is Shri Surajmalji Mundhra. We three Brothers, Jug Raj, Ram Singh and Vijay Singh and the proprietors of the firms Messrs Mundhra Brothers Chhapar for which the application for licence of Drugs has been sent to you. All the three brothers named above have got the right to sign for Messrs Mundhra Brothers Chhapar, Kindly note and oblige.

After an enquiry it was found that M/S J. and Brothers is no more in existence at Chhapar. The name of M/S J.& Brothers has been changed to Messrs Mundara Brothers.

Sd/—S. R. Vyas,
C. A. S. Class II.
M. O. Chhapar.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८२ का उत्तर देखिए)

Copy of the Notification No. F. 4 (1) LSG/A/59 dated the 2nd February, 1959 from the Secretary to the Government Local Self Government 'A' Department.

No. F. 4 (1) LSG/A/ 59:—In exercise of the power conferred by Section 83 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 (Rajasthan Act of 1953) and all other powers enabling him in this behalf, and in partial modification of this Department Notification No. F. 1 (d) (36) LSG/54, dated the 18th. Feb., 1955, the Governor is pleased to withdraw, with immediate effect, the power to lease or sell Government owned lands in the abadi areas within their circles and limits from the Panchayats situated within the Bhakra project Area. The sale proceeds of such lands, after deducting the development charges, will be handed over to the Panchayat concerned by the colonization Department.

DIRECTORATE OF PANCHAYATS

RAJASTHAN

No. Jaipur, March, 1959

Copy forwarded to the:—

Director of Panchayats,
Rajasthan.

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE TANKS

Name of tank	Teshil
1. Doondi Bund	Bayana
2. Jaisoara Bund	—do—
3. Nauharda bund	—do—
4. Baseri bund	Roopbas
5. Gahlow bund	—do—
6. Sena bund	—do—
7. Kandoli bund	—do—
8. Mahalpur Kachi bund	—do—
9. Mertha bund	—do—
10. Sirondh bund	—do—
11. Samant Garh bund	—do—
12. Bachcamdi bund	—do—

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ का उत्तर देखिये)

LIST

1.	Doctors.	Doctors Coat.	3 Sets in a year.
2.	Compunder Gr. 1.	Bush Shirt Half sleeves with four peokets. Full Pant & Full Cap.	4 Sets in a year.
3.	Compounder Gr. II.	—do—	4 Sets in a year.
4.	Compounder Gr. III	—do—	3 Sets in a year.
5.	ward Boys.	(a) Buttoned up Bushshirt Full Pants & Cap—	2 Sets in a year.
		(b) Buttoned up Shortcoat (Woollen)	1 set two years.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०१ का उत्तर देखिए)

सूची

१. श्री भगवतीलाल भूतपूर्व कनिष्ठ लेखक ।

२. ,, चिरंजीलाल कम्पाउन्डर ।

३. ,, मानसिंह कम्पाउन्डर ।

४. ,, लादूलाल गुप्त ।

५. श्रीमती नारायण पोदन ।

६. श्री रामचन्द्र बलिब्राय ।

७. ,, फकीरा हरिजन ।

८. श्रीमती छोटीबाई हरिजन ।

९. श्री बालमचन्द बलिब्राय ।

१०. कोयला बाई ।

११. श्रीमती बावली बाई नई बाई ।

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क) तारांकित प्रश्न संख्या ७ ए० सी एम० बड़ोदिया भवन निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों की सूची

क्रम संख्या	नाम सदस्य	निवास स्थान
१	२	३
(१)	श्री बालाबख्श शर्मा	बड़ोदिया
(२)	,, नाथूलाल शर्मा	,,
(३)	,, रामदयाल शर्मा	,,
(४)	,, गोपीनाथ शर्मा	,,
(५)	श्रीमती नर्मदा देवी	,,
(६)	श्री ग्यारसीलाल शर्मा	,,
(७)	,, नाथूराम	,,
(८)	,, कन्हैयालाल	,,
(९)	,, चतरसिंह	,,
(१०)	,, प्यारसिंह	,,
(११)	श्रीमती सोनदेवी	,,
(१२)	श्री पूरनसिंह	,,
(१३)	,, करवेल सिंह	,,
(१४)	,, कमला प्रसाद	,,
(१५)	,, रुडमल शर्मा	,,
(१६)	,, ग्यारसीलाल	,,

१	२	३
(१७)	श्री प्रकाशचन्द जोशी	बड़ौदिया
(१८)	,, गुरवचनसिंह	,,
(१९)	,, मेवासिंह	,,
(२०)	,, मोकमसिंह	,,
(२१)	,, जुमरदी खां	,,
(२२)	,, घासीराम	,,
(२३)	,, बाबूलाल	,,
(२४)	,, बाबूसिंह	,,
(२५)	,, बहादुरसिंह	,,
(२६)	,, मुंशी सिंह	,,
(२७)	,, मंगल सिंह	,,
(२८)	,, दौलत सिंह	,,
(२९)	,, भंवरसिंह	,,
(३०)	,, रामगोपाल	,,
(३१)	,, जुम्मा खां	,,
(३२)	,, डालूराम	,,
(३३)	,, उजागर सिंह	,,
(३४)	,, सेवासिंह	,,
(३५)	,, मुलक सिंह	,,

१	२	३
(३६)	श्री बिरधीचन्द	बड़ौदिया
(३७)	,, दामोदर प्रसाद	,,
(३८)	श्रीमती हरनाम कौर	,,
(३६)	श्री संतोषसिंह	,,
(४०)	,, वजीर खां	,,

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ७ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२४५१	शीर्ष	—	(श्री सम्पतराम)
२४५३	२३	ब्रदर्स को	ब्रॉदर्स को
२४६१	अन्तिम	मत्री यह	मंत्री यह
२४६५	शीर्ष	(श्री बद्रीप्रसाद	(श्री बद्रीप्रसाद
२४६६	१९	की गई है	की गई हैं
२४७७-७८	शीर्षक	६ सितम्बर	७ सितम्बर
२४८४	१६	२९५	३९५
२४८५	शीर्ष	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
२४९३	२	applinaces	appliances
,,	१३	एफलाइन्सेज	एप्लाएन्सेज़
२४९७	अन्तिम से ५	कर रहा हूं	कर रही हूं
२४९८	२७	Contrractor	Contractor
२५०७	२६	27-4-54 ? when	27-4-54 when
,,	२७	get it, and	get it and
२५०९	१५	किसी तारीख	किस तारीख
२५११	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव	कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन
,,	१०	दिलाने, सम्बन्धी	दिलाने सम्बन्धी
२५१३ व २५१५	शीर्षक	भरतपुर में बांढ़	भरतपुर में बाढ़
२५१५	१५	ज्याहा होना	ज्यादा होना
२५१६	अन्तिम से ४	Bhaatpur Distric	Bharaptur District
,,	अन्तिम	नुक्सन हुआ	नुक्सान हुआ
२५१७	१७	सलाहकारी समिति	सलाहकार समिति
,,	२१	योजना के रूप-रेखा	योजना की रूप-रेखा
२५१८	अन्तिम से ५	श्री अयध्द	श्री अध्यक्ष
२५१९	१०	आफार पर	आधार पर
२५२१	२	सयस्यों ने	सदस्यों ने
,,	२२	रुपये में से	रुपयों में से

१	२	३	४
२६१२	अन्तिम से ४	ऊसको आज	उसको आज
२५२२	शीर्षक	रूपरे–खा	रूप–रेखा
२५२३	१३	एन्टर प्राइजेज सेन्द्रल	एन्टरप्राइज़ेज़ में सेन्ट्रल
२५२५	शीर्षक	वोजना की	योजना की
२५२६	३	एडवान्सेड़ के	एडवान्सेज़ के
,,	१०	की रेल्वे	की रेल्वे।
२५२८	१६	में। हैं	में हैं।
,,	१६	खेतरी क्या	खेतड़ी क्या
२५३२	२३	पन्द्र–हबीस	पन्द्रह–बीस
,,	२६	agriculture	agriculture पर
२५३३	१७	टन। ५६	टन,५६
२५३४	४	प्रोडपशन है	प्रोडक्शन है
२५४१	२४	कीं बात	की बात
२५५०	अन्तिम	को पच	को पांच
२५६०	,,	की सारी	कि सारी
२५७५	,, से ७	ज्याकी यों	ज्यों की त्यों
२५८२	११	छोड़छोड़ कर	छोड़ छाड़ कर
,,	१८	मिलता हैं	मिलता है
२५८६	२१	टेम्पोरीं काम	टेम्पोरेरी काम
२५६१	२५	Leader dwett	Leader dwelt
२५६३	अन्तिम से ६	Planning on	Planning in
२५६४	३	Seond plan	Second plan
,,	२६	Caloulations but it	Calculations but if
२५६५	२०	pressent	present
२५६७	५	Lleader of	Leader of
,,	१७	wiil be	will be
,,	२१	bo any	be any
,,	२६	Secod plan	Second plan
२५६८	६	the Cen tre	the Centre
,,	७	our demad	Our demand
२६००	अन्तिम से ६	डेफिशियेट या	डेफिशियेन्ट था
२६०६	२	सपोटिंग नहीं	सपोर्टिंग नहीं
२६१२	११	श्री नाराम	श्री नाथूराम

१	२	३	४
२६१३	१२	पम्पिंग सेट	पम्पिग सैट
,,	अन्तिम से ६	सदस्यौं के	सदस्यों के
,,	अन्तिम से २	(वल्लभनगर–स०)	(बल्लभनगर–सु०)
२६१७	१८	नागार जिले	नागौर जिले
२६१९	७	का हागा	का होगा
२६२६	१	को लकड़ा	को लकड़ी
२६२७	७	(श्री आब्दिअली	(श्री आबिदअली
२६२९	शीर्षक	तृतीय पंचवषीय	तृतीय पंचवर्षीय
२६३१, २६३३ व २६३५	शीर्षक	(श्री दयाकृप्ण	(श्री दयाकृष्ण
२६३८	शीर्षक	रू–परेखा	रूप-रेखा
,,	१४	तनख्वार	तनख्वाह
२६४४	७	के सरपास	को सरपास
२६४५	शीर्षक	वोजना की	योजना की
२६४६	२०	आर्थत्	अर्थात्
२६५२	१३	(वल्भनगर	(बल्लभनगर
२६५४	५	उनको धन्यबाद	उनको धन्यवाद
,,	२९	(फुलेर)	(फुलेरा)
२६७२	प्रथम	निधिका	ग्राम विकास निधि का
२६८५	सीरियल नं. ६	नारायण पोदन	नारायण पादन